

D.P. VIPRA LAW COLLEGE BILASPUR (C.G.)

Approved From BCI,
Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya Bilaspur (C.G.)



D.P. Vipra Law College Bilaspur

Ashok Nagar, Seepat Road, Sarkanda, Bilaspur (C.G.)

D.P. VIPRA LAW COLLEGE BILASPUR (C.G.)

Approved From BCI,
Affiliated to atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya Bilaspur (C.G.)



5.1.4

The Institution has a transparent mechanism for timely redressal of student grievances including sexual harassment and ragging cases

- 1. Implementation of guidelines of statutory/ regulatory bodies**
- 2. Organisation wide awareness and undertakings on policies with zero tolerance**
- 3. Mechanisms for submission of online/offline students' grievances**
- 4. Timely redressal of the grievances through appropriate committees**

D.P. Vipra Law College Bilaspur
Ashok Nagar, Seepat Road, Sarkanda, Bilaspur (C.G.)



Office Of The Principal D.P. Vipra Law College Bilaspur




Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur(C.G.)

<https://dpvipralawcollege.ac.in> –Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

Summary - sheet

Criteria	5. Student Support and Progression
Key Indicator	5.1: Student Support
Metric	<p>5.1.4. The Institution has a transparent mechanism for timely redressal of student grievances including sexual harassment and ragging cases:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementation of guidelines of statutory/regulatory bodies 2. Organisation wide awareness and undertakings on policies with zero tolerance 3. Mechanisms for submission of online/offline students' grievances 4. Timely redressal of the grievances through appropriate committees

Description	Relevant link
1) Constitution & Policies of Anti-Ragging, Women Grievance Cell (Anti-Sexual Harassment), Grievance Redressal Committee (Student Redressal Committee). (Appendix-I)	https://dpvipralawcollege.ac.in/wp-content/uploads/2024/07/5.1.4.pdf
2) Office order, minutes of meeting, grievances received & Action Taken. (Appendix-II)	
3) Web link of various committees is available on institutional website. (Appendix-III)	
4) Annual report of the committee monitoring the activities and number of grievances is attached. (Appendix-IV)	


Co-Ordinator
I.Q.A.C.




PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

D.P. VIPRA LAW COLLEGE BILASPUR (C.G.)

Approved From BCI,
Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya Bilaspur (C.G.)

Appendix - I

D.P. Vipra Law College Bilaspur

Ashok Nagar, Seepat Road, Sarkanda, Bilaspur (C.G.)

NO RAGGING

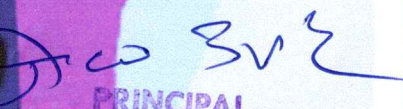
GUIDANCE

FOR

Anti Ragging

COMMITTEE




PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)



ज्ञान-विज्ञान विपुलतये

प्रो. रजनीश जैन
सचिव

Prof. Rajnish Jain
Secretary



सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)

बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Ph : 011-23236288/23239337

Fax : 011-2323 8858

E-mail : secy.ugc@nic.in

अ०श०मि०स० 3-2/2021 (ए.आर.सी)

27 OCT 2021

अक्तूबर, 2021

SPEED POST

विषय: विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन रैगिंग रोधी शपथ-पत्र दाखिल करने की संशोधित प्रक्रिया।

प्रिय महोदया/महोदय,

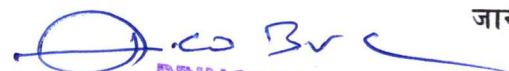
जैसा कि आप जानते हैं, सिविल अपील संख्या 887/2009 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 8.5.2009 के निर्णय के अनुसरण में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग को रोकने के लिए विनियम, 2009" में अधिसूचित किया है जिसके दूसरे संशोधन के अनुपालन में, प्रत्येक विद्यार्थी और उनके माता-पिता/अभिभावक को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में www.antiragging.in और www.amanmovement.org में से किसी एक वेबसाइट पर ऑनलाइन वचन पत्र जमा करवाना अनिवार्य है।

इस प्रक्रिया को सहज करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन रैगिंग रोधी शपथ-पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया में संशोधन किया है।

संशोधित प्रक्रिया निम्नवत हैं:

- चरण 1: विद्यार्थी अपना विवरण पूर्ववत् (www.antiragging.in और www.amanmovement.org) वेबसाइट पर जमा करेंगे और पढ़कर इसकी पुष्टि करेंगे कि वे और उनके माता-पिता/अभिभावकों ने रैगिंग को रोकने के लिए विनियम को अच्छी तरह पढ़ और समझ लिया है, वे इस बात की भी पुष्टि करेंगे कि वे किसी भी रूप में रैगिंग में शामिल नहीं होंगे। (चरण 1 पहले जैसा ही है)।
- चरण 2: विद्यार्थी को उसकी पंजीकरण संख्या और एक वेब लिंक के लिए एक ई-मेल प्राप्त होगा। विद्यार्थी अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में नोडल अधिकारी के ई-मेल पर लिंक अग्रेषित करेगा। (कृपया ध्यान दें कि विद्यार्थी को पीडीएफ शपथ-पत्र प्राप्त नहीं होगा और उसे इसे प्रिंट करने और हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है जैसा कि पहले हुआ करता था)।
- चरण 3: विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के नोडल अधिकारी उन विद्यार्थियों की सूची प्राप्त करने के लिए जिन्होंने अपने महाविद्यालय में रैगिंग रोधी शपथ पत्र/वचन पत्र जमा किए हैं, अपने महाविद्यालय के किसी भी विद्यार्थी से प्राप्त किसी भी अग्रेषित ईमेल के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, सूची हर 24 घंटे में अद्यतन की जाएगी।

जारी.../-


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

CONTINUATION SHEET

-02-

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से अनुरोध है कि वे दिए गए प्रारूप के अनुसार अपने विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के प्रवेश पत्र में एक अनिवार्य कॉलम डालें:

रैगिंग रोधी शपथ की संदर्भ संख्या:	
-----------------------------------	--

आपसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के रैगिंग रोधी नोडल अधिकारी का ईमेल पता और संपर्क हेतु टेलीफोन नंबर अपनी वेबसाइट और परिसर क्षेत्रों जैसे प्रवेश केंद्र, विभागों, पुस्तकालय, कैंटीन, छात्रावास, और सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित करें ताकि विद्यार्थियों में ऑनलाइन रैगिंग रोधी शपथ-पत्र दाखिल करने की संशोधित प्रक्रिया के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके।

आपसे यह भी निवेदन किया जाता है कि प्रवेश-पुस्तिका/विवरणिका आदि की प्रिन्ट/हार्ड कॉपी के बजाय उनकी सॉफ्ट कॉपी तथा साथ ही रैगिंगसम्बन्धी मार्गदर्शन हेतु ई-लिफ्लेट भी प्रकाशित की जाए।

सादर,

भवदीय,



(रजनीश जैन)

सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति

सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य



PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)



ज्ञान-विमान विमुक्तये

प्रो. रजनीश जैन
सचिव

Prof. Rajnish Jain
Secretary



सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)

बहादुरशाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Ph.: 011-23236288/23239337

Fax : 011-2323 8858

E-mail : secy.ugc@nic.in

अर्ध शासकीय पत्र संख्या 1-15/2009 (एआरसी) भाग-III

30 DEC 2021 23 दिसंबर, 2021

आदरणीय महोदय/महोदया,

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या 887/2009 दिनांक 08.05.2009 के निर्णय के अनुसरण में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए विनियम, 2009" अधिसूचित किया है, जो देश के सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों पर अनिवार्य रूप से लागू है। ये विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध हैं।

रैगिंग मुक्त परिसर सुनिश्चित करने के लिए कुछ सिफारिशें और कार्रवाई योग्य बिन्दु, जिन्हें आपके विश्वविद्यालय तथा संबद्ध/सहयुक्त सभी संस्थानों में लागू करने की आवश्यकता है, निम्नवत् हैं:-

क) बुनियादी उपाय:-

1. रैगिंग रोधी समिति तथा रैगिंग रोधी दस्ते का गठन एवं रैगिंग रोधी प्रकोष्ठ की स्थापना कर विभिन्न मीडिया के माध्यमों से इन उपायों का पर्याप्त प्रचार किया जाए।
2. संस्था की विवरणिका एवं सूचना पुरस्तिकाओं में रैगिंग रोधी चेतावनी का उल्लेख सुनिश्चित किया जाए।
3. विद्यार्थियों के सूचनार्थ और मार्गदर्शन के लिए प्रकाशित नामांकन-विवरणिकाओं, सूचना-पुरस्तिकाओं, पत्रकों इत्यादि के कागजी प्रति के बजाय उनकी सॉफ्ट प्रतियाँ प्रकाशित की जाए तथा उनमें रैगिंग रोधी निर्देशों के साथ-साथ इस संबंध में समुचित मार्गदर्शन को भी समाहित किए जाएँ।
4. रैगिंग रोधी समिति तथा इसके नोडल अधिकारियों के पूरे पते और उनके संपर्क विवरण के साथ संस्थानों की वेबसाइटों को अद्यतन किया जाए।
5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों और इसके दूसरे संशोधन के अनुपालन में, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में प्रत्येक विद्यार्थी और उनके माता-पिता द्वारा एक ऑनलाइन संकल्प पत्र जमा कराया जाए।
6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 29 जून, 2016 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों में तीसरा संशोधन अधिसूचित किया है, जिसमें निम्नलिखित को शामिल करके रैगिंग की परिभाषा का विस्तार किया गया है:-
"3. (i) रंग, प्रजाति, धर्म, जाति, नृजातीयता, लिंग (ट्रांसजेंडर सहित), सेक्सुअल ओरिएंटेशन, भेष, राष्ट्रीयता, क्षेत्रीय मूल, भाषाई पहचान, जन्म स्थान, निवास स्थान या आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी छात्र (नए या अन्यथा) पर लक्षित या शारीरिक या मानसिक शोषण (दादागिरी और बहिष्करण सहित) का कोई भी कृत्य।"
7. महत्वपूर्ण स्थानों पर सी.सी.टी.वी कैमरे लगाना।

ख) परामर्श तथा निगरानी के उपाय:-

1. विद्यार्थियों के साथ नियमित बातचीत और परामर्श से रैगिंग के शुरुआती लक्षणों का पता लगाया जा सकता है और परेशानी करने वाले कारकों की पहचान की जा सकती है।
2. छात्रावारों, विद्यार्थियों के आवास, कैंटीन, विश्राम-सह-मनोरंजन कक्षों, शौचालयों, बस-स्टैंड इत्यादि का औचक निरीक्षण और कोई भी अन्य उपाय जो रैगिंग को रोकने/ लगाम लगाने और अनुचित व्यवहार/घटना को रोकने में प्रभावी हैं, किए जाएँ।

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

ग) रैगिंग मुक्त परिसर के विचार का रचनात्मक प्रसार:-

1. रैगिंग रोधी कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और इस विचार को फैलाने के लिए कोई भी अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों को किया जाना चाहिए।
2. व्यक्तियों की गोपनीयता को प्रभावित किए बिना सुरक्षा एवं संरक्षा ऐप्स को रचनात्मक रूप से प्रयोग में लाया जाए।

घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शुरू किए गए अन्य उपायों का उपयोग करना:-

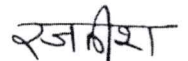
1. रैगिंग से संबंधित घटनाओं के कारण संकट में फंसे विद्यार्थी राष्ट्रीय रैगिंग रोधी हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5522 (24x7 टोल फ्री) पर कॉल कर सकते हैं या रैगिंग रोधी वेबसाइट helpline@antiragging.in पर ई-मेल कर सकते हैं।
2. रैगिंग के संबंध में किसी भी अन्य जानकारी के लिए, कृपया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट www.uqc.ac.in एवं www.antiragging.in पर जाएं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निगरानी एजेंसी अमन सत्य काचरू ट्रस्ट से मोबाइल नंबर 09871170303, 09818400116 पर (केवल आपात स्थिति में) संपर्क करें।
3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न माध्यमों से रैगिंग रोधी मीडिया अभियान भी चलाता है और आयोग ने रैगिंग रोधी क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित संसाधन विकसित किए हैं जो आयोग की वेबसाइट www.uqc.ac.in पर उपलब्ध हैं।
 - (i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने माता-पिता, पीड़ित और रैगिंग के दोषियों के परिप्रेक्ष्य से 30 सेकंड के अलग-अलग 05 टी.वी.सी विकसित किया है।
 - (ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रचार-प्रसार के लिए पोस्टर बनाकर विश्वविद्यालयों/विनियामक प्राधिकरणों/परिषदों/आईआईटी/एनआईटी/अन्य शैक्षणिक संस्थानों के बीच वितरित किया है।
 - (iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रैगिंग के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए विद्यार्थियों/शिक्षकों/आम जनता के लिए 02 रैगिंग रोधी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों का उल्लंघन या इन विनियमों के अनुसार रैगिंग को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने में संस्थान की विफलता या रैगिंग की घटनाओं के दोषियों को उपयुक्त रूप से दण्डित करने में विफलता की स्थिति में उनके विरुद्ध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अंतर्गत उचित दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।


आपसे अनुरोध है कि इस कार्यालय के पत्र सं. 3-2/2021 (एआरसी) दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 के अनुसार विद्यार्थियों को ऑनलाइन रैगिंग रोधी शपथपत्र दायर करने के लिए संशोधित प्रक्रिया को लागू करें और अपनी वेबसाइट और परिसर के मत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे प्रवेश केंद्र, विभागों, पुस्तकालय, कैटीन, छात्रावास में अपने विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों के रैगिंग रोधी के नोडल अधिकारी का ईमेल पता और संपर्क नंबर प्रदर्शित करें। विद्यार्थियों को ऑनलाइन रैगिंग रोधी शपथपत्र दाखिल करने के लिए संशोधित प्रक्रिया के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, और आपके विश्वविद्यालय से संबद्ध/सहयुक्त सभी महाविद्यालयों को इसका पालन करने के लिए निर्देश देने की कृपा करें।

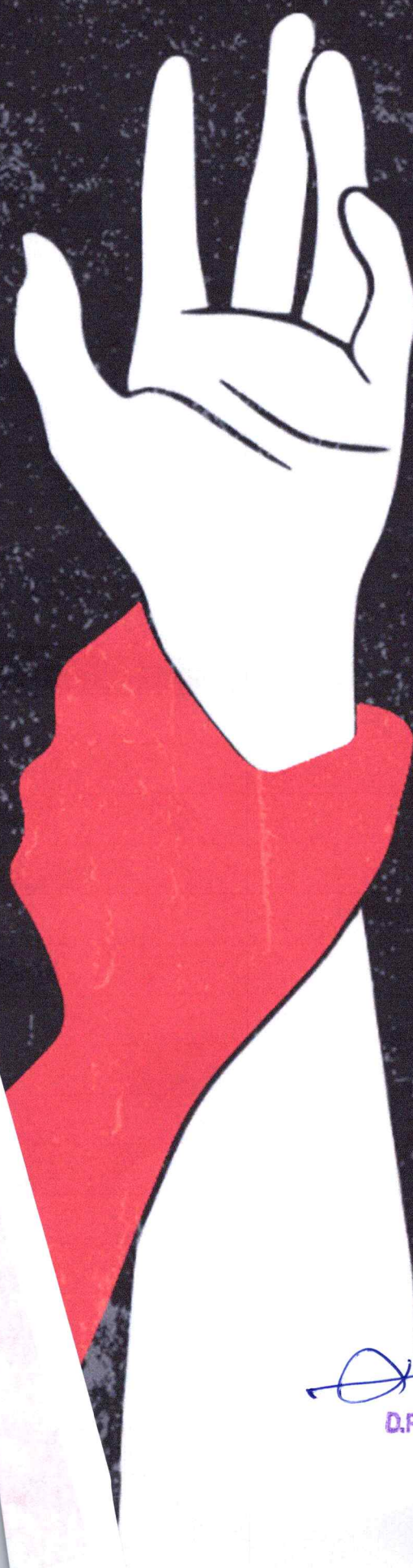
सादर,

भवदीय,


(रजनीश जैन)


सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति।


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)



 **STOP**

**GUIDANCE
FOR
ANTI
SEXUAL
HARASSMENT
COMMITTEE**


PRINCIPAL
D.P. MITRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)



1.1/PRL-DIR/ICC/2021

जून June 29, 2021

कार्यालय आदेश OFFICE ORDER -20/2021

विषय: पी.आर.एल. की आइ.सी.सी. का पुनर्गठन। Sub: Reconstitution of ICC of PRL

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक देखने के लिए पी.आर.एल. की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का पुनर्गठन किया गया है।

The Internal Complaints Committee (ICC) of PRL is reconstituted to look into the complaints of sexual harassment of women at workplace with immediate effect and until further orders.

- | | |
|--|-----------------|
| 1. डॉ. (सुश्री) शीतल एच. पटेल, चिकित्सा अधिकारी-एस.एफ | अध्यक्ष |
| Dr. (Ms.) Shital H. Patel, Medical Officer – SF | Chair |
| 2. डॉ. (सुश्री) श्रुबावती गोस्वामी, वरिष्ठ प्रोफेसर, सैद्धांतिक भौतिकी | सदस्य |
| Dr. (Ms.) Srubabati Goswami, Senior Professor, THEPH | Member |
| 3. डॉ. (सुश्री) नंदिता श्रीवास्तवा, वरिष्ठ प्रोफेसर, उदयपुर सौर वेधशाला | सदस्य |
| Dr. (Ms.) Nandita Srivastava, Senior Professor, USO | Member |
| 4. डॉ. रवि भूषण, वैज्ञानिक- प्रोफेसर, भूविज्ञान प्रभाग, | सदस्य |
| Dr. Ravi Bhushan, Scientist – Professor, GSDN | Member |
| 5. डॉ. सोम कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, अंतरिक्ष एवं वायुमंडलीय विज्ञान प्रभाग | सदस्य |
| Dr. Som Kumar Sharma, Associate Professor, SPASC | Member |
| 6. डॉ. (सुश्री) मेघा उपेंद्र भट्ट, रीडर, ग्रहीय विज्ञान प्रभाग | सदस्य |
| Dr. (Ms.) Megha Upendra Bhatt, Reader, PSDN | Member |
| 7. सुश्री इंदु कपूर, निदेशक, चेतना आउटरीच | बाहरी सदस्य |
| Ms. Indu Kapoor Director, Chetna Outreach | External Member |
| 8. डॉ. (सुश्री) निष्ठा अनिल कुमार, पुस्तकालय अधिकारी -एफ., पुस्तकालय | संयोजक |
| Dr. (Ms.) Nishtha Anilkumar, Library Officer – F, Library | Convener |

Dr. Anil Bhardwaj
29/6/2021

डॉ. अनिल भारद्वाज

Dr. Anil Bhardwaj

निदेशक / Director

सेवा में: अध्यक्ष एवं समिति के सदस्य To: Chair and Members of Committee

प्रतिलिपि: रजिस्ट्रार, पी.आर.एल. cc: Registrar, PRL

सभी संबंधितों के लिए To all concerned

Dr. Anil Bhardwaj
PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE
(PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013

ACT NO. 14 OF 2013

[22nd April, 2013]

An Act to provide protection against sexual harassment of women at workplace and for the prevention and redressal of complaints of sexual harassment and for matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS sexual harassment results in violation of the fundamental rights of a woman to equality under articles 14 and 15 of the Constitution of India and her right to life and to live with dignity under article 21 of the Constitution and right to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business with includes a right to a safe environment free from sexual harassment;

AND WHEREAS the protection against sexual harassment and the right to work with dignity are universally recognised human rights by international conventions and instruments such as Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women, which has been ratified on the 25th June, 1993 by the Government of India;

AND WHEREAS it is expedient to make provisions for giving effect to the said Convention for protection of women against sexual harassment at workplace.

BE it enacted by Parliament in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows: —

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

(2) It extends to the whole of India.

(3) It shall come into force on such date¹ as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires, —

(a) “aggrieved woman” means—

(i) in relation to a workplace, a woman, of any age whether employed or not, who alleges to have been subjected to any act of sexual harassment by the respondent;

(ii) in relation to dwelling place or house, a woman of any age who is employed in such a dwelling place or house;

(b) “appropriate Government” means—

(i) in relation to a workplace which is established, owned, controlled or wholly or substantially financed by funds provided directly or indirectly—

(A) by the Central Government or the Union territory administration, the Central Government;

(B) by the State Government, the State Government;

1. 9th December, 2013, vide notification No. S.O. 3606(E), dated 9th December, 2013, see Gazette of India, Extraordinary, Part II, sec. 3(ii).

(ii) in relation to any workplace not covered under sub-clause (i) and falling within its territory, the State Government;

(c) "Chairperson" means the Chairperson of the Local Complaints Committee nominated under sub-section (1) of section 7;

(d) "District Officer" means an officer notified under section 5;

(e) "domestic worker" means a woman who is employed to do the household work in any household for remuneration whether in cash or kind, either directly or through any agency on a temporary, permanent, part time or full time basis, but does not include any member of the family of the employer;

(f) "employee" means a person employed at a workplace for any work on regular, temporary, *ad hoc* or daily wage basis, either directly or through an agent, including a contractor, with or, without the knowledge of the principal employer, whether for remuneration or not, or working on a voluntary basis or otherwise, whether the terms of employment are express or implied and includes a co-worker, a contract worker, probationer, trainee, apprentice or called by any other such name;

(g) "employer" means—

(i) in relation to any department, organisation, undertaking, establishment, enterprise, institution, office, branch or unit of the appropriate Government or a local authority, the head of that department, organisation, undertaking, establishment, enterprise, institution, office, branch or unit or such other officer as the appropriate Government or the local authority, as the case may be, may by an order specify in this behalf;

(ii) in any workplace not covered under sub-clause (i), any person responsible for the management, supervision and control of the workplace.

Explanation. —For the purposes of this sub-clause "management" includes the person or board or committee responsible for formulation and administration of policies for such organisation;

(iii) in relation to workplace covered under sub-clauses (i) and (ii), the person discharging contractual obligations with respect to his or her employees;

(iv) in relation to a dwelling place or house, a person or a household who employs or benefits from the employment of domestic worker, irrespective of the number, time period or type of such worker employed, or the nature of the employment or activities performed by the domestic worker;

(h) "Internal Committee" means an Internal Complaints Committee constituted under section 4;

(i) "Local Committee" means the Local Complaints Committee constituted under section 6;

(j) "Member" means a Member of the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be;

(k) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(l) "Presiding Officer" means the Presiding Officer of the Internal Complaints Committee nominated under sub-section (2) of section 4;

(m) "respondent" means a person against whom the aggrieved woman has made a complaint under section 9;

(n) "sexual harassment" includes any one or more of the following unwelcome acts or behavior (whether directly or by implication) namely:—

- (i) physical contact and advances; or
- (ii) a demand or request for sexual favours; or
- (iii) making sexually coloured remarks; or
- (iv) showing pornography; or
- (v) any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature;

(o) "workplace" includes—

(i) any department, organisation, undertaking, establishment, enterprise, institution, office, branch or unit which is established, owned, controlled or wholly or substantially financed by funds provided directly or indirectly by the appropriate Government or the local authority or a Government company or a corporation or a co-operative society;

(ii) any private sector organisation or a private venture, undertaking, enterprise, institution, establishment, society, trust, non-governmental organisation, unit or service provider carrying on commercial, professional, vocational, educational, entertainment, industrial, health services or financial activities including production, supply, sale, distribution or service;

(iii) hospitals or nursing homes;

(iv) any sports institute, stadium, sports complex or competition or games venue, whether residential or not used for training, sports or other activities relating thereto;

(v) any place visited by the employee arising out of or during the course of employment including transportation by the employer for undertaking such journey;

(vi) a dwelling place or a house;

(p) "unorganised sector" in relation to a workplace means an enterprise owned by individuals or self-employed workers and engaged in the production or sale of goods or providing service of any kind whatsoever, and where the enterprise employs workers, the number of such workers is less than ten.

3. Prevention of sexual harassment.—(1) No woman shall be subjected to sexual harassment at any workplace.


(2) The following circumstances, among other circumstances, if it occurs, or is present in relation to or connected with any act or behavior of sexual harassment may amount to sexual harassment:—

- (i) implied or explicit promise of preferential treatment in her employment; or
- (ii) implied or explicit threat of detrimental treatment in her employment ; or
- (iii) implied or explicit threat about her present or future employment status; or
- (iv) interference with her work or creating an intimidating or offensive or hostile work environment for her; or
- (v) humiliating treatment likely to affect her health or safety.

CHAPTER II

CONSTITUTION OF INTERNAL COMPLAINTS COMMITTEE

4. Constitution of Internal Complaints Committee.— (1) Every employer of a workplace shall, by an order in writing, constitute a Committee to be known as the "Internal Complaints Committee":


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

Provided that where the offices or administrative units of the workplace are located at different places or divisional or sub-divisional level, the Internal Committee shall be constituted at all administrative units or offices.

(2) The Internal Committees shall consist of the following members to be nominated by the employer, namely: —

(a) a Presiding Officer who shall be a woman employed at a senior level at workplace from amongst the employees:

Provided that in case a senior level woman employee is not available, the Presiding Officer shall be nominated from other offices or administrative units of the workplace referred to in sub-section(1):

Provided further that in case the other offices or administrative units of the workplace do not have a senior level woman employee, the Presiding Officer shall be nominated from any other workplace of the same employer or other department or organisation;

(b) not less than two Members from amongst employees preferably committed to the cause of women or who have had experience in social work or have legal knowledge;

(c) one member from amongst non-governmental organisations or associations committed to the cause of women or a person familiar with the issues relating to sexual harassment:

Provided that at least one-half of the total Members so nominated shall be women.

(3) The Presiding Officer and every Member of the Internal Committee shall hold office for such period, not exceeding three years, from the date of their nomination as may be specified by the employer.

(4) The Member appointed from amongst the non-governmental organisations or associations shall be paid such fees or allowances for holding the proceedings of the Internal Committee, by the employer, as may be prescribed.

(5) Where the Presiding Officer or any Member of the Internal Committee, —

(a) contravenes the provisions of section 16; or

(b) has been convicted for an offence or an inquiry into an offence under any law for the time being in force is pending against him; or

(c) he has been found guilty in any disciplinary proceedings or a disciplinary proceeding is pending against him; or

(d) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest,

such Presiding Officer or Member, as the case may be, shall be removed from the Committee and the vacancy so created or any casual vacancy shall be filled by fresh nomination in accordance with the provisions of this section.

CHAPTER III

CONSTITUTION OF LOCAL COMPLAINTS COMMITTEE

5. Notification of District Officer.—The appropriate Government may notify a District Magistrate or Additional District Magistrate or the Collector or Deputy Collector as a District Officer for every District to exercise powers or discharge functions under this Act.

6. Constitution and jurisdiction of ¹[Local Committee].—(1) Every District Officer shall constitute in the district concerned, a committee to be known as the "¹[Local Committee]" to receive complaints of

1. Subs. by Act 23 of 2016, s. 3 and the Second Schedule, for "Local Complaints Committee" (w.e.f. 6-5-2016).


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

sexual harassment from establishments where the ¹[Internal Committee] has not been constituted due to having less than ten workers or if the complaint is against the employer himself.

(2) The District Officer shall designate one nodal officer in every block, taluka and tehsil in rural or tribal area and ward or municipality in the urban area, to receive complaints and forward the same to the concerned ²[Local Committee] within a period of seven days.

(3) The jurisdiction of the ²[Local Committee] shall extend to the areas of the district where it is constituted.

7. Composition, tenure and other terms and conditions of ²[Local Committee].—(1) The ²[Local Committee] shall consist of the following members to be nominated by the District Officer, namely: —

(a) a Chairperson to be nominated from amongst the eminent women in the field of social work and committed to the cause of women;

(b) one Member to be nominated from amongst the women working in block, taluka or tehsil or ward or municipality in the district;

(c) two Members, of whom at least one shall be a woman, to be nominated from amongst such non-governmental organisations or associations committed to the cause of women or a person familiar with the issues relating to sexual harassment, which may be prescribed:

Provided that at least one of the nominees should, preferably, have a background in law or legal knowledge:

Provided further that at least one of the nominees shall be a woman belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or the Other Backward Classes or minority community notified by the Central Government, from time to time;

(d) the concerned officer dealing with the social welfare or women and child development in the district, shall be a member *ex officio*.

(2) The Chairperson and every Member of the Local Committee shall hold office for such period, not exceeding three years, from the date of their appointment as may be specified by the District Officer.

(3) Where the Chairperson or any Member of the ²[Local Committee]—

(a) contravenes the provisions of section 16; or

(b) has been convicted for an offence or an inquiry into an offence under any law for the time being in force is pending against him; or

(c) has been found guilty in any disciplinary proceedings or a disciplinary proceeding is pending against him; or

(d) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest,

such Chairperson or Member, as the case may be, shall be removed from the Committee and the vacancy so created or any casual vacancy shall be filled by fresh nomination in accordance with the provisions of this section.

(4) The Chairperson or Members of the Local Committee other than the Members nominated under clauses (b) and (d) of sub-section (1) shall be entitled to such fees or allowances for holding the proceedings of the Local Committee as may be prescribed.

8. Grants and audit.—(1) The Central Government may, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, make to the State Government grants of such sums of money as the Central

1. Subs. by Act 23 of 2016, s. 3 and the Second Schedule, for "Internal Complaints Committee" (w.e.f. 6-5-2016).

2. Subs. by s. 3 and the Second Schedule, *ibid.*, for "Local Complaints Committee" (w.e.f. 6-5-2016).

Government may think fit, for being utilised for the payment of fees or allowances referred to in sub-section (4) of section 7.

(2) The State Government may set up an agency and transfer the grants made under sub-section (1) to that agency.

(3) The agency shall pay to the District Officer, such sums as may be required for the payment of fees or allowances referred to in sub-section (4) of section 7.

(4) The accounts of the agency referred to in sub-section (2) shall be maintained and audited in such manner as may, in consultation with the Accountant General of the State, be prescribed and the person holding the custody of the accounts of the agency shall furnish, to the State Government, before such date, as may be prescribed, its audited copy of accounts together with auditors' report thereon.

CHAPTER IV

COMPLAINT

9. Complaint of sexual harassment.—(1) Any aggrieved woman may make, in writing, a complaint of sexual harassment at workplace to the Internal Committee if so constituted, or the Local Committee, in case it is not so constituted, within a period of three months from the date of incident and in case of a series of incidents, within a period of three months from the date of last incident:

Provided that where such complaint cannot be made in writing, the Presiding Officer or any Member of the Internal Committee or the Chairperson or any Member of the Local Committee, as the case may be, shall render all reasonable assistance to the woman for making the complaint in writing:

Provided further that the Internal Committee or, as the case may be, the Local Committee may, for the reasons to be recorded in writing, extend the time limit not exceeding three months, if it is satisfied that the circumstances were such which prevented the woman from filing a complaint within the said period.

(2) Where the aggrieved woman is unable to make a complaint on account of her physical or mental incapacity or death or otherwise, her legal heir or such other person as may be prescribed may make a complaint under this section.

10. Conciliation.—(1) The Internal Committee or, as the case may be, the Local Committee, may, before initiating an inquiry under section 11 and at the request of the aggrieved woman take steps to settle the matter between her and the respondent through conciliation:

Provided that no monetary settlement shall be made as a basis of conciliation.

(2) Where settlement has been arrived at under sub-section (1), the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, shall record the settlement so arrived and forward the same to the employer or the District Officer to take action as specified in the recommendation.

(3) The Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, shall provide the copies of the settlement as recorded under sub-section (2) to the aggrieved woman and the respondent.

(4) Where a settlement is arrived at under sub-section (1), no further inquiry shall be conducted by the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be.

11. Inquiry into complaint.—(1) Subject to the provisions of section 10, the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, shall, where the respondent is an employee, proceed to make inquiry into the complaint in accordance with the provisions of the service rules applicable to the respondent and where no such rules exist, in such manner as may be prescribed or in case of a domestic worker, the Local Committee shall, if *prima facie* case exist, forward the complaint to the police, within a period of seven days for registering the case under section 509 of the Indian Penal Code (45 of 1860), and any other relevant provisions of the said Code where applicable:

Provided that where the aggrieved woman informs the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, that any term or condition of the settlement arrived at under sub-section (2) of section 10 has not been complied with by the respondent, the Internal Committee or the Local Committee shall proceed to make an inquiry into the complaint or, as the case may be, forward the complaint to the police:

Provided further that where both the parties are employees, the parties shall, during the course of inquiry, be given an opportunity of being heard and a copy of the findings shall be made available to both the parties enabling them to make representation against the findings before the Committee.

(2) Notwithstanding anything contained in section 509 of the Indian Penal Code (45 of 1860), the court may, when the respondent is convicted of the offence, order payment of such sums as it may consider appropriate, to the aggrieved woman by the respondent, having regard to the provisions of section 15.

(3) For the purpose of making an inquiry under sub-section (1), the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, shall have the same powers as are vested in a civil court the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) when trying a suit in respect of the following matters, namely:—

- (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
 - (b) requiring the discovery and production of documents; and
 - (c) any other matter which may be prescribed.
- (4) The inquiry under sub-section (1) shall be completed within a period of ninety days.

CHAPTER V

INQUIRY INTO COMPLAINT

12. Action during pendency of inquiry.—(1) During the pendency of an inquiry on a written request made by the aggrieved woman, the Internal Committee or the local Committee, as the case may be, may recommend to the employer to—

- (a) transfer the aggrieved woman or the respondent to any other workplace; or
- (b) grant leave to the aggrieved woman up to a period of three months; or
- (c) grant such other relief to the aggrieved woman as may be prescribed.

(2) The leave granted to the aggrieved woman under this section shall be in addition to the leave she would be otherwise entitled.

(3) On the recommendation of the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, under sub-section (1), the employer shall implement the recommendations made under sub-section (1) and send the report of such implementation to the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be.

13. Inquiry report.—(1) On the completion of an inquiry under this Act, the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, shall provide a report of its findings to the employer, or as the case may be, the District Officer within a period of ten days from the date of completion of the inquiry and such report be made available to the concerned parties.

(2) Where the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, arrives at the conclusion that the allegation against the respondent has not been proved, it shall recommend to the employer and the District Officer that no action is required to be taken in the matter.

(3) Where the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, arrives at the conclusion that the allegation against the respondent has been proved, it shall recommend to the employer or the District Officer, as the case may be—

(i) to take action for sexual harassment as a misconduct in accordance with the provisions of the service rules applicable to the respondent or where no such service rules have been made, in such manner as may be prescribed;

(ii) to deduct, notwithstanding anything in the service rules applicable to the respondent, from the salary or wages of the respondent such sum as it may consider appropriate to be paid to the aggrieved woman or to her legal heirs, as it may determine, in accordance with the provisions of section 15:

Provide that in case the employer is unable to make such deduction from the salary of the respondent due to his being absent from duty or cessation of employment it may direct to the respondent to pay such sum to the aggrieved woman:

Provided further that in case the respondent fails to pay the sum referred to in clause (ii), the Internal Committee or as, the case may be, the Local Committee may forward the order for recovery of the sum as an arrear of land revenue to the concerned District Officer.

(4) The employer or the District Officer shall act upon the recommendation within sixty days of its receipt by him.

14. Punishment for false or malicious complaint and false evidence.—(1) Where the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, arrives at a conclusion that the allegation against the respondent is malicious or the aggrieved woman or any other person making the complaint has made the complaint knowing it to be false or the aggrieved woman or any other person making the complaint has produced any forged or misleading document, it may recommend to the employer or the District Officer, as the case may be, to take action against the woman or the person who has made the complaint under sub-section (1) or sub-section (2) of section 9, as the case may be, in accordance with the provisions of the service rules applicable to her or him or where no such service rules exist, in such manner as may be prescribed:

Provided that a mere inability to substantiate a complaint or provide adequate proof need not attract action against the complainant under this section:

Provided further that the malicious intent on part of the complainant shall be established after an inquiry in accordance with the procedure prescribed, before any action is recommended.

(2) Where the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, arrives at a conclusion that during the inquiry any witness has given false evidence or produced any forged or misleading document, it may recommend to the employer of the witness or the District Officer, as the case may be, to take action in accordance with the provisions of the service rules applicable to the said witness or where no such service rules exist, in such manner as may be prescribed.

15. Determination of compensation.—For the purpose of determining the sums to be paid to the aggrieved woman under clause (ii) of sub-section (3) of section 13, the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, shall have regard to—

- (a) the mental trauma, pain, suffering and emotional distress caused to the aggrieved woman;
- (b) the loss in the career opportunity due to the incident of sexual harassment;
- (c) medical expenses incurred by the victim for physical or psychiatric treatment;
- (d) the income and financial status of the respondent;
- (e) feasibility of such payment in lump sum or in instalments.

16. Prohibition of publication or making known contents of complaint and inquiry proceedings.—Notwithstanding anything contained in the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), the contents of the complaint made under section 9, the identity and addresses of the aggrieved woman, respondent and witnesses, any information relating to conciliation and inquiry proceedings, recommendations of the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, and the action taken by the employer or the District Officer under the provisions of this Act shall not be published, communicated or made known to the public, press and media in any manner:

Provided that information may be disseminated regarding the justice secured to any victim of sexual harassment under this Act without disclosing the name, address, identity or any other particulars calculated to lead to the identification of the aggrieved woman and witnesses.

17. Penalty for publication or making known contents of complaint and inquiry proceedings.—Where any person entrusted with the duty to handle or deal with the complaint, inquiry or any recommendations or action to be taken under the provisions of this Act, contravenes the provisions of section 16, he shall be liable for penalty in accordance with the provisions of the service rules applicable to the said person or where no such service rules exist, in such manner as may be prescribed.

18. Appeal.—(1) Any person aggrieved from the recommendations made under sub-section (2) of section 13 or under clause (i) or clause (ii) of sub-section (3) of section 13 or sub-section (1) or sub-section (2) of section 14 or section 17 or non-implementation of such recommendations may prefer an appeal to the court or tribunal in accordance with the provisions of the service rules applicable to the said person or where no such service rules exist then, without prejudice to provisions contained in any other law for the time being in force, the person aggrieved may prefer an appeal in such manner as may be prescribed.

(2) The appeal under sub-section (1) shall be preferred within a period of ninety days of the recommendations.

CHAPTER VI

DUTIES OF EMPLOYER

19. Duties of employer.— Every employer shall—

(a) provide a safe working environment at the workplace with shall include safety from the persons coming into contact at the workplace;

(b) display at any conspicuous place in the workplace, the penal consequences of sexual harassments; and the order constituting, the Internal Committee under sub-section (1) of section 4;

(c) organise workshops and awareness programmes at regular intervals for sensitising the employees with the provisions of the Act and orientation programmes for the members of the Internal Committee in the manner as may be prescribed;

(d) provide necessary facilities to the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, for dealing with the complaint and conducting an inquiry;

(e) assist in securing the attendance of respondent and witnesses before the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be;

(f) make available such information to the Internal Committee or the Local Committee, as the case be, as it may require having regard to the complaint made under sub-section (1) of section 9;

(g) provide assistance to the woman if she so chooses to file a complaint in relation to the offence under the Indian Penal Code (45 of 1860) or any other law for the time being in force;

(h) cause to initiate action, under the Indian Penal Code (45 of 1860) or any other law for the time being in force, against the perpetrator, or if the aggrieved woman so desires, where the perpetrator is not an employee, in the workplace at which the incident of sexual harassment took place;

(i) treat sexual harassment as a misconduct under the service rules and initiate action for such misconduct;

(j) monitor the timely submission of reports by the Internal Committee.

CHAPTER VII

DUTIES AND POWERS OF DISTRICT OFFICER

20. Duties and powers of District Officer.—The District Officer shall, —

(a) monitor the timely submission of report furnished by the Local Committee;

(b) take such measures as may be necessary for engaging non-governmental organisations for creation of awareness on sexual harassment and the rights of the women.

CHAPTER VIII

MISCELLANEOUS

21. Committee to submit annual report.—(1) The Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, shall in each calendar year prepare, in such form and at such time as may be prescribed, an annual report and submit the same to the employer and the District Officer.

(2) The District Officer shall forward a brief report on the annual reports received under sub-section (1) to the State Government.

22. Employer to include information in annual report.—The employer shall include in its report the number of cases filed, if any, and their disposal under this Act in the annual report of his organisation or where no such report is required to be prepared, intimate such number of cases, if any, to the District Officer.

23. Appropriate Government to monitor implementation and maintain data.—The appropriate Government shall monitor the implementation of this Act and maintain date on the number of cases filed and disposed of in respect of all cases of sexual harassment at workplace.

24. Appropriate Government to take measures to publicise the Act.—The appropriate Government may, subject to the availability of financial and other resources, —

(a) develop relevant information, education, communication and training materials, and organise awareness programmes, to advance the understanding of the public of the provisions of this Act providing for protection against sexual harassment of woman at workplace;

(b) formulate orientation and training programmes for the members of the ¹[Local Committee].

25. Power to call for information and inspection of records.—(1) The appropriate Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest or in the interest of women employees at a workplace to do so, by order in writing,—

(a) call upon any employer or District Officer to furnish in writing such information relating to sexual harassment as it may require;

(b) authorise any officer to make inspection of the records and workplace in relation to sexual harassment, who shall submit a report of such inspection to it within such period as may be specified in the order.

(2) Every employer and District Officer shall produce on demand before the officer making the inspection all information, records and other documents in his custody having a bearing on the subject matter of such inspection.

26. Penalty for non-compliance with provisions of Act.—(1) Where the employer fails to—

(a) constitute an Internal Committee under sub-section (1) of section 4;

1. Subs. by Act 23 of 2016, s. 3 and the Second Schedule, for "Local Complaints Committee" (w.e.f. 6-5-2016).

(b) take action under sections 13, 14 and 22; and

(c) contravenes or attempts to contravene or abets contravention of other provisions of this Act or any rules made thereunder,

he shall be punishable with fine which may extend to fifty thousand rupees.

(2) If any employer, after having been previously convicted of an offence punishable under this Act subsequently commits and is convicted of the same offence, he shall be liable to—

(i) twice the punishment, which might have been imposed on a first conviction, subject to the punishment being maximum provided for the same offence:

Provided that in case a higher punishment is prescribed under any other law for the time being in force, for the offence for which the accused is being prosecuted, the court shall take due cognizance of the same while awarding the punishment;

(ii) cancellation, of his licence or withdrawal, or non-renewal, or approval, or cancellation of the registration, as the case may be, by the Government or local authority required for carrying on his business or activity.

27. Cognizance of offence by courts.—(1) No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act or any rules made thereunder, save on a complaint made by the aggrieved woman or any person authorised by the Internal Committee or Local Committee in this behalf.

(2) No court inferior to that of a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of the first class shall try any offence punishable under this Act.

(3) Every offence under this Act shall be non-cognizable.

28. Act not in derogation of any other law.—The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force.

29. Power of appropriate Government to make rules.—(1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the fees or allowances to be paid to the Members under sub-section (4) of section 4;

(b) nomination of members under clause (c) of sub-section (1) of section 7;

(c) the fees or allowances to be paid to the Chairperson, and Members under sub-section (4) of section 7;

(d) the person who may make complaint under sub-section (2) of section 9;

(e) the manner of inquiry under sub-section (1) of section 11;

(f) the powers for making an inquiry under clause (c) of sub-section (2) of section 11;

(g) the relief to be recommended under clause (c) of sub-section (1) of section 12;

(h) the manner of action to be taken under clause (i) of sub-section (3) of section 13;

(i) the manner of action to be taken under sub-sections (1) and (2) of section 14;

(j) the manner of action to be taken under section 17;

(k) the manner of appeal under sub-section (1) of section 18;

(l) the manner of organising workshops, awareness programmes for sensitising the employees and orientation programmes for the members of the Internal Committee under clause (c) of section 19; and

(m) the form and time for preparation of annual report by Internal Committee and the Local Committee under sub-section (1) of section 21.


(3) Every rule made by the Central Government under this Act shall be laid as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

(4) Any rule made under sub-section (4) of section 8 by the State Government shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature where it consists of two Houses, or where such Legislature consists of one House, before that House.

30. Power to remove difficulties.— (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it to be necessary for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament.


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013

(2013 का अधिनियम संख्यांक 14)

[22 अप्रैल, 2013]

महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण और
लैंगिक उत्पीड़न के परिवादों के निवारण तथा
प्रतितोषण और उससे संबंधित या उसके
आनुषंगिक विषयों का उपबंध
करने के लिए
अधिनियम

लैंगिक उत्पीड़न के परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 के अधीन समता तथा संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण और गरिमा से जीवन व्यतीत करने के किसी महिला के मूल अधिकारों और किसी वृत्ति का व्यवसाय करने या कोई उपजीविका, व्यापार या कारबार करने के अधिकार का, जिसके अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण का अधिकार भी है, उल्लंघन होता है;

और, लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण तथा गरिमा से कार्य करने का अधिकार, महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के विभेदों को दूर करने संबंधी अभिसमय जैसे अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों और लिखतों द्वारा सर्वव्यापी मान्यताप्राप्त ऐसे मानवाधिकार हैं, जिनका भारत सरकार द्वारा 25 जून, 1993 को अनुसमर्थन किया गया है;

और, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से महिलाओं के संरक्षण के लिए उक्त अभिसमय को प्रभावी करने के लिए उपबंध करना समीचीन है;

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएँ—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "संयुक्त महिला" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) किसी कार्यस्थल के संबंध में, किसी भी आयु की ऐसी महिला, चाहे नियोजित है या नहीं, जो प्रत्यर्थी द्वारा लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य के करने का अभिकथन करती है;

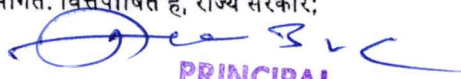
(ii) किसी निवास स्थान या गृह के संबंध में, किसी भी आयु की ऐसी महिला, जो ऐसे किसी निवास स्थान या गृह में नियोजित है;

(ख) "संयुक्त सरकार" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) ऐसे कार्यस्थल के संबंध में, जो,—

(अ) केन्द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित है, केन्द्रीय सरकार;

(आ) राज्य सरकार द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित है, राज्य सरकार;


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

(ii) उपखंड (i) के अंतर्गत न आने वाले और उसके राज्यक्षेत्र के भीतर आने वाले किसी कार्यस्थल के संबंध में, राज्य सरकार;

(10) "अध्यक्ष" से धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट स्थानीय परिवार समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(11) "जिला अधिकारी" से धारा 5 के अधीन अधिसूचित कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(12) "घरेलू कर्मकार" से ऐसी कोई महिला अभिप्रेत है जो किसी गृहस्थी में पारिवारिक के लिए गृहस्थी का कार्य करने के लिए, चाहे नकद या वस्तुरूप में, या तो सीधे या किसी अभिकरण के माध्यम से अस्थायी, स्थायी, अंशकालिक या पूर्णकालिक आधार पर नियोजित है किंतु इसके अंतर्गत नियोजक के कुटुंब का कोई सदस्य नहीं है;

(13) "कर्मचारी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी कार्यस्थल पर किसी कार्य के लिए या तो सीधे या किसी अभिकर्ता के माध्यम से, जिसके अंतर्गत कोई ठेकेदार भी है, प्रधान नियोजक की जानकारी से या उसके बिना, नियमित, अस्थायी, तत्काल या दैनिक मजदूरी के आधार पर, चाहे पारिवारिक पर या उसके बिना, नियोजित है या स्वैच्छिक आधार पर या अन्याय कार्य कर रहा है, चाहे नियोजन के निबंधन अभिव्यक्त या विवक्षित हैं या नहीं और इसके अंतर्गत कोई सहकर्मकार, कोई संविदा कर्मकार, परिवीक्षाधीन, शिषु, प्रशिक्षु या ऐसे किसी अन्य नाम से ज्ञात कोई व्यक्ति भी है;

(14) "नियोजक" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट के संबंध में, उस विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट का प्रधान या ऐसा अन्य अधिकारी जो, यथास्थिति, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

(ii) उपखंड (i) के अंतर्गत न आने वाले किसी कार्यस्थल के संबंध में, कार्यस्थल के प्रबंध, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "प्रबंध" के अंतर्गत ऐसे संगठन के लिए नीतियों की विनिर्दिष्टि और प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या बोर्ड या समिति भी है;

(iii) उपखंड (i) और उपखंड (ii) के अंतर्गत आने वाले कार्यस्थल के संबंध में, अपने कर्मचारियों के संबंध में संविदात्मक बाध्यताओं का निर्वहन करने वाला व्यक्ति;

(iv) किसी निवास स्थान या गृह के संबंध में, ऐसा कोई व्यक्ति या गृहस्थी, जो ऐसे नियोजित कर्मकार की संख्या, समयावधि या प्रकार या नियोजन की प्रकृति या घरेलू कर्मकार द्वारा निष्पादित कार्यकलापों का विचार दिए बिना, घरेलू कर्मकार को नियोजित करता है या उसके नियोजन से फायदा प्राप्त करता है;

(15) "आंतरिक समिति" से धारा 4 के अधीन गठित आंतरिक परिवार समिति अभिप्रेत है;

(16) "स्थानीय समिति" से धारा 6 के अधीन गठित स्थानीय परिवार समिति अभिप्रेत है;

(17) "सदस्य" से, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति का कोई सदस्य अभिप्रेत है;

(18) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(19) "पीठासीन अधिकारी" से धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन नामनिर्दिष्ट किया गया आंतरिक परिवार समिति का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है;

(20) "प्रत्यर्धी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध व्यथित महिला ने धारा 9 के अधीन कोई परिवार किया है;

(21) "लैंगिक उत्पीड़न" के अंतर्गत निम्नलिखित कोई एक या अधिक अवांछनीय कार्य या व्यवहार चाहे प्रत्यक्ष रूप से या विवक्षित रूप से हैं, अर्थात्:—

(i) शारीरिक संपर्क और अग्रगमन; या


(ii) लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध करना; या

(iii) लैंगिक अत्युक्त टिप्पणियां करना; या

(iv) अश्लील साहित्य दिखाना; या

(v) लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण करना;

(22) "कार्यस्थल" के अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं—


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

(i) ऐसा कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट, जो समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी सरकारी कम्पनी या निगम या सहकारी सोसाइटी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या पूर्णतः या सारतः, उसके द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित की जाती है;

(ii) कोई प्राइवेट सेक्टर संगठन या किसी प्राइवेट उद्यम, उपक्रम, उद्यम, संस्था, स्थापन, सोसाइटी, स्थापन, गैर-सरकारी संगठन, यूनिट या सेवा प्रदाता, जो वाणिज्यिक, वृत्तिक, व्यावसायिक, शैक्षिक, मनोरंजक, औद्योगिक, स्वास्थ्य सेवाएं या वित्तीय क्रियाकलाप करता है, जिनके अंतर्गत उत्पादन, प्रदाता, विक्रय, वितरण या सेवा भी है;

(iii) अस्पताल या परिचर्या गृह;

(iv) प्रशिक्षण, खेलकूद या उनसे संबंधित अन्य क्रियाकलापों के लिए प्रयुक्त, कोई खेलकूद संस्थान, स्टेडियम, खेलकूद प्रक्षेत्र या प्रतिस्पर्धा या क्रीडा का स्थान, चाहे आवासीय है या नहीं;

(v) नियोजन से उद्भूत या उसके प्रक्रम के दौरान कर्मचारी द्वारा परिदर्शित कोई स्थान जिसके अंतर्गत ऐसी यात्रा करने के लिए नियोजक द्वारा उपलब्ध कराया गया परिवहन भी है;

(vi) कोई निवास स्थान या कोई गृह;

(र) किसी कार्यस्थल के संबंध में, असंगठित सेक्टर से ऐसा कोई उद्यम अभिप्रेत है, जो व्यष्टियों या स्वनियोजित कर्मचारियों के स्वामित्वाधीन है और किसी प्रकार के माल के उत्पादन या विक्रय अथवा सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है और जहां उद्यम, कर्मचारियों को नियोजित करता है, वहां ऐसे कर्मचारियों की संख्या दस से अन्यून है।

3. लैंगिक उत्पीड़न का निवारण—(1) किसी भी महिला का किसी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा।

(2) अन्य परिस्थितियों में निम्नलिखित परिस्थितियां, यदि वे लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य या आचरण के संबंध में होती हैं या विद्यमान हैं या उससे संबद्ध हैं, लैंगिक उत्पीड़न की कोटि में आ सकेंगी :—

(i) उसके नियोजन में अधिमानी व्यवहार का विवक्षित या सुस्पष्ट वचन देना; या

(ii) उसके नियोजन में अहितकर व्यवहार की विवक्षित या सुस्पष्ट धमकी देना; या

(iii) उसके वर्तमान या भावी नियोजन की प्रास्थिति के बारे में विवक्षित या सुस्पष्ट धमकी देना; या

(iv) उसके कार्य में हस्तक्षेप करना या उसके लिए अभिवासरमय या संतापकारी या प्रतिकूल कार्य वातावरण सृजित करना; या

(v) उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करने की संभावना वाला अपमानजनक व्यवहार करना।

अध्याय 2

आंतरिक परिवाद समिति का गठन

4. आंतरिक परिवाद समिति का गठन—(1) किसी कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक, लिखित आदेश द्वारा, "आंतरिक परिवाद समिति" नामक एक समिति का गठन करेगा :

परंतु जहां कार्यस्थल के कार्यालय या प्रशासनिक यूनिटें, भिन्न-भिन्न स्थानों या खंड या उपखंड स्तर पर अवस्थित हैं, वहां आंतरिक समिति सभी प्रशासनिक यूनिटों या कार्यालयों में गठित की जाएगी।

(2) आंतरिक समिति, नियोजक द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) एक पीठासीन अधिकारी, जो कर्मचारियों में से कार्यस्थल पर ज्येष्ठ स्तर पर नियोजित महिला होगी :

परंतु किसी ज्येष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी के उपलब्ध नहीं होने की दशा में, पीठासीन अधिकारी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक यूनिटों से नामनिर्देशित किया जाएगा :

परंतु यह और कि कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक यूनिटों में ज्येष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी नहीं होने की दशा में, पीठासीन अधिकारी, उसी नियोजक या अन्य विभाग या संगठन के किसी अन्य कार्यस्थल से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(ख) कर्मचारियों में से दो से अन्यून ऐसे सदस्य, जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति अधिमानी रूप से प्रतिबद्ध हैं या जिनके पास सामाजिक कार्य में अनुभव है या विधिक ज्ञान है;


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

(ग) गैर-सरकारी संगठनों या संगमों में से ऐसा एक सदस्य जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध है या ऐसा कोई व्यक्ति, जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से सुपरिचित है :

परंतु इस प्रकार नामनिर्देशित कुल सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्य महिलाएं होंगी।

(3) आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी और प्रत्येक सदस्य अपने नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष से अधिक की ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा, जो नियोजक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(4) गैर-सरकारी संगठनों या संगमों में से नियुक्त किए गए सदस्य को आंतरिक समिति की कार्यवाहियां करने के लिए नियोजक द्वारा ऐसी फीस या भत्ते, जो विहित किए जाएं, संदत्त किए जाएंगे।

(5) जहां आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी या कोई सदस्य,—

(क) धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करता है; या

(ख) किसी अपराध के लिए सिद्धोष ठहराया गया है या उसके विरुद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध की कोई प्रांच लंबित है; या

(ग) किहीं अनुशासनिक कार्यवाहियों में दोषी पाया गया है या उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है; या

(घ) अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग करता है, जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो गया है,

वहां, यथास्थिति, ऐसे पीठासीन अधिकारी या सदस्य को समिति से हटा दिया जाएगा और इस प्रकार सृजित रिक्ति या किसी अन्य आकस्मिक रिक्ति को इस धारा के उपबंधों के अनुसार नए नामनिर्देशन द्वारा भरा जाएगा।

अध्याय 3

स्थानीय परिवाद समिति का गठन

5. जिला अधिकारी की अधिसूचना—समुचित सरकार, इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने या कृत्यों का निर्वहन करने के लिए किसी जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट या कलक्टर या उप कलक्टर को प्रत्येक जिले के लिए जिला अधिकारी के रूप में अधिसूचित कर सकेगी।

6. स्थानीय परिवाद समिति का गठन और उसकी अधिकारिता—(1) प्रत्येक जिला अधिकारी, संबंधित जिले में, ऐसे स्थापनों से जहां दस से कम वर्गका होने के कारण आंतरिक परिवाद समिति गठित नहीं की गई है या यदि परिवाद स्वयं नियोजक के विरुद्ध है, वहां लैंगिक उत्पीड़न के परिवाद ग्रहण करने के लिए "स्थानीय परिवाद समिति" नामक एक समिति का गठन करेगा।

(2) जिला अधिकारी, ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्र में प्रत्येक ब्लॉक, ताल्लुका और तहसील में और शहरी क्षेत्र में बार्ड या नगरपालिका में परिवाद ग्रहण करने के लिए और सात दिन की अवधि के भीतर उसको संबंधित स्थानीय परिवाद समिति को भेजने के लिए एक नोटिस अधिवार्ड को पदाभिहित करेगा।

(3) स्थानीय परिवाद समिति की अधिकारिता का विस्तार जिले के उन क्षेत्रों पर होगा, जहां वह गठित की गई है।

7. स्थानीय परिवाद समिति की संरचना, सेवाधृति और अन्य निर्बंधन तथा शर्तें—(1) स्थानीय परिवाद समिति, जिला अधिकारी द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्—

(अ) अध्यक्ष, जो सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रख्यात और महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध महिलाओं में से नामनिर्दिष्ट की जाएगी;

(ब) एक सदस्य, जो जिले में ब्लॉक, ताल्लुका या तहसील या बार्ड या नगरपालिका में कार्यरत महिलाओं में से नामनिर्दिष्ट की जाएगी;

(ग) दो सदस्य, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी, जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध ऐसे गैर-सरकारी संगठनों या संगमों में से या ऐसा व्यक्ति, जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित ऐसे मुद्दों से सुपरिचित हो जो विहित किए जाएं, नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

परंतु कम से कम एक नामनिर्देशिनी के पास, अधिमानी रूप से विधि की पृष्ठभूमि या विधिक ज्ञान होना चाहिए।

परंतु यह और कि कम से कम एक नामनिर्देशिनी, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय की महिला होगी;

(घ) जिले में सामाजिक कल्याण या महिला और बाल विकास से संबंधित संबद्ध अधिकारी, सदस्य पदेन होगा।


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

(2) स्थानीय समिति का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष से अधिक की ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जो जिला अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(3) जहां स्थानीय परिवार समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य,—

(क) धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करता है; या

(ख) किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है या उसके विरुद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध की कोई जांच लंबित है; या

(ग) किन्हीं अनुशासनिक कार्यवाहियों में दोषी पाया गया है या उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है; या

(घ) अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग करता है, जिससे उसका अपने पद पर बने रहना लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो गया है,

वहां, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को समिति से हटा दिया जाएगा और इस प्रकार सृजित रिक्ति या किसी आकस्मिक रिक्ति को इस धारा के उपबंधों के अनुसार नए नामनिर्देशन से भरा जाएगा।

(4) स्थानीय समिति का अध्यक्ष और उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों से भिन्न सदस्य स्थानीय समिति की कार्यवाहियां करने के लिए ऐसी फीसों या भत्तों के लिए, जो विहित किए जाएं, हकदार होंगे।

8. अनुदान और संपरीक्षा—(1) केंद्रीय सरकार, संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् राज्य सरकार को धारा 7 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट फीसों या भत्तों के संदाय के लिए उपयोग किए जाने के लिए ऐसी धनराशियों के, जो केंद्रीय सरकार टीक समझौते, अनुदान दे सकेगी।

(2) राज्य सरकार, एक अभिकरण की स्थापना कर सकेगी और उस अभिकरण को उपधारा (1) के अधीन किए गए अनुदान अंतरित कर सकेगी।

(3) अभिकरण, जिला अधिकारी को ऐसी राशियों का, जो धारा 7 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट फीसों या भत्तों के संदाय के लिए अपेक्षित हों, संदाय करेगा।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट अभिकरण के लेखाओं को ऐसी रीति से रखा और संपरीक्षित किया जाएगा, जो राज्य के महालेखाकार के परामर्श से विहित की जाए और अभिकरण के लेखाओं को अभिरक्षा में रखने वाला व्यक्ति, ऐसी तारीख से पूर्व, जो विहित की जाए, राज्य सरकार को लेखाओं की संपरीक्षित प्रति, उस पर संपरीक्षक की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करेगा।

अध्याय 4

परिवाद

9. लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद—(1) कोई व्यक्ति महिला, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद, घटना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर और श्रृंखलाबद्ध घटनाओं की दशा में अंतिम घटना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर, लिखित में, आंतरिक समिति को, यदि इस प्रकार गठित की गई है या यदि इस प्रकार गठित नहीं की गई है तो स्थानीय समिति को कर सकेगी।

परंतु जहां ऐसा परिवाद, लिखित में नहीं किया जा सकता है वहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी या कोई सदस्य, या स्थानीय समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य, महिला को लिखित में परिवाद करने के लिए सभी युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा।

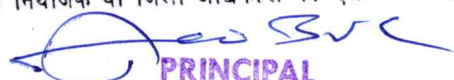
परंतु यह और कि, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से तीन मास से अधिक की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि परिस्थितियां ऐसी थीं, जिसने महिला को उक्त अवधि के भीतर परिवाद फाइल करने से निवारित किया था।

(2) कोई व्यक्ति महिला, अपनी शारीरिक या मानसिक असमर्थता या मृत्यु के कारण या अन्यथा परिवाद करने में असमर्थ है वहां उसका विधिक धारित्र या ऐसा अन्य व्यक्ति जो विहित किया जाए, इस धारा के अधीन परिवाद कर सकेगा।

10. सुलह—(1) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, धारा 11 के अधीन जांच आरंभ करने से पूर्व और व्यक्ति महिला के अनुरोध पर, सुलह के माध्यम से उसके और प्रत्यर्थी के बीच मामले को निपटाने के उपाय कर सकेगी।

परंतु कोई धनीय समझौता, सुलह के आधार के रूप में नहीं किया जाएगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई समझौता हो गया है, वहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, इस प्रकार किए गए समझौते को अभिलिखित करेगी और उसको नियोजक या जिला अधिकारी को ऐसी कार्रवाई, जो सिफारिश में विनिर्दिष्ट की जाए, करने के लिए भेजेगी।


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

(3) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, उपधारा (2) के अधीन अभिलिखित किए गए समझौते की प्रतियां व्यथित महिला और प्रत्यर्थी को उपलब्ध कराएंगी।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई समाधान हो जाता है, वहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति द्वारा कोई और जांच नहीं की जाएगी।

11. परिवाद की जांच—(1) धारा 10 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, जहां प्रत्यर्थी कोई कर्मचारी है, वहां प्रत्यर्थी को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार और जहां ऐसे कोई नियम विद्यमान नहीं हैं, वहां ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, परिवाद की जांच करने की कार्यवाही करेगी या किसी घरेलू कर्मकार की दशा में, स्थानीय समिति, यदि प्रथमदृष्ट्या मामला विद्यमान है, तो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 509 और जहां लागू हो, वहां उक्त संहिता के किन्हीं अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन मामला रजिस्टर करने के लिए सात दिन की अवधि के भीतर पुलिस को परिवाद भेजेगी:

परंतु जहां व्यथित महिला, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को यह सूचित करती है कि धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन किए गए समझौते के किसी निबंधन या शर्त का प्रत्यर्थी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है, वहां आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, यथास्थिति, परिवाद की जांच करने के लिए कार्यवाही करेगी या पुलिस को परिवाद भेजेगी:

परंतु यह और कि जहां दोनों पक्षकार कर्मचारी हैं, वहां पक्षकारों को, जांच के अनुक्रम के दौरान, सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और निष्कर्ष की प्रति दोनों पक्षकारों को, समिति के समक्ष निष्कर्षों के विरुद्ध अभ्यावेदन करने में उनको समर्थ बनाने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 509 में किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय, जब प्रत्यर्थी को अपराध का सिद्धोप ठहराया जाता है, तब धारा 15 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी द्वारा व्यथित महिला को ऐसी राशि के संदाय का, जो वह समुचित समझे, आदेश कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन जांच करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को वही शक्तियां होंगी, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:—

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसको हाजिर कराना तथा उसकी शपथ पर परीक्षा करना;

(ख) किन्हीं दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) ऐसा कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

(4) उपधारा (1) के अधीन जांच, नब्बे दिन की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

अध्याय 5

परिवाद की जांच

12. जांच लंबित रहने के दौरान कार्यवाई—(1) जांच लंबित रहने के दौरान, व्यथित महिला द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, नियोजक को निम्नलिखित सिफारिश कर सकेगी,—

(क) व्यथित महिला या प्रत्यर्थी का किसी अन्य कार्यस्थल पर स्थानान्तरण करना; या

(ख) व्यथित महिला को तीन मास तक की अवधि की छुट्टी अनुदान करना; या

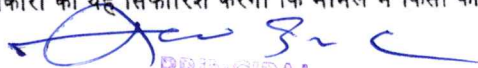
(ग) व्यथित महिला को ऐसी अन्य राहत, जो विहित की जाए प्रदान करना।

(2) इस धारा के अधीन व्यथित महिला को अनुदत्त छुट्टी ऐसी छुट्टी के अतिरिक्त होगी, जिसके लिए वह अन्यथा हकदार होगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिश पर, नियोजक, उपधारा (1) के अधीन की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करेगा और ऐसे कार्यान्वयन की रिपोर्ट, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को भेजेगा।

13. जांच रिपोर्ट—(1) इस अधिनियम के अधीन जांच के पूरा होने पर, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति अपने निष्कर्षों को एक रिपोर्ट, यथास्थिति, नियोजक या जिला अधिकारी को जांच के पूरा होने की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर उपलब्ध कराएंगी और ऐसी रिपोर्ट संबंधित पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) जहां यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभिकथन साबित नहीं किया गया है वहां, वह, नियोजक और जिला अधिकारी को यह सिफारिश करेगी कि मामले में किसी कार्यवाई का किया जाना अपेक्षित नहीं है।


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

(3) जहाँ, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभिकथन साबित हो गया है, वहाँ, वह, यथास्थिति, नियोजक या जिला अधिकारी से निम्नलिखित के लिए सिफारिश करेगी,—

(i) प्रत्यर्थी को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार कदाचार के रूप में या जहाँ, ऐसे सेवा नियम नहीं बनाए गए हैं, वहाँ ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, लैंगिक उत्पीड़न के लिए कार्रवाई करने;

(ii) प्रत्यर्थी को लागू सेवा नियमों में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्यर्थी के वेतन या मजदूरी से व्यथित महिला को या उसके विधिक वारिसों को संदत्त की जाने वाली ऐसी राशि की जो वह समुचित समझे, कटौती करने, जो धारा 15 के उपबंधों के अनुसार वह अवधारित करे :

परंतु यदि नियोजक प्रत्यर्थी के कर्तव्य से अनुपस्थित रहने या नियोजन के समाप्त हो जाने के कारण उसके वेतन से ऐसी कटौती करने में असमर्थ है तो वह प्रत्यर्थी को, व्यथित महिला को ऐसी राशि का संदाय करने का निदेश दे सकेगा :

परंतु यह और कि यदि प्रत्यर्थी, खंड (ii) में निर्दिष्ट राशि का संदाय करने में असफल रहता है तो, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, संबंधित जिला अधिकारी को भू-राजस्व के बकाया के रूप में राशि की वसूली के लिए आदेश अग्रेषित कर सकेगी ।

(4) नियोजक या जिला अधिकारी, उसके द्वारा सिफारिश की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर उस पर कार्रवाई करेगा ।

14. मिथ्या या द्वेषपूर्ण परिवार और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड—(1) जहाँ, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभिकथन द्वेषपूर्ण है या व्यथित महिला या परिवार करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने परिवार को मिथ्या जानते हुए किया है या व्यथित महिला या परिवार करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कूटरचित या धमक दस्तावेज पेश किया है तो वह, यथास्थिति, नियोजक या जिला अधिकारी को ऐसी महिला या व्यक्ति के विरुद्ध जिसने, यथास्थिति, धारा 9 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन परिवार किया है, उसको लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार या जहाँ ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं हैं, वहाँ, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगी :

परंतु किसी परिवार को सिद्ध करने या पर्याप्त सबूत उपलब्ध कराने में केवल असमर्थता, इस धारा के अधीन परिवादी के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ नहीं करेगी :

परंतु यह और कि किसी कार्रवाई की सिफारिश किए जाने से पूर्व, विहित प्रक्रिया के अनुसार कोई जांच करने के पश्चात् परिवारी की ओर से द्वेषपूर्ण आशय सिद्ध किया जाएगा ।

(2) जहाँ, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि जांच के दौरान किसी साक्षी ने मिथ्या साक्ष्य दिया है या कोई कूटरचित या धमक दस्तावेज दिया है, वहाँ वह, यथास्थिति, साक्षी के नियोजक या जिला अधिकारी को, उक्त साक्षी को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार या जहाँ ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं हैं, वहाँ ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगी ।

15. प्रतिकर का अवधारण—धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (ii) के अधीन व्यथित महिला को संदत्त की जाने वाली राशियों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति निम्नलिखित को ध्यान में रखेगी,—

(क) व्यथित महिला को कारित हुए मानसिक आघात, पीड़ा, यातना और भावात्मक कष्ट;

(ख) लैंगिक उत्पीड़न की घटना के कारण वृत्ति के अवसर की हानि;

(ग) पीड़ित द्वारा शारीरिक या मनश्चिकित्सीय उपचार के लिए उपगत चिकित्सा व्यय;

(घ) प्रत्यर्थी की आय और वित्तीय हैसियत;

(ङ) एकमुश्त या किस्तों में ऐसे संदाय की साध्यता ।

16. परिवार की अंतर्वस्तुओं और जांच कार्यवाहियों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने का प्रतिषेध—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) में किसी बात के होते हुए भी, धारा 9 के अधीन किए गए परिवार की अंतर्वस्तुओं, व्यथित महिला, प्रत्यर्थी और साक्षियों की पहचान और पते, सुलह और जांच कार्यवाहियों से संबंधित किसी जानकारी, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति भी सिफारिशों तथा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियोजक या जिला अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई को, किसी भी रीति से, प्रकाशित, प्रेस और मीडिया को संसूचित या सार्वजनिक नहीं किया जाएगा :

परंतु इस अधिनियम के अधीन लैंगिक उत्पीड़न की किसी पीड़ित को सुनिश्चित न्याय के संबंध में जानकारी का, व्यथित महिला और साक्षियों के नाम, पते या पहचान या उनकी पहचान को प्रकल्पित करने वाली किन्हीं अन्य विशिष्टियों को प्रकट किए बिना, प्रसारित किया जा सकेगा ।

17. परिवार की अंतर्वस्तुओं और जांच कार्यवाहियों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने के लिए शक्ति—जहाँ कोई व्यक्ति, जिसको इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन परिवार, जांच या किन्हीं सिफारिशों या की जाने वाली कार्रवाई का संचालन करने या

उस पर कार्यवाही करने का कर्तव्य सौंपा गया है, धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वहां वह उक्त व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार या जहां ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं हैं, वहां, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, शास्ति के लिए दायी होगा।

18. अपील—(1) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन या धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (i) या खंड (ii) या धारा 14 की उपधारा (1) या उपधारा (2) या धारा 17 के अधीन की गई सिफारिशों या ऐसी सिफारिशों को कार्यान्वित न किए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति, उक्त व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार न्यायालय या अधिकरण को अपील कर सकेगा या जहां ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं हैं, वहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, व्यथित व्यक्ति ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, अपील कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील, सिफारिशों के नब्बे दिन की अवधि के भीतर की जाएगी।

अध्याय 6

नियोजक के कर्तव्य

19. नियोजक के कर्तव्य—प्रत्येक नियोजक,—

- (क) कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराएगा, जिसके अंतर्गत कार्यस्थल पर संपर्क में आने वाले व्यक्तियों से सुरक्षा भी है;
- (ख) लैंगिक उत्पीड़न के शास्तिक परिणाम; और धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन आंतरिक समिति का गठन करने वाले आदेश को कार्यस्थल में किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा;
- (ग) अधिनियम के उपबंधों से कर्मचारियों को सुग्राही बनाने के लिए नियमित अंतरालों पर कार्यशालाएं और जानकारी कार्यक्रम और आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, आयोजित करेगा;
- (घ) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को परिवाद पर कार्यवाही करने और जांच का संचालन करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा;
- (ङ) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के समक्ष प्रत्यर्थी और साक्षियों की हाजिरी सुनिश्चित करने में सहायता करेगा;
- (च) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा, जो धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन किए गए परिवाद को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित हो;
- (छ) महिला को, यदि वह भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपराध के संबंध में कोई परिवाद फाइल करना, चयन करती है, सहायता प्रदान करेगा;
- (ज) ऐसे कार्यस्थल में, जिसमें लैंगिक उत्पीड़न की घटना हुई थी, अपराधकर्ता के विरुद्ध या यदि व्यथित महिला ऐसी वांछा करती है, जहां अपराधकर्ता कोई कर्मचारी नहीं है, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कार्रवाई आरंभ करवाएगा;
- (झ) लैंगिक उत्पीड़न को सेवा नियमों के अधीन कदाचार मानेगा और ऐसे कदाचार के लिए कार्रवाई आरंभ करेगा;
- (ञ) आंतरिक समिति द्वारा रिपोर्टों को समय पर प्रस्तुत किए जाने को मानिटर करेगा।

अध्याय 7

जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियां

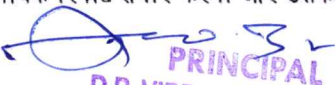
20. जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियां—जिला अधिकारी,—

- (क) स्थानीय समिति द्वारा दी गई रिपोर्टों को समय से प्रस्तुत किए जाने को मानिटर करेगा;
- (ख) ऐसे उपाय करेगा, जो लैंगिक उत्पीड़न और महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जानकारी सृजित करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को लगाने के लिए आवश्यक हों।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

21. समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना—(1) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, प्रत्येक कलेंडर वर्ष में, ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसको नियोजक तथा जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेगी।


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

(2) जिला अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन प्राप्त वार्षिक रिपोर्टों पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा।

22. नियोजक द्वारा वार्षिक रिपोर्ट में जानकारी का सम्मिलित किया जाना—नियोजक, अपनी रिपोर्ट में फाइल किए गए मामलों, यदि कोई हों, और अपने संगठन की वार्षिक रिपोर्ट में इस अधिनियम के अधीन उनके निपटारे की संख्या को सम्मिलित करेगा या जहां ऐसी रिपोर्ट तैयार किए जाने की अपेक्षा नहीं की गई है, वहां ऐसे मामलों की संख्या, यदि कोई हो, जिला अधिकारी को सूचित करेगा।

23. समुचित सरकार द्वारा कार्यान्वयन की मानिटरी और आंकड़े रखा जाना—समुचित सरकार इस अधिनियम के कार्यान्वयन की मानिटरी करेगी और कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के फाइल किए गए और निपटाए गए सभी मामलों की संख्या से संबंधित आंकड़े रखेगी।

24. समुचित सरकार द्वारा अधिनियम के प्रचार के लिए उपाय किया जाना—समुचित सरकार, वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए :—

(क) कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण के लिए उपबंध करने वाले इस अधिनियम के उपबंधों के बारे में जनता की समझ बढ़ाने के लिए सुसंगत सूचना, शिक्षा, संसूचना और प्रशिक्षण सामग्रियां विकसित कर सकेगी और जानकारी कार्यक्रम आयोजित कर सकेगी;

(ख) स्थानीय परिवार समिति के सदस्यों के लिए अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम निश्चित कर सकेगी।

25. सूचना मांगने और अभिलेखों का निरीक्षण करने की शक्ति—(1) समुचित सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में या कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के हित में आवश्यक है, लिखित आदेश द्वारा,—

(क) किसी नियोजक या जिला अधिकारी से लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में ऐसी लिखित सूचना जो उसको अपेक्षित हो प्रस्तुत करने की मांग कर सकेगी;

(ख) किसी ऐसे अधिकारी को लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में अभिलेखों और कार्यस्थल का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी, जो उसको ऐसी अवधि के भीतर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे निरीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) प्रत्येक नियोजक और जिला अधिकारी, मांग किए जाने पर निरीक्षण करने वाले अधिकारी के समक्ष, उसकी अभिरक्षा में ऐसी सभी सूचनाओं, अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करेंगे, जो ऐसे निरीक्षण की विषय-वस्तु से संबंधित हैं।

26. अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के लिए शास्ति—(1) जहां कोई नियोजक,—

(क) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन एक आंतरिक समिति का गठन करने में असफल रहेगा;

(ख) धारा 13, धारा 14 और धारा 22 के अधीन कार्रवाई करने में असफल रहेगा; और

(ग) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा या उनके उल्लंघन को दुष्प्रेरित करेगा,

वहां वह, ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(2) यदि कोई नियोजक इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध में पूर्ववर्ती सिद्धदोष ठहराए जाने के पश्चात् उसी अपराध को करता है और सिद्धदोष ठहराया जाता है तो वह,—

(i) उसी अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम दंड के अधीन रहते हुए, पूर्ववर्ती सिद्धदोष ठहराए जाने पर अधिकतम दंड से दुगुने दंड का दायी होगा;

परंतु यदि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे अपराध के लिए, जिसके संबंध में अभियुक्त का अभियोजन किया जा रहा है, कोई उच्चतर दंड विहित है तो न्यायालय दंड देते समय उसका सम्यक् संज्ञान लेगा;

(ii) सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उसके कारबार या क्रियाकलाप को चलाने के लिए अपेक्षित, यथास्थिति, उसकी अनुज्ञप्ति के रद्द किए जाने या रजिस्ट्रीकरण को समाप्त किए जाने या नवीकरण या अनुमोदन न किए जाने या रद्दकरण के लिए दायी होगा।

27. न्यायालयों द्वारा अपराध का संज्ञान—(1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, व्यथित महिला या आंतरिक समिति अथवा स्थानीय समिति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा परिवार किए जाने के सिवाय न करेगा।

(2) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध असंज्ञेय होगा।


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

28. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना—इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में।

29. समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

- (क) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन सदस्यों को संदत्त की जाने वाली फीसों या भत्ते;
- (ख) धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन सदस्यों का नामनिर्देशन;
- (ग) धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को संदत्त की जाने वाली फीसों या भत्ते;
- (घ) ऐसा व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन परिवाद कर सकेगा;
- (ङ) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जांच की रीति;
- (च) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन जांच करने की शक्तियां;
- (छ) धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन सिफारिश की जाने वाली राहत;
- (ज) धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (i) के अधीन की जाने वाली कार्रवाई की रीति;
- (झ) धारा 14 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन की जाने वाली कार्रवाई की रीति;
- (ञ) धारा 17 के अधीन की जाने वाली कार्रवाई करने की रीति;
- (ट) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन अपील की रीति;
- (ठ) धारा 19 के खंड (ग) के अधीन कर्मचारियों को सुग्राही बनाने के लिए कार्यशालाएं, जानकारी कार्यक्रम और आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करने की रीति; और
- (ड) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन आंतरिक समिति और स्थानीय समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रारंभ और समय।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(4) किसी राज्य सरकार द्वारा धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन बनाया गया कोई नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, जहां राज्य विधान-मंडल के दो सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां ऐसे विधान-मंडल का एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।

30. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों :

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।



PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

Laws related to women harassment and sexual exploitation

1. All such behaviour which directly or indirectly involves, or is motivated by, sexual feelings through disinterest.
2. Physical contact and attempts to get closer.
3. Demand for sexual favours.
4. Words with sexual connotation.
5. Showing obscene pictures.
6. Any other unpleasant physical, verbal or non-verbal contact with sexual overtones.
7. Sexual harassment that is done through insult, fear of health or safety.
8. Such sexual harassment is done by warning or threatening harmful consequences.
9. Sexual harassment that is likely to pollute the country or environment.
10. To flirt.
11. Trying to violate a woman's freedom.
12. Making crude jokes.
13. Having a real conversation on the phone.
14. To go against his will, to violate his privacy.
15. Committing any kind of excess.

In case of crime etc., inform the nearest police station, women's police station and State Women's Commission.

Broadcast in the interest of women by State Women Commission, Raipur, Chhattisgarh


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

महिला उत्पीड़न तथा यौन शोषण संबंधी कानून

1. ऐसे सभी व्यवहार जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो, जो अरुचि कर यौन भावना से प्रेरित हो ।
2. शारीरिक संपर्क एवं निकट आने का प्रयत्न ।
3. यौन अनुग्रह की मांग ।
4. यौन अर्थ से रंजित फलितियां ।
5. अश्लील चित्र दिखाना ।
6. कोई अन्य अरुचिकर यौन भाव वाला शारीरिक, मौखिक अथवा गैर-मौखिक संपर्क ।
7. ऐसा यौन उत्पीड़न जो अपमान, स्वास्थ्य या सुरक्षा का भय दिखाकर किया जाये ।
8. ऐसा यौन उत्पीड़न जो हानिकारक परिणामों की चेतावनी, धमकी देकर किया जाये ।
9. ऐसा यौन उत्पीड़न जो देश या माहौल दूषित हो की संभावना दिखाकर किया जाये ।
10. छेड़खानी करना ।
11. किसी स्त्री की स्वंत्रता भंग करने का प्रयत्न करना ।
12. भद्दा मजाक करना ।
13. फोन पर अश्लील बातचीत करना ।
14. इच्छा के विरुद्ध करना, उसकी निजता का उल्लंघन करना ।
15. किसी भी प्रकार की ज्यादाती करना ।


आदि संबंधी अपराध होने पर प्रमुख निकटस्थ पुलिस थाना, महिला थाना तथा राज्य महिला आयोग को सूचित करें ।

राज्य महिला आयोग, रायपुर, छत्तीसगढ़
द्वारा महिलाओं के हित में प्रसारित

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)



GUIDANCE FOR GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEE


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)





प्रो. रजनीश जैन
सचिव

Prof. Rajnish Jain
Secretary



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)

बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Ph.: 011-23236288/23239337

Fax : 011-2323 8858

E-mail : secy.ugc@nic.in

F.No. 14-4/2012(CPP-II)

7th December, 2018

PUBLIC NOTICE

ON

UGC (GRIEVANCE REDRESSAL) REGULATIONS, 2018

UGC had notified UGC (Grievance Redressal) Regulations, 2012 in official Gazette of India on **23rd March, 2013**. These regulations were aimed at addressing and effectively resolving grievances of students related to Higher Educational Institutions.

The UGC had received a number of responses on these regulations and hence constituted an Expert Committee to revisit UGC (Grievance Redressal) Regulations, 2012. The draft University Grants Commission (Grievance Redressal of Students) Regulations, 2018 prepared by the Committee is attached herewith for observations and suggestions of stakeholders. The feedback and comments on the above draft may be sent to UGC via email grmhei.2018@gmail.com on or before **31st December, 2018**.

(Prof. Rajnish Jain)

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

**UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADUR SHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI – 110 002**

NOTIFICATION

F.No.14-4/2012 (CPP-II)

New Delhi, the __ October, 2018

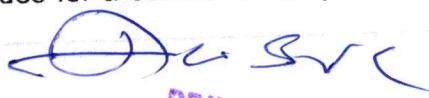
In exercise of the power conferred under clause (g) of sub-section (1) of Section 26 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), and in supersession of the University Grants Commission (Grievance Redressal) Regulations, 2012, the University Grants Commission hereby makes the following regulations:

1. SHORT TITLE, APPLICATION AND COMMENCEMENT:

- a) These regulations shall be called as the University Grants Commission (Grievance Redressal of Students) Regulations, 2018.
- b) They shall apply to all HEIs, whether established or incorporated by or under a Central Act or a State Act, and every institution recognised by the University Grants Commission under clause (f) of Section 2 of the University Grants Commission Act, 1956 and to all institutions deemed to be a university declared as such under Section 3 of the said Act.
- c) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. DEFINITION: IN THESE REGULATIONS, UNLESS THE CONTEXT OTHERWISE REQUIRES:

- (a) "Act" means the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);
- (b) "aggrieved student" means a student who has any complaint in the matters concerned with the grievances defined under these regulations, and includes a person seeking admission to any institution of higher education;
- (c) "college" means any institution, whether known as such or by any other name, which provides for a course of study for obtaining any


**PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)**

qualification from a university and which, in accordance with the rules and regulations of such university, is recognised as competent to provide for such course of study and present students undergoing such course of study for the examination for the award of such qualification;

(d) "Commission" means the University Grants Commission established under section 4 of the UGC Act, 1956.

(e) "declared admission policy" means such policy for admission to a course or program of study as may be offered by the institution and published in the prospectus referred to in sub-regulation (1) of regulation 3;

(f) "grievances" include the following complaints of the aggrieved students, namely:

- i. making admission contrary to merit determined in accordance with the declared admission policy of the institution;
- ii. irregularity in the admission process adopted by the institution;
- iii. refusing admission in accordance with the declared admission policy of the institution;
- iv. non publication of prospectus, (either hard copy / online) as specified in these regulations;
- v. publishing any information in the prospectus, which is false or misleading, and not based on facts;
- vi. withhold or refuse to return any document in the form of certificates of degree, diploma or any other award or other document deposited with it by a students for the purpose of seeking admission in such institution, with a view to induce or compel such student to pay any fee or fees in respect of any course or program of study which such student does not intend to pursue;
- vii. demand of money in excess of that specified in the declared admission policy to be charged by such institution;


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

- viii. breach in reservation policy in admission as may be applicable;
 - ix. nonpayment or delay in payment of scholarships to any student that such institution is committed, under the conditions imposed by University Grants Commission, or by any other authority;
 - x. delay in conduct of examinations or declaration of results beyond the specified schedule in the academic calendar;
 - xi. on provision of student amenities as may have been promised or required to be provided by the institution;
 - xii. non transparent or unfair evaluation practices;
 - xiii. Refund of fees, in case a student withdraws the admission within the stipulated time as mentioned in the prospectus, as notified by the Commission from time to time.
- (g) "Department Grievance Redressal Committee" means a committee constituted under these regulations, at the level of a Department.
- (h) "Institutional Grievance Redressal Committee" means a committee constituted under these regulations, at the level of an Institution.
- (i) "College Grievance Redressal Committee" means a committee constituted under these regulations, at the level of a college.
- (j) "University Grievance Redressal Committee" means a committee constituted under these regulations, at the level of a University.
- (k) "Higher Educational Institution" means a University within the meaning of clause (f) of Section 2, a college within the meaning of clause (b) of sub-section (1) of Section 12A, and an institution deemed to be a University declared under Section 3, of the University Grants Commission Act, 1956;
- (l) "Institution" for the purposes of these regulations, means any university, college or such other institutions, as the case may be;
- (m) "Office of profit" means an office which is capable of yielding a profit or pecuniary gain, and to which some pay, salary, emolument, remuneration or non-compensatory allowance is attached;

(n) "Ombudsperson" means the Ombudsperson appointed under these regulations;

(o) "University" means a university established or incorporated by or under a Central Act or a State Act and includes an institution deemed to be university declared as such under Section 3 of the Act.

3. MANDATORY PUBLICATION OF PROSPECTUS, ITS CONTENTS AND PRICING:


- i. Every higher educational institution, shall publish and/or upload on its website, before expiry of at least sixty days prior to the date of the commencement of the admission to any of its courses or programs of study, a prospectus containing the following for the information of persons intending to seek admission to such institution and the general public, namely:
 - (a) the list of programs of study and courses offered along with the broad outlines of the syllabus specified by the appropriate statutory authority or by the institution, as the case may be, for every course or program of study, including teaching hours, practical sessions and other assignments;
 - (b) the number of seats approved by the appropriate statutory authority in respect of each course or program of study for the academic year for which admission is proposed to be made;
 - (c) the conditions of educational qualifications and eligibility including the minimum and maximum age limit of persons for admission as a student in a particular course or program of study, specified by the institution;
 - (d) the process of selection of eligible candidates applying for such admission, including all relevant information in regard to the details of test or examination for selecting such candidates for admission to each course or program of study and the amount of fee prescribed for the admission test;


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

- (e) each component of the fee, deposits and other charges payable by the students admitted to such institution for pursuing a course or program of study, and the other terms and conditions of such payment;
- (f) rules / regulations for imposition and collection of any fines specified heads or categories, minimum and maximum fine may be imposed.
- (g) the percentage of tuition fee and other charges refundable to a student admitted in such institution in case such student withdraws from such institution before or after completion of course or program of study and the time within and the manner in which such refund shall be made to that student;
- (h) details of the teaching faculty, including their educational qualifications, alongwith the category they belong to Regular / visiting ----- and teaching experience of every member of its teaching faculty.
- (i) information with regard to physical and academic infrastructure and other facilities including hostel accommodation and its fee, library, hospital or industry wherein the practical training to be imparted to the students and in particular the facilities accessible by students on being admitted to the institution;
- (j) all relevant instructions in regard to maintaining the discipline by students within or outside the campus of the institution.
- (k) any other information as may be specified by the Commission:

Provided that an institution shall publish / upload information referred to in items (a) to (k) of this regulation, on its website, and the attention of prospective students and the general public shall be drawn to such publication on the website through advertisements displayed prominently in different newspapers and through other media:

- ii. Every institution shall fix the price of each printed copy of the prospectus, being not more than the reasonable cost of its


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

publication and distribution and no profit be made out of the publication, distribution or sale of prospectus.

4. GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEES (GRC):

A. Department Grievance Redressal Committee (DGRC)

- (i) In case of universities, all complaints relating to a department shall first be addressed to Department Grievance Redressal Committee (DGRC) to be constituted at the level of departments/school/center whose composition shall be as follows:
 - a) Head of the Department / School / Center – Chairperson
 - b) a Professor from outside the department / school / center to be nominated by the Head of HEI – Member
 - c) A faculty member well-versed with grievance redressal mechanism to be nominated by the Head of the Department – Member.
- (ii) The Chairperson and members of the committee shall have a term of two years.
- (iii) The quorum for the meeting shall be two, including Chairperson.
- (iv) The DGRC shall follow the principles of natural justice while deciding the grievances of the students.
- (v) The DGRC shall make efforts to resolve the grievance within the stipulated period and shall submit its report to the Head of the Institution within a period of 15 days from the date of receipt of complaint to the DGRC.
- (vi) The DGRC shall provide a copy of the report to the aggrieved person(s).

B. Institutional Grievance Redressal Committee (IGRC)


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

- (i) The complaints not related to departments/schools / center and the grievances not resolved at the DGRC shall be referred to the Institutional Grievance Redressal Committee (IGRC) to be constituted by Head of the HEI, whose composition shall be as follows:
 - (a) Pro-Vice Chancellor / Dean/ Senior academician of HEI – Chairperson.
 - (b) Dean of students/Dean, Students Welfare
 - (c) Two senior academicians other than Chairperson.
 - (d) Proctor / Senior academician
- (ii) The above Committee shall be approved by the statutory body of institution (Executive Council or its equivalent).
- (iii) The Chairperson of IGRC and DGRC shall not be the same. The tenure of the Committee members shall be two years.
- (iv) The quorum for the meetings shall be three, including Chairperson.
- (v) The IGRC shall consider the recommendation of DGRC while giving its recommendations. However, the IGRC shall have the power to review recommendations of the DGRC.
- (vi) The IGRC shall follow the principles of natural justice while deciding the grievances.
- (vii) The IGRC shall send the report and the recommendations to the Head of the HEI within in a period of 15 workings days from the date of receipt of grievance, or appeal or recommendations of the DGRC.
- (viii) The IGRC shall provide a copy of the report to the aggrieved person(s).


C. College Grievance Redressal Committee (CGRC)


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

- (i) In case of colleges, all complaints shall first be addressed to College Grievance Redressal Committee (CGRC) whose composition shall be as follows:
 - a) Principal of the college -Chairperson
 - b) Two senior faculty members nominated by the principal of the College.
- (ii) The tenure of the members shall be two years.
- (iii) The quorum for the meeting shall be two, including Chairperson.
- (iv) The CGRC shall follow the principles of natural justice while considering the grievances of the students.
- (v) The CGRC shall send the report and recommendations to the Vice-Chancellor of the affiliating university within a period of 15 days of receiving the complaint.

D. University Grievance Redressal Committee (UGRC)

- (i) In case of grievances not resolved by CGRC, it shall be referred to University Grievance Redressal Committee (UGRC) for which the Vice-chancellor of the affiliating university shall constitute a University Grievance Redressal Committee (UGRC) consisting of five members for a individual colleges or a group of colleges keeping in view the location of the college(s). The UGRC shall be constituted by the Vice-chancellor of the affiliating university consisting of :
 - a) A senior Professor of the university – Chairperson
 - b) Dean, Student Welfare or its equivalent - Member
 - c) Three Principals drawn from the affiliating colleges, on rotation basis to be nominated by the Vice-Chancellor – Members
- (ii) The Chairperson and members of the committee shall have a term of two years.
- (iii) The quorum for the meeting shall be two, including Chairperson.


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

(iv) The CGRC shall follow the principle of normal justice while deciding the grievance of the students.

(v) The CGRC shall send the report and the recommendations to the principal of the college within a period of 15 days of receiving the complaint.

E. Any person aggrieved by the decision of the Institutional Grievance Redressal Committee or University Grievance Redressal Committee may within in a period of six days prefer an appeal to the Ombudsperson.

5. APPOINTMENT, TENURE, REMOVAL AND CONDITIONS OF SERVICES OF OMBUDSPERSON:

(i) Each HEI shall appoint an Ombudsperson for redressal of grievances of students under these regulations.

(ii) The Ombudsperson shall be a person not related to the university and who is a retired Vice-Chancellor, Registrar or a faculty member who has at least ten years of experience as a Professor.

(iii) The Ombudsperson shall not be in any conflict of interest with the university, either before or after his appointment.


(iv) The Ombudsperson, or any member of his immediate family shall not -

(a) hold or have held at any point in the past, any post or, employment in any office of profit in the university;

(b) have any significant relationship, including personal, family, professional or financial, with the university;

(c) hold any position in university by whatever name called, in the administration or governance structure of the university.

(v) The Ombudsperson in a State University shall be appointed by the Executive council of the university on part-time basis from a panel of three names recommended by the search committee consisting of the following members, namely:-


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

- (a) Nominee of the Governor of the State or his nominee - Chairperson
 - (b) Vice-Chancellor of a University of State to be nominated by the State Government – Member
 - (c) Vice-Chancellor of the concerned State University – Member
 - (d) Registrar of the concerned State University – Secretary (non-voting)
- (vi) The Ombudsperson in a Central University and institution deemed to be university shall be appointed by the Executive Council of the Central University or the equivalent statutory body of the Deemed to be University, as the case may be, on part - time basis from a panel of three member recommended by the search committee consisting of the following members, namely:-

- (a) Nominee of University Grants Commission – Chairperson
- (b) One Vice Chancellor from Central University to be nominated by UGC (for Central Universities) – Member

OR

One Vice Chancellor from institution deemed to be university to be nominated by the UGC (for Deemed to be Universities) - Member

- (c) The Vice Chancellor of the university – Member
 - (d) The Registrar of the university – Secretary (Non-Voting)
- (vii) The Ombudsperson shall be a part time officer appointed for a period of three years from the date he/she assumes the office and may be reappointed for another one term in the same university.
- (viii) The Ombudsperson shall be paid the sitting fee per day as per the norms of the university for hearing the cases, in addition to the reimbursement of the conveyance.


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

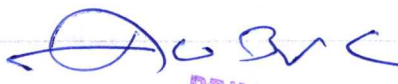
- (ix) The Ombudsperson may be removed on charges of proven misconduct or misbehavior or as defined under these regulations, by the concerned appointing authority i.e. the Executive Council of the University.

6. FUNCTIONS OF OMBUDSPERSON:

- (i) The Ombudsperson shall hear any appeal of an applicant for admission as student or student of the university against the university or institution affiliated to it as the case may be, after the student has availed all remedies available in such institution for redressal of grievance such as IGRC / UGRC;
- (ii) No application for revaluation or remarking of answer sheets shall be entertained by the Ombudsperson. However, the issues of malpractices in the examination and evaluation processes may be referred to the Ombudsperson.
- (iii) Ombudsperson may seek the assistance of any person as amicus curiae, for hearing complaints of alleged discrimination.
- (iv) The Ombudsperson shall make all efforts to resolve the grievances within a period of 30 days of receiving the appeal from the student(s).

7. PROCEDURE FOR REDRESSAL OF GRIEVANCES BY OMBUDSPERSON AND GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEE:

- (i) Each institution shall, within a period of three months from the date of issue of this notification, have an online portal where any aggrieved student of that institution may submit an application seeking grievance redressal.
- (ii) On receipt of any online complaint, the institution shall refer the complaint to the appropriate Grievance Redressal Committee, as the case may be, along with its comments within 15 days of receipt of complaint on online portal.
- (iii) The Grievance Redressal Committee, as the case may be, shall fix a date for hearing the complaint which shall be communicated to the institution and the aggrieved person.


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

- (iv) An aggrieved person may appear either in person or be represented by such person as may be authorized to present his/her case.
- (v) The Grievances not resolved at the appropriate Grievance Redressal Committee(s) shall be referred to the Ombudsperson.
- (vi) The institution shall co-operate with the Ombudsperson or the Grievance Redressal Committee(s), as the case may be, in redressal of grievances and failure to do so may be reported by the Ombudsperson to the Vice Chancellor.
- (vii) On the conclusion of proceedings, the Ombudsperson shall pass such order, with reasons for such order, as may be deemed fit to redress the grievance and provide such relief as may be desirable to the affected party at issue, after giving due hearing to both the parties.
- (viii) Every order under the signature of the Ombudsperson shall be provided to the aggrieved person and the institution and shall be placed on the website of the institution.
- (ix) The institution shall comply with the recommendations of the Ombudsperson. Any recommendations of the Ombudsperson not complied with by the institution shall be reported by the Ombudsperson to the Commission.
- (x) In case of any false or frivolous complaint, the Ombudsperson may recommend appropriate action against the complainant.

8. INFORMATION REGARDING OMBUDSPERSON GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEE:

The institution shall provide detailed information regarding provisions of Grievance Redressal Committee(s) and Ombudsperson on their website and in their prospectus prominently.

9. CONSEQUENCES OF NON-COMPLIANCE:

The Commission shall in respect of any institution which willfully contravenes these regulations or repeatedly fails to comply with the recommendation of the Ombudsperson or the Grievance Redressal

Committee(s), as the case may be, may proceed to take one or more of the following actions, namely:

- (a) withdrawal of declaration of fitness to receive grants under section 12B of the Act;
- (b) withholding any grant allocated to the Institution;
- (c) declaring the institution ineligible for consideration for any assistance under any of the general or special assistance programs of the Commission;
- (d) informing the general public, including potential candidates for admission, through a notice displayed prominently in suitable media and posted on the website of the Commission, declaring that the institution does not possess the minimum standards for redressal of grievances;
- (e) recommend to the affiliating university for withdrawal of affiliation, in case of a college;
- (f) The Commission may take necessary and appropriate action as it may deemed fit, in case of an institution deemed to be university;
- (g) recommend to the concerned State Government for necessary and appropriate action, in case of a university established or incorporated under a State Act;
- (h) The Commission may take necessary and appropriate actions against any institution for non-compliance.

Provided that no action shall be taken by the Commission under this regulation unless the institution has been given an opportunity to explain its position and an opportunity of being heard has been provided to it.

(Prof. Rajnish Jain)
Secretary


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

D.P. VIPRA LAW COLLEGE BILASPUR (C.G.)

Approved From BCI,
Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya Bilaspur (C.G.)

Appendix - II

D.P. Vipra Law College Bilaspur

Ashok Nagar, Seepat Road, Sarkanda, Bilaspur (C.G.)

D.P. VIPRA LAW COLLEGE BILASPUR (C.G.)

Approved From BCI,
Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya Bilaspur (C.G.)



Academic Year 2018-19

D.P. Vipra Law College Bilaspur
Ashok Nagar, Seepat Road, Sarkanda, Bilaspur (C.G.)

कार्यालय, प्राचार्य,

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

Ph. 07752-329260, 210760, E-Mail-dpvlawprincipal@yahoo.com www.dpvipralawcollege.com

पत्र क्रमांक ...Q/2018

दिनांक 06/08/2018

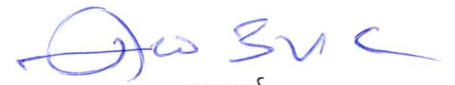
— :: सूचना :: —

डी. पी. विप्र विधि महाविद्यालय समस्त प्राध्यापकों कर्मचारियों एवं छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि रैगिंग को रोकने एवं अनुशासन को बनाये रखने हेतु अनुशासन एवं एंटी रैगिंग (Anti Ragging) समिति का गठन किया गया है जिसके सदस्य निम्नानुसार है —

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. प्रो. कु. सुषमा तिवारी | संयोजक |
| 2. प्रो. संतोष ठाकुर | सदस्य |
| 3. श्री आलोक शर्मा (खेल अधिकारी) | सदस्य |
| 4. प्रो. धर्मेन्द्र शर्मा | सदस्य |

प्रतिलिपि

1. माननीय अध्यक्ष महोदय प्रशासन समिति
2. प्रो. कु. सुषमा तिवारी
3. प्रो. संतोष ठाकुर
4. श्री आलोक शर्मा (खेल अधिकारी)
5. प्रो. धर्मेन्द्र शर्मा


प्राचार्य
PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

कार्यालय, प्राचार्य, डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
Ph. 07752-329260, 210760, E-Mail-dpvlawprincipal@yahoo.com www.dpvipralawcollege.com

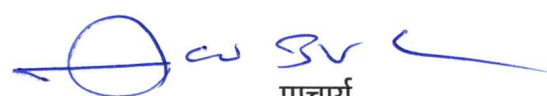
पत्र क्रमांकQ/2018

दिनांक 09/08/2018

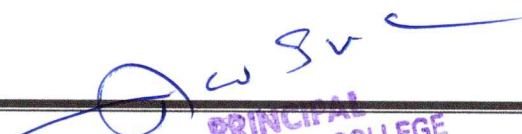
— :: आदेश :: —

शैक्षणिक सत्र 2018-2019 हेतु एन्टी रैगिंग समिति का गठन किया जाता है जिसके सदस्य निम्न हैं जो 12.08.2018 से प्रभावशील होगी।

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. प्रो. कु. सुषमा तिवारी | संयोजक |
| 2. प्रो. संतोष ठाकुर | सदस्य |
| 3. श्री आलोक शर्मा (खेल अधिकारी) | सदस्य |
| 4. प्रो. धर्मेन्द्र शर्मा | सदस्य |



प्राचार्य
PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)



PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

कार्यालय, प्राचार्य,

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
Ph. 07752-329260, 210760, E-Mail-dpvlawprincipal@yahoo.com www.dpvipralawcollege.com

पत्र क्रमांकQ / 2018

दिनांक 12 / 08 / 2018


Notice

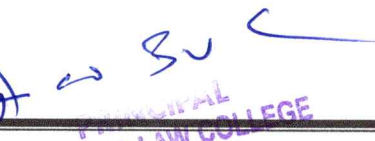
The Anti-Ragging Committee meeting will convene at the Principal Office on Monday, August 16, 2018, at 2:15 p.m.

Agenda for the meeting:

- 1: Greetings and Induction
- 2: Discuss the steps taken to stop ragging on campus.
- 3: Discuss subjects that have the chairman's consent.

Please make time to attend the meeting, as requested.


Principal
PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

कार्यालय, प्राचार्य,

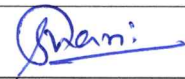

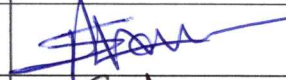

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
Ph. 07752-329260, 210760, E-Mail-dpvlawprincipal@yahoo.com www.dpvipralawcollege.com


पत्र क्रमांकQ/2018

दिनांक 16/08/2018

ATTENDENCE

S. No.	ATTENDENCE	SIGNATURE
1	MISS SUSHMA TIWARI	
2	MR. SANTOSH THAKUR	
3	MR. ALOK SHARMA	
4	MR. DHARMENDRA SHARMA	


Principal
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)


D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

कार्यालय, प्राचार्य,

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
Ph. 07752-329260, 210760, E-Mail-dpvlawprincipal@yahoo.com www.dpvipralawcollege.com

पत्र क्रमांक ..Q../2018

दिनांक 16/08/2018

Minutes of Meeting

Agenda 1:

Approval of Minutes of the Most Recent Meeting, Held on August 16, 2018.

Resolution:

The most recent meeting's minutes, which were read and overwhelmingly accepted on August 16, 2018, were adopted.

Agenda 2:

Talk about the ban on ragging.

Resolution:

The Committee members expressed their happiness and pride in stating that there have been no documented cases of ragging on campus, indicating that the Institute campus is free of ragging. The committee members expressed their gratitude to Miss Sushma Tiwari for his efforts in this respect, and they especially thanked him. Since there was nothing to discuss, the meeting was adjourned with a vote of gratitude from the in attendance.



PRINCIPAL
DRA VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

कार्यालय, प्राचार्य,

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

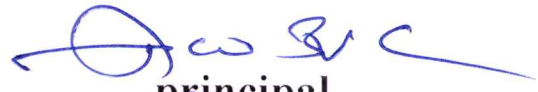
Ph. 07752-329260, 210760, E-Mail-dpvlawprincipal@yahoo.com www.dpvipralawcollege.com

पत्र क्रमांक९...../2018

दिनांक 16/08/2018

REPORT ON ACTIONS TAKEN AT THE TUESDAY, AUGUST 16,2018

Sr. No.	Resolution in the meeting	Action Taken for Implementation & Outcomes
NIL		


principal
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

D.P. VIPRA LAW COLLEGE BILASPUR (C.G.)

Approved From BCI,
Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya Bilaspur (C.G.)



Academic Year 2019-20

D.P. Vipra Law College Bilaspur
Ashok Nagar, Seepat Road, Sarkanda, Bilaspur (C.G.)

कार्यालय, प्राचार्य,

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

<https://dpvipralawcollege.ac.in> - Email - dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. - 9926165945, 9926138734

पत्र क्रमांक९...../2019

दिनांक 13/09/2019

- :: सूचना :: -

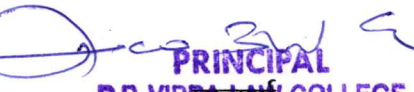
डी. पी. विप्र विधि महाविद्यालय समस्त प्राध्यापकों कर्मचारियों एवं छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि रैगिंग को रोकने एवं अनुशासन को बनाये रखने हेतु अनुशासन एवं एंटी रैगिंग (Anti Ragging) समिति का गठन किया गया है जिसके सदस्य निम्नानुसार है -

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. प्रो. कु. सुषमा तिवारी | संयोजक |
| 2. प्रो. संतोष ठाकुर | सदस्य |
| 3. श्री आलोक शर्मा (खेल अधिकारी) | सदस्य |
| 4. प्रो. धर्मेन्द्र शर्मा | सदस्य |

प्राचार्य

प्रतिलिपि

1. माननीय अध्यक्ष महोदय प्रशासन समिति
2. प्रो. कु. सुषमा तिवारी
3. प्रो. संतोष ठाकुर
4. श्री आलोक शर्मा (खेल अधिकारी)
5. प्रो. धर्मेन्द्र शर्मा


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)
डी.पी.विप्र. विधि महाविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

कार्यालय, प्राचार्य,

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

<https://dpvipralawcollege.ac.in> - Email - dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. - 9926165945, 9926138734

पत्र क्रमांक 9 / 2019

दिनांक 19/09/2019

— :: आदेश :: —

शैक्षणिक सत्र 2019-2020 हेतु एन्टी रैगिंग समिति का गठन किया जाता है जिसके सदस्य निम्न हैं जो 20.09.2019 से प्रभावशील होगी।

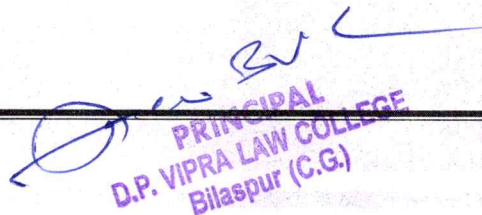
- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. प्रो. कु. सुषमा तिवारी | संयोजक |
| 2. प्रो. संतोष ठाकुर | सदस्य |
| 3. श्री आलोक शर्मा (खेल अधिकारी) | सदस्य |
| 4. प्रो. धर्मेन्द्र शर्मा | सदस्य |



प्राचार्य

डी.पी.विप्र. विधि महाविद्यालय,

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)



PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

कार्यालय, प्राचार्य,

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

<https://dpvipralawcollege.ac.in> – Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 992613873

पत्र क्रमांक ०९/२०१९ / 2019

दिनांक 20 / 09 / 2019


NOTICE

The meeting of anti-raging Committee has been scheduled on 23/09/2019 AT 1:30 pm in staff room.


You are requested to attend the meeting compulsory.

Agenda of meeting –

- Committees introduction
- Discussion related to provision of raging in the college campus
- Discussion upon issues with the permission of the coordinator


Co-Ordinator
Anti Ragging Commi


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

कार्यालय, प्राचार्य,

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

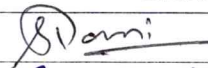
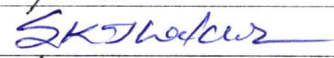
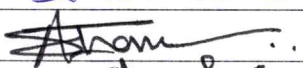
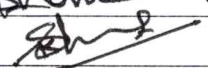
Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

<https://dpvipralawcollege.ac.in> – Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 992613873

पत्र क्रमांक / 2019

दिनांक 23 / 09 / 2019

ATTENDENCE

S. NO.	ATTENDENCE	SIGN
1	MISS. SUSHMA TIWARI	
2	MR. SANTOSH THAKUR	
3	MR. ALOK SHARMA	
4	MR. DHARMENDRA SHARMA	


Co-Ordinator
Anti Ragging Committee


Principal
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)


Principal
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

कार्यालय, प्राचार्य,

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

<https://dpvipralawcollege.ac.in> – Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 992613873

पत्र क्रमांक९...../2019

दिनांक 23/09/2019

Minutes of Meeting:

Agenda 1. Committee introduction.

Resolution:

All the member of the committee introduce themselves after that co-ordinator Miss. Sushma tiwari adressed all the member of the committee further she highlighted the objectives and functions of committee.

Agenda. 2. Discussion related to prohibition of raging in college campus.

Resolution:


All the committee member where glad as no raging case was reported in the campus till date and it was assured that in the future too they will be aware that no such case will be profound in the collage campus. For this they discussed that the students must be aware about their safty and feel free to complain if they face any problem.

Agenda 3. Discussions upon issue with the permission of the co-ordinator

Resolution:

As there was nothing more to discuss the meeting was consuled with vote of thanks.


Co-Ordinator
Anti Ragging Committee


Principal
PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

कार्यालय, प्राचार्य,

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)


<https://dpvipralawcollege.ac.in> – Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 992613873

पत्र क्रमांक९...../2019


दिनांक 23/09/2019

Action taken report of meeting held on Monday 23/09/2019

Sr. no.	Resolution in the meeting	Action taken for implication and outcome
Nil		


Principal
PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)


Co-Ordinator
Anti Ragging Committee


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)



कार्यालय, प्राचार्य,

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

<https://dpvipralawcollege.ac.in> – Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

पत्र क्रमांक 9 / 2020 दिनांक 21 / 01 / 2020

दिनांक 21 / 01 / 2020

NOTICE

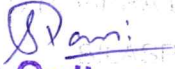
NOTICE


The meeting of anti-raging Committee has been scheduled on 23/01/2020 at 12:30 pm in meeting room.

You are requested to attend the meeting compulsory.

Agenda of meeting –

- Confirmation of meeting held on 23/09/2019.
- Discussion related to provision of raging in the college campus.


Co-Ordinator
Anti Ragging Committee


Principal
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
BILASPUR (C.G.)


Principal
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)



कार्यालय, प्राचार्य,

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

<https://dpvipralawcollege.ac.in> – Email– dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

पत्र क्रमांक9...../2020

दिनांक 23/01/2020

ATTENDENCE

S. NO.	ATTENDENCE	SIGN
1	MISS. SUSHMA TIWARI	
2	MR. SANTOSH THAKUR	
3	MR. ALOK SHARMA	
4	MR. DHARMENDRA SHARMA	

Co-Ordinator
Anti Ragging Committee

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)
BILASPUR (C.G.)

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

कार्यालय, प्राचार्य,

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

<https://dpvipralawcollege.ac.in> – Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No.– 9926165945, 9926138734

पत्र क्रमांक ...Q./2019

दिनांक 23/01/2020

Minutes of Meeting

- **Agenda 1.** Confirmation of meeting held on 23/09/2019.

Resolution:

Minutes of Meeting held on 23/09/2019 has been approved.

- **Agenda. 2.** Discussion related to provision of raging in the college campus.

Resolution

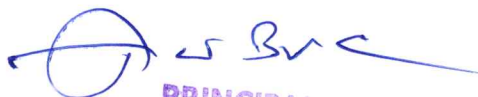
No ragging cases was reported in the campus which make the institute raging free, for which committee was glad and proud Special thanks was given to all the committee member to Miss. Sushma Tiwari for affords in this regard.



PRINCIPAL

D.P. VIPRA LAW COLLEGE

BILASPUR (C.G.)
Bilaspur (C.G.)



PRINCIPAL

D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)



कार्यालय, प्राचार्य,

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)


Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
<https://dpvipralawcollege.ac.in> – Email– dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734


पत्र क्रमांक 9 / 2020

दिनांक 23 / 01 / 2020

Action taken report of meeting held on Thursday 23/01/2020

Sr. no.	Resolution in the meeting	Action taken for implication and outcome
Nil		


Co-Ordinator
Anti Ragging Committee


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
BILASPUR (C.G.)


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

D.P. VIPRA LAW COLLEGE BILASPUR (C.G.)

Approved From BCI,
Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya Bilaspur (C.G.)



Academic Year 2020-21

D.P. Vipra Law College Bilaspur
Ashok Nagar, Seepat Road, Sarkanda, Bilaspur (C.G.)



कार्यालय, प्राचार्य,

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

<https://dpvipralawcollege.ac.in> – Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 992613873

पत्र क्रमांकQ...../2020

दिनांक 17/08/2020

- :: सूचना :: -

डी. पी. विप्र विधि महाविद्यालय समस्त प्राध्यापकों कर्मचारियों एवं छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि रैगिंग को रोकने एवं अनुशासन को बनाये रखने हेतु अनुशासन एवं एंटी रैगिंग (Anti Ragging) समिति का गठन किया गया है जिसके सदस्य निम्नानुसार है –

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. प्रो. कु. सुषमा तिवारी | संयोजक |
| 2. प्रो. संतोष ठाकुर | सदस्य |
| 3. श्री आलोक शर्मा (खेल अधिकारी) | सदस्य |
| 4. प्रो. धर्मेन्द्र शर्मा | सदस्य |

प्राचार्य

प्रतिलिपि

- माननीय अध्यक्ष महोदय प्रशासन समिति
- प्रो. कु. सुषमा तिवारी
- प्रो. संतोष ठाकुर
- श्री आलोक शर्मा (खेल अधिकारी)
- प्रो. धर्मेन्द्र शर्मा

प्राचार्य
डी.पी.विप्र. विधि महाविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)



कार्यालय, प्राचार्य,

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)


<https://dpvipralawcollege.ac.in> – Email– dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

पत्र क्रमांक 9 / 2020


दिनांक 20 / 08 / 2020

DECLARATION

Due to the COVID-19 pandemic, the anti-ragging committee did not convene during the 2020–2021 session.


Principal
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)
BILASPUR (C.G.)


Co-Ordinator
Anti Ragging Committee


Principal
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

D.P. VIPRA LAW COLLEGE BILASPUR (C.G.)

Approved From BCI,
Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya Bilaspur (C.G.)



Academic Year 2021-22

D.P. Vipra Law College Bilaspur
Ashok Nagar, Seepat Road, Sarkanda, Bilaspur (C.G.)



कार्यालय प्राचार्य

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI. Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
<https://dpvipralawcollege.ac.in> –Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

पत्र क्रमांक 9/2021

दिनांक 19/08/2021

- :: सूचना :: -

डी. पी. विप्र विधि महाविद्यालय समस्त प्राध्यापकों कर्मचारियों एवं छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि रैगिंग को रोकने एवं अनुशासन को बनाये रखने हेतु अनुशासन एवं एंटी रैगिंग (Anti Ragging) समिति का गठन किया गया है जिसके सदस्य निम्नानुसार है –

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. प्रो. कु. सुषमा तिवारी | संयोजक |
| 2. प्रो. संतोष ठाकुर | सदस्य |
| 3. श्री आलोक शर्मा (खेल अधिकारी) | सदस्य |
| 4. प्रो. धर्मेन्द्र शर्मा | सदस्य |

प्राचार्य


प्रतिलिपि

- माननीय अध्यक्ष महोदय प्रशासन समिति
- प्रो. कु. सुषमा तिवारी
- प्रो. संतोष ठाकुर
- श्री आलोक शर्मा (खेल अधिकारी)
- प्रो. धर्मेन्द्र शर्मा



PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)



कार्यालय प्राचार्य

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
<https://dpvipralawcollege.ac.in> –Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734


पत्र क्रमांक ९ / 2021

दिनांक 19/08/2021

– :: आदेश :: –

शैक्षणिक सत्र 2021–2022 हेतु एन्टी रैगिंग समिति का गठन किया जाता है जिसके सदस्य निम्न हैं जो 23.08.2021 से प्रभावशील होगी।

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. प्रो. कु. सुषमा तिवारी | संयोजक |
| 2. प्रो. संतोष ठाकुर | सदस्य |
| 3. श्री आलोक शर्मा (खेल अधिकारी) | सदस्य |
| 4. प्रो. धर्मेन्द्र शर्मा | सदस्य |


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)
डी.पी.विप्र. विधि महाविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)



कार्यालय प्राचार्य

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
<https://dpvipralawcollege.ac.in> – Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

पत्र क्रमांक 9 / 2021

दिनांक 23 / 08 / 2021

— :: Notice :: —

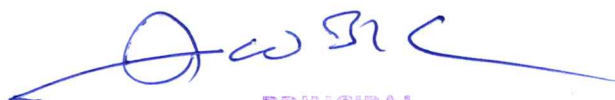
The meeting of Anti- Ragging Committee is scheduled on 25/08/2021, at 02:00 pm in principle office.

Agenda of meeting:

1. Introduction of session.
2. Discuss the measures made to prevent ragging in college.
3. Discussion of issues with the chairman permission.


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)
D.P.Vipra PG Law Collage Bilaspur c.g.


Co-Ordinator
Anti Ragging Committee


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)



कार्यालय प्राचार्य

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
<https://dpvipralawcollege.ac.in> – Email– dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

पत्र क्रमांक 9 / 2021

दिनांक 25 / 08 / 2021

Attendance

S. NO.	ATTENDANCE	SIGN
1	MISS. SUSHMA TIWARI	
2	MR. SANTOSH THAKUR	
3	MR. ALOK SHARMA	
4	MR. DHARMENDRA SHARMA	

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)
D.P.Vipra PG Law Collage Bilaspur c.g.

Co-Ordinator
Anti Ragging Committee

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)



कार्यालय प्राचार्य

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
<https://dpvipralawcollege.ac.in> – Email– dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

पत्र क्रमांक9..... / 2021

दिनांक 25 / 08 / 2021

Minutes of Meeting

Agenda. 1. Introduction of session.

Resolution:

All the members introduce themselves then miss. Sushma tiwari outlined the goals and purposes of the Anti-Ragging Committee.

Agenda. 2. Discuss the measures made to prevent ragging in college.


Resolution:

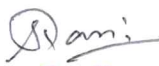
We inform them that if any instances of ragging are discovered, they will be subject to legal action in accordance with the law, even though up to this point, incidents of ragging have been reported or brought to the attention of the anti-ragging committee, which has made sure that senior-junior relationships are harmonious and the college is free of ragging.


Agenda. 3. Discussion of issues with the chairman permission.

Resolution:

As there was no issue to discuss, the meeting was concluded with the votes of thanks to the present member.


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)
D.P.Vipra PC Law College Bilaspur c.g.


Co-Ordinator
Anti Ragging Committee


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)



कार्यालय प्राचार्य

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
<https://dpvipralawcollege.ac.in> – Email– dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

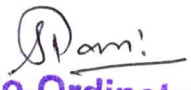
पत्र क्रमांक ९ / 2021


दिनांक 25 / 08 / 2021

Action taken report of meeting held on Wednesday 25/08/2021

Sr. no.	Resolution in the meeting	Action taken for implication and outcome
	Nil	


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)


Co-Ordinator
Anti Ragging Committee


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)



OFFICE OF THE PRINCIPAL D.P. Vipra Law College Bilaspur

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
<https://dpvipralawcollege.ac.in> –Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

Letter No. 005-A / 2022

Dated : 10 / 01 / 2022

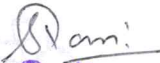
NOTICE

The meeting of anti-raging Committee has been scheduled on 12/01/2022 at 01:30 pm in staff room.

You are requested to attend the meeting compulsory.

Agenda of meeting :

- Confirmation of meeting held on 25/08/2021.
- Discussion related to provision of ragging in the campus.


Co-Ordinator
Anti Ragging Committee


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)



OFFICE OF THE PRINCIPAL


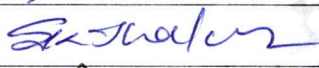
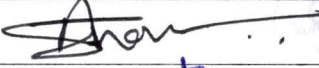

D.P. Vipra Law College Bilaspur

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
<https://dpvipralawcollege.ac.in> –Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

Letter No. 005-B / 2022

Dated : 12 / 01 / 2022

ATTENDENCE

S. NO.	ATTENDENCE	SIGN
1	MISS. SUSHMA TIWARI	
2	MR. SANTOSH THAKUR	
3	MR. ALOK SHARMA	
4	MR. DHARMENDRA SHARMA	


Co-Ordinator
Anti Ragging Committee


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

—: श्रद्धावान लभते ज्ञानम :—



OFFICE OF THE PRINCIPAL

D.P. Vipra Law College Bilaspur

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
<https://dpvipralawcollege.ac.in> Email - dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. - 9926165945, 9926138734

Letter No. 005-C / 2022 Dated : 13/01/2022

Dated : 12/01/2022

MINUTES OF MEETING

Agenda. 1. Confirmation of meeting held on 25/08/2021.

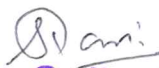
Resolution:

In minutes of last meeting which held on 25/08/2021 was read and unanimously approved.

Agenda. 2. Discussion related to provision of ragging in the campus.

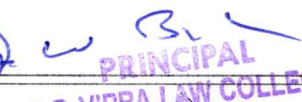
Resolution:

All the committee members were feeling proud and happy to state that no any ragging case is reported in campus which make it clean and institution is ragging free. All the members were greatful and gave special thanks to Miss. Sushma Tiwari for her efforts in this regards.


Co-Ordinator
Anti Ragging Committee

Principal


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

- श्रीदावान लभते ज्ञानम् :-



OFFICE OF THE PRINCIPAL D.P. Vipra Law College Bilaspur


Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
<https://dpvipralawcollege.ac.in> –Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

Letter No. 005-D / 2022

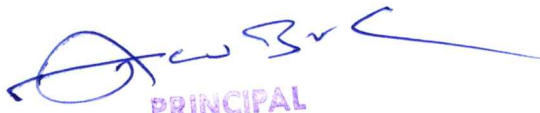
Dated : 12 / 01 / 2022

Action taken report of meeting held on Wednesday 12/01/2022

Sr. no.	Resolution in the meeting	Action taken for implication and outcome
	Nil	


Co-Ordinator
Anti Ragging Committee


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

—: श्रद्धावान लभते ज्ञानम् —



OFFICE OF THE PRINCIPAL D.P. Vipra Law College Bilaspur

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
<https://dpvipralawcollege.ac.in> –Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

Letter No. 121-A / 2022

Dated : 02 / 06 / 2022


NOTICE


The meeting of anti-raging Committee has been scheduled on 06/06/2022 at 12:30 pm in principal room.


You are requested to attend the meeting compulsory.

Agenda of meeting:

- Confirmation minutes of meeting held on 12/01/2022.
- Discussion related to provision of Ragging.


Principal
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)


Co-Ordinator
Anti Ragging Committee


Principal
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)



OFFICE OF THE PRINCIPAL

D.P. Vipra Law College Bilaspur

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
<https://dpvipralawcollege.ac.in> – Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

Letter No. 164-A / 2022

Dated : 06 / 06 / 2022

ATTENDENCE

S. NO.	ATTENDENCE	SIGN
1	MISS. SUSHMA TIWARI	
2	MR. SANTOSH THAKUR	
3	MR. ALOK SHARMA	
4	MR. DHARMENDRA SHARMA	

Principal
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

Co-Ordinator
Anti Ragging Committee

Principal
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

—: श्रद्धावान लभते ज्ञानम् —



OFFICE OF THE PRINCIPAL D.P. Vipra Law College Bilaspur

Approved from BCI, Affiliated to AtalBihariVajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
<https://dpvipralawcollege.ac.in> –Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

Letter No. Q./2022

Dated : 06/06/2022

Minutes of Meeting

Agenda 1. Confirmation minutes of meeting held on 12/01/2022.

Resolution:

In minutes of last meeting which held on 12/01/2022 was read and unanimously approved.

Agenda 2. Discussion related to provision of Ragging.

Resolution:

After knowing that no ragging cases has been reported in the premises all the committee members were very happy which make the institution ragging free. All the member was giving special thanks to Miss. Sushma Tiwari for her efforts in this regard.

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)



OFFICE OF THE PRINCIPAL

D.P. Vipra Law College Bilaspur

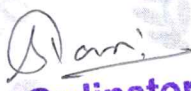
Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
<https://dpvipralawcollege.ac.in> –Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

Letter No. 164-C / 2022 Dated : 06/06/2022

Dated : 06 / 06 / 2022

Action taken report of meeting held on Monday 06/06/2022

Sr. no.	Resolution in the meeting	Action taken for implication and outcome
	Nil	


Co-Ordinator
Anti Ragging Committee


Principal
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

—: श्रद्धावान लभते ज्ञानम् —

D.P. VIPRA LAW COLLEGE BILASPUR (C.G.)

Approved From BCI,
Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya Bilaspur (C.G.)



Academic Year 2022-23

D.P. Vipra Law College Bilaspur
Ashok Nagar, Seepat Road, Sarkanda, Bilaspur (C.G.)



OFFICE OF THE PRINCIPAL D.P. Vipra Law College Bilaspur

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
<https://dpvipralawcollege.ac.in> –Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

Letter No. 299-A / 2022

Dated : 05 / 09 / 2022

- :: सूचना :: -

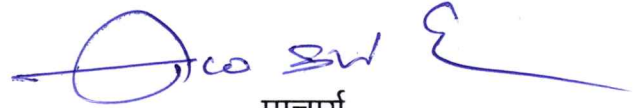
डी. पी. विप्र विधि महाविद्यालय समस्त प्राध्यापकों कर्मचारियों एवं छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि रैगिंग को रोकने एवं अनुशासन को बनाये रखने हेतु अनुशासन एवं एंटी रैगिंग (Anti Ragging) समिति का गठन किया गया है जिसके सदस्य निम्नानुसार है –

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. प्रो. कु. सुषमा तिवारी | संयोजक |
| 2. प्रो. संतोष ठाकुर | सदस्य |
| 3. श्री आलोक शर्मा (खेल अधिकारी) | सदस्य |
| 4. प्रो. धर्मेन्द्र शर्मा | सदस्य |

प्राचार्य

प्रतिलिपि

- माननीय अध्यक्ष महोदय प्रशासन समिति
- प्रो. कु. सुषमा तिवारी
- प्रो. संतोष ठाकुर
- श्री आलोक शर्मा (खेल अधिकारी)
- प्रो. धर्मेन्द्र शर्मा



प्राचार्य

डी.पी.विप्र. विधि महाविद्यालय,

बिलासपुर (छ.ग.)
Bilaspur (C.G.)


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

—: श्रद्धावान लभते ज्ञानम :-



OFFICE OF THE PRINCIPAL

D.P. Vipra Law College Bilaspur

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
https://dpvipralawcollege.ac.in – Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

Letter No. 299-B / 2022

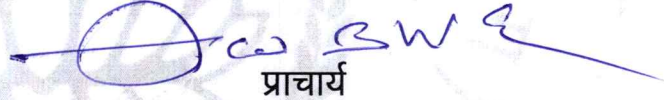
Dated : 05 / 09 / 2022

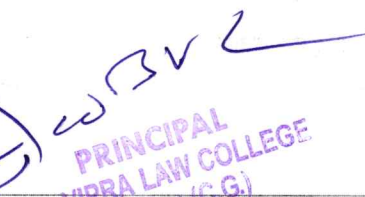
– :: आदेश :: –

शैक्षणिक सत्र 2022–2023 हेतु एन्टी रैगिंग समिति का गठन किया जाता है जिसके सदस्य निम्न हैं जो 06.09.2022 से प्रभावशील होगी।

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. प्रो. कु. सुषमा तिवारी | संयोजक |
| 2. प्रो. संतोष ठाकुर | सदस्य |
| 3. श्री आलोक शर्मा (खेल अधिकारी) | सदस्य |
| 4. प्रो. धर्मेन्द्र शर्मा | सदस्य |

प्राचार्य
डी.पी.वि. विधि महाविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)


प्राचार्य
डी.पी.वि. विधि महाविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)
PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)



OFFICE OF THE PRINCIPAL

D.P. Vipra Law College Bilaspur

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
<https://dpvipralawcollege.ac.in> –Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

Letter No. 300-B / 2022

Dated : 07 / 09 / 2022

NOTICE

The meeting of anti-raging Committee has been scheduled on 09/09/2022 at 01:30 pm in principal room.

You are requested to attend the meeting compulsory.

Agenda of meeting:

- Introductory session.
- Discussion regarding to regular meeting with students.
- Discussion on issue with the permission of the Co-codenter.


Co-Ordinator
Anti Ragging Committee


Principal
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)


Principal
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

—: श्रद्धावान लभते ज्ञानम्



OFFICE OF THE PRINCIPAL

D.P. Vipra Law College Bilaspur

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
<https://dpvipralawcollege.ac.in> –Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

Letter No. 301-A / 2022

Dated : 09 / 09 / 2022

ATTENDANCE

S. NO.	ATTENDENCE	SIGN
1	MISS. SUSHMA TIWARI	
2	MR. SANTOSH THAKUR	
3	MR. ALOK SHARMA	
4	MR. DHARMENDRA SHARMA	

Co-Ordinator
Anti Ragging Committee

Principal
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

Principal
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)



OFFICE OF THE PRINCIPAL

D.P. Vipra Law College Bilaspur

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
<https://dpvipralawcollege.ac.in> -Email - dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. - 9926165945, 9926138734

Letter No. 301-B / 2022 Dated 09/09/2022

Dated : 09 / 09 / 2022

Minutes of Meeting

Agenda. 1. Introductory session.

Resolution:

All the committee member introduce themselves then the co-ordenater Miss. Sushma Tiwari addressed the committee and highlighted the objectives and functions of the Anti- Ragging committee.

Agenda. 2. Discussion regarding to regular meeting with students.

Resolution:

The committee is asked to meet with the students on a regular basis and advise the senior students to be kind and supportive to their juniors. They also inform the junior students that ragging is illegal and that they should be aware of this. If they encounter any problems of this nature, they should notify the anti-ragging committee members.


Agenda .3. Discussion on issue with the permission of the co- ordenater.

Resolution:

As there was no issue to discuss, the meeting was concluded with the vote of thanks to the present members.


Co-Ordinator
Anti Ragging Committee

Principal


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)
शुद्धाचारं लभते ज्ञानम् :-



OFFICE OF THE PRINCIPAL

D.P. Vipra Law College Bilaspur

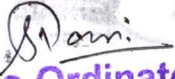
Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
<https://dpvipralawcollege.ac.in> – Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734


Letter No. 301-C / 2022

Dated : 09 / 09 / 2022

Action taken report of meeting held on Friday 09/09/2022

Sr. no.	Resolution in the meeting	Action taken for implication and outcome
	Nil	


Co-Ordinator
Anti Ragging Committee


Principal
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)



Principal
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

—: श्रद्धावान लभते ज्ञानम :—



WOMEN GRIEVANCE CELL

(ANTI-SEXUAL HARASSMENT)


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

D.P. VIPRA LAW COLLEGE BILASPUR (C.G.)

Approved From BCI,
Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya Bilaspur (C.G.)



Academic Year 2018-19

D.P. Vipra Law College Bilaspur
Ashok Nagar, Seepat Road, Sarkanda, Bilaspur (C.G.)

कार्यालय, प्राचार्य, डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
Ph. 07752-329260, 210760, E-Mail-dpvlawprincipal@yahoo.com www.dpvipralawcollege.com


पत्र क्रमांक...Q./2018


दिनांक 10/09/2018

— :: आदेश :: —

शैक्षणिक सत्र 2018-2019 हेतु महिला उत्पीड़न समिति का गठन किया जाता है जिसके सदस्य निम्न हैं जो 14.09.2018 से प्रभावशील होगी

1. प्रो. कु. सुषमा तिवारी	संयोजक
2. श्री जी.पी कौशिक	सदस्य
3. डॉ. हीराचंद पटेल	सदस्य
4. डॉ. इंदुबल मिन्ज	सदस्य
5. प्रो. अनिता टण्डन	सदस्य
6. नम्रता परिछा	सदस्य


PRINCIPAL प्राचार्य
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)


PRINCIPAL प्राचार्य
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

कार्यालय, प्राचार्य,

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

Ph. 07752-329260, 210760, E-Mail-dpvlawprincipal@yahoo.com www.dpvipralawcollege.com

पत्र क्रमांक ...Q/2018

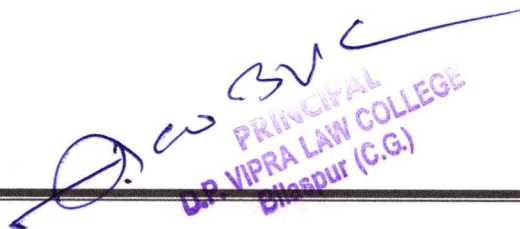
दिनांक 06/08/2018

EXECUTIVE COMMITTEE (2018-2019)

1. Ku. Sushma Tiwari
2. Mr. G.P. Kaushik
3. Dr. Hirachand Patel
4. Dr. Indubala Minj
5. Ku. Anita Tandon
6. Ku. Namrata Parichha



PRINCIPAL
PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)



PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

कार्यालय, प्राचार्य, डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

Ph. 07752-329260, 210760, E-Mail-dpvlawprincipal@yahoo.com www.dpvipralawcollege.com

पत्र क्रमांक ..Q. / 2018

दिनांक 25 / 09 / 2018

NOTICE

All members of the women's grievance cell committee are informed that the committee will meet on Saturday, September 29, 2019 at 2:00 p.m. in the conference room.

The meeting's Agenda:

1. Committee introduction.
2. Talk about the harassment of girls on college campuses
3. Talk about holding conferences and seminars on women's rights.

We kindly ask that you find time to attend the meeting.



PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)



PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

कार्यालय, प्राचार्य, डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

Ph. 07752-329260, 210760, E-Mail-dpvlawprincipal@yahoo.com www.dpvipralawcollege.com

पत्र क्रमांक ..Q. / 2018

दिनांक 29 / 09 / 2018

MINUTES OF MEETING

Agenda 1:

committee introduction. Result: Each committee member gave a brief introduction. Miss Sushma Tiwari provided an overview of the committee's roles and responsibilities.

Agenda 2:


Talk about female bullying on college campuses. Result: The committee deliberated over the different ramifications of harassing girls.


Agenda 3.

Talk about holding conferences and seminars on women's rights Result: Committee members talked about holding conferences and seminars on women's rights to educate female and girl faculty members about their rights.

It was decided after much debate to exhibit the Anti-Women's Grievances Cell board on the college campus.

A vote of gratitude was taken to adjourn the meeting as there were no matters to discuss.


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

कार्यालय, प्राचार्य, डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

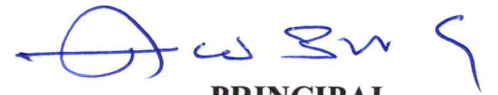
Ph. 07752-329260, 210760, E-Mail-dpvlawprincipal@yahoo.com www.dpvipralawcollege.com

पत्र क्रमांक ..Q. / 2018

दिनांक 29/09/2018

Action taken Report of Meeting on Saturday 29/09/2019

Sr. no.	Resolution in the meeting	Action taken for implementation & outcomes
NIL		


PRINCIPAL
PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

D.P. VIPRA LAW COLLEGE BILASPUR (C.G.)

Approved From BCI,
Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya Bilaspur (C.G.)



Academic Year 2019-20

D.P. Vipra Law College Bilaspur
Ashok Nagar, Seepat Road, Sarkanda, Bilaspur (C.G.)

कार्यालय, प्राचार्य,

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

<https://dpvipralawcollege.ac.in> – Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 992613873

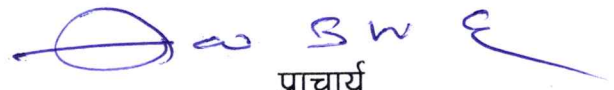
पत्र क्रमांक९...../2019

दिनांक 07/09/2019

– :: आदेश :: –

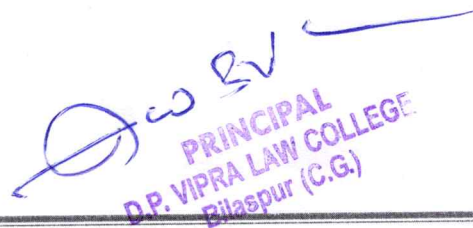
शैक्षणिक सत्र 2019–2020 हेतु महिला उत्पीड़न समिति का गठन किया जाता है जिसके सदस्य निम्न हैं जो 09.09.2019 से प्रभावशील होगी।

1. प्रो. कु. सुषमा तिवारी	संयोजक
2. श्री जी. पी. कौशिक	सदस्य
3. डॉ. हीराचंद पटेल	सदस्य
4. डॉ. इन्दुबाला मिंज	सदस्य
5. प्रो. अनिता टण्डन	सदस्य
6. प्रो. नम्रता परिछा	सदस्य



प्राचार्य

डी.पी.विप्र विधि महाविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)



PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

कार्यालय, प्राचार्य,

डी.पी. विप्रविधि महाविद्यालय, सीपतरोड, अशोकनगरबिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to AtalBihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

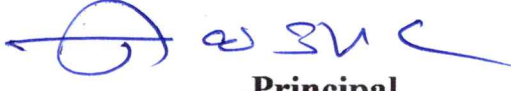
<https://dpvipralawcollege.ac.in>– Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 992613873

पत्र क्रमांक ...Q/2019

दिनांक 09/09/2019

EXECUTIVE COMMITTEE (2019-20)

1. Ku. Sushma Tiwari
2. Mr. G.P. Kaushik
3. Dr. Hirachand Patel
4. Dr. Indubala Minj
5. Ku. Anita Tandon
6. Ku. Namrata Parichha


Principal
PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)


Principal
PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

कार्यालय, प्राचार्य, डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
<https://dpvipralawcollege.ac.in> – Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 992613873

पत्र क्रमांक९...../2019

दिनांक 20/09/2019

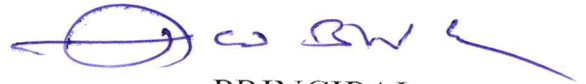
NOTICE

It is inform to all the committee members of women Grievance cell that the meeting of the committee is scheduled on Wednesday, 25/09/2019 at 2:00 p.m. at the meeting room.

Agenda of the meeting:

1. Introduction of committee.
2. Discussion regarding ragging of girl's in the college campus.
3. Discussion regarding the organization of seminars/conferences on women rights.


You are requested to make it convenient to attend the meeting.



PRINCIPAL
PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)



Co-Ordinator
Woman Grievance
Cell



PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

कार्यालय, प्राचार्य,

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

<https://dpvipralawcollege.ac.in> – Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 992613873

पत्र क्रमांक९..... / 2019

दिनांक 25 / 09 / 2019

MINUTES OF MEETING

Agenda 1. Introduction of committee.

Resolution:

All the member of the committee introduced themselves. Miss. Sushma Tiwari gave overview about roles and responsibilities of the committee.

Agenda 2. Discussion regarding ragging of girls in the college campus.

Resolution :

Committee discussed regarding various consequences of ragging of girls.

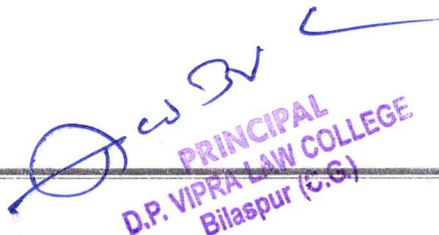
Agenda 3. Discussion regarding the organization of seminars/conferences on women rights.

Resolution :

Committee discussed regarding the organization of seminars/conferences on women rights to aware girl and female faculties for their rights.

Through discussion was made and it is resolved to display board of Anti women's Grievances Cell in the college campus.

As there were no issues to discuss, meeting concluded with vote of thanks to all.


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

कार्यालय, प्राचार्य,

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

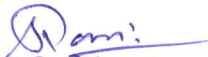
<https://dpvipralawcollege.ac.in> – Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 992613873

पत्र क्रमांक०...../2019

दिनांक 25/09/2019

Action taken Report of Meeting on Wednesday 25/09/2019

Sr. no.	Resolution in the meeting	Action taken for implementation & outcomes
	NIL	


Co-Ordinator
Woman Grievance
Cell


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

कार्यालय, प्राचार्य,

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

<https://dpvipralawcollege.ac.in> – Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 992613873

पत्र क्रमांक९...../2019

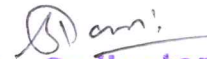
दिनांक 11/12/2019

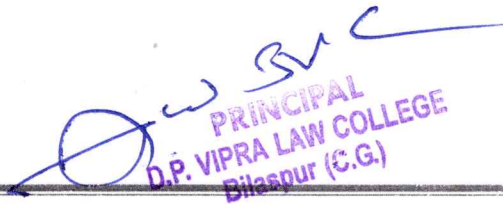
NOTICE

It is inform to all the committee members of women Grievance cell that the students of B.A.LL.B 2nd sem. Face difficulty while submitting the examination form therefore a meeting has to be held on the above mention subject. Presents of all the members are compulsory on Friday, 13/12/2019 at 01:00 p.m. at the meeting room.



PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)


Co-Ordinator
Woman Grievance
Cell



PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

कार्यालय, प्राचार्य,

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

<https://dpvipralawcollege.ac.in> – Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 992613873

पत्र क्रमांक९...../2019

दिनांक 13/12/2019

MINUTES OF MEETING

Agenda 1. Introduction of committee.

Resolution:

All the member of the committee introduced themselves. Miss. Sushma Tiwari gave overview roles and responsibilities of the committee.

Agenda 2. Discussion regarding the problem faced by students during form submission.

Resolution :

Committee discussed regarding various problem faced by girls during the submission. The problem must be discussed with the principal so that it can be resolved as soon as possible.

As there were no issues to discuss, meeting concluded with vote of thanks to all.


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

कार्यालय, प्राचार्य,

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

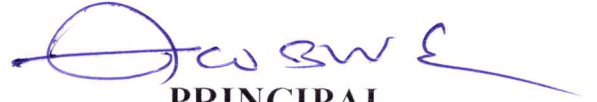
<https://dpvipralawcollege.ac.in> – Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 992613873

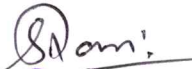
पत्र क्रमांक९...../2019


दिनांक 11/12/2019

Action taken Report of Meeting on Friday 13/12/2019

Sr. no.	Resolution in the meeting	Action taken for implementation & outcomes
	The problem has been resolved by assuring them to make other row for girls as soon as possible.	


PRINCIPAL
PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)


Co-Ordinator
Woman Grievance
Cell


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

D.P. VIPRA LAW COLLEGE BILASPUR (C.G.)

Approved From BCI,
Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya Bilaspur (C.G.)



Academic Year 2020-21

D.P. Vipra Law College Bilaspur
Ashok Nagar, Seepat Road, Sarkanda, Bilaspur (C.G.)



कार्यालय, प्राचार्य,

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

<https://dpvipralawcollege.ac.in> – Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 992613873

पत्र क्रमांक ७ / 2020

दिनांक 20/08/2020

– :: आदेश :: –

शैक्षणिक सत्र 2020–2021 हेतु महिला उत्पीड़न समिति का गठन किया जाता है जिसके सदस्य निम्न हैं जो 21.08.2020 से प्रभावशील होगी।

- | | |
|---------------------------|--------|
| 1. प्रो. कु. सुषमा तिवारी | संयोजक |
| 2. श्री जी. पी. कौशिक | सदस्य |
| 3. डॉ. हीराचंद पटेल | सदस्य |
| 4. डॉ. इन्दुबाला मिंज | सदस्य |
| 5. प्रो. अनिता टण्डन | सदस्य |


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
डी.पी.विप्र विधि महाविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)



कार्यालय, प्राचार्य,

डी.पी. विप्रविधि महाविद्यालय, सीपतरोड, अशोकनगरबिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to AtalBihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

<https://dpvipralawcollege.ac.in>– Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 992613873

पत्र क्रमांक ...Q / 2020

दिनांक 21 / 08 / 2020

EXECUTIVE COMMITTEE (2020-2021)

1. Ku. Sushma Tiwari
2. Mr. G.P. Kaushik
3. Dr. Hirachand Patel
4. Dr. Indubala Minj
5. Ku. Anita Tandon
6. Ku. Namrata Parichha

Principal

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)



कार्यालय, प्राचार्य,

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

<https://dpvipralawcollege.ac.in> – Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 992613873

पत्र क्रमांक 9 / 2020

दिनांक 21 / 08 / 2020

DECLARATION

This meeting of Anti-sexual harassment committee was not held during the session 2020-2021 due to COVID-19 pandemic.

Principal
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

Co-Ordinator
Woman Grievance
Cell

Principal
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

D.P. VIPRA LAW COLLEGE BILASPUR (C.G.)

Approved From BCI,
Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya Bilaspur (C.G.)



Academic Year 2021-22

D.P. Vipra Law College Bilaspur
Ashok Nagar, Seepat Road, Sarkanda, Bilaspur (C.G.)



कार्यालय प्राचार्य

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
<https://dpvipralawcollege.ac.in> –Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

पत्र क्रमांक ९ / 2021

दिनांक 12 / 11 / 2021

— :: आदेश :: —

शैक्षणिक सत्र 2021–2022 हेतु महिला उत्पीड़न समिति का गठन किया जाता है जिसके सदस्य निम्न हैं जो 12.11.2021 से प्रभावशील होगी।

1. प्रो. कु. सुषमा तिवारी	संयोजक
2. श्री जी. पी. कौशिक	सदस्य
3. डॉ. हीराचंद पटेल	सदस्य
4. डॉ. इन्दुबाला मिंज	सदस्य
5. प्रो. अनिता टण्डन	सदस्य
6. प्रो. नम्रता परिछा	सदस्य


प्राचार्य
डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)



कार्यालय प्राचार्य

डी.पी. विप्रविधि महाविद्यालय, सीपतरोड, अशोकनगरबिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
<https://dpvipralawcollege.ac.in>—Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

पत्र क्रमांक...Q/2021

दिनांक 12/11/2021

EXECUTIVE COMMITTEE (2021-2022)

1. Ku. Sushma Tiwari
2. Mr. G.P. Kaushik
3. Dr. Hirachand Patel
4. Dr. Indubala Minj
5. Ku. Anita Tandon
6. Ku. Namrata Parichha

Principal

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)



कार्यालय प्राचार्य

डी.पी. विप्रविधि महाविद्यालय, सीपतरोड, अशोकनगरबिलासपुर (छ.ग.)


Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
<https://dpvipralawcollege.ac.in>—Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

पत्र क्रमांक Q...../2021

दिनांक 10/03/2022

NOTICE

This is to inform all the committee members of women grievance cell that the students of B.A. L.L.B. 3rd semester facing difficulty while submitting the final examination answer sheet therefore a meeting has to be conducted on the above mention subject. Presence of all the members is compulsory on Friday, 11/03/2022 at 02:00 PM at the meeting room.


Principal
PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)


Principal
PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)



कार्यालय प्राचार्य

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
<https://dpvipralawcollege.ac.in> –Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

पत्र क्रमांक ९/2022

दिनांक 11/03/2022

MINUTES OF MEETING

Agenda 1. Introduction of committee.

Resolution:

The session was started by introducing the committee members. Miss. Sushma Tiwari gave overview roles and responsibilities of the committee.

Agenda 2. Discussion regarding the problem facing by students during submission of final examination answer sheet.

Resolution :

Committee discussed regarding various problems faced by girls students due to the submission of final examination answer sheet, and concluded that the problem must be discusses with the principal and should be resolved as soon as possible.

As there were no issues to discuss, meeting concluded with vote of thanks to all.


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)



कार्यालय प्राचार्य

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

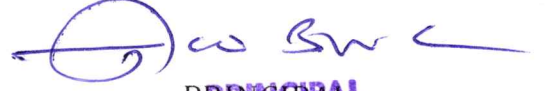
Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
<https://dpvipralawcollege.ac.in> –Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

पत्र क्रमांक ०९ / 2022

दिनांक 11 / 03 / 2022

Action taken Report of Meeting on Thursday 11/03/2022

Sr. no.	Resolution in the meeting	Action taken for implementation & outcomes
	The problem has been resolved by assuring them to make other row for girl's students and female Asst. Prof. will collect their answer sheet as soon as possible.	


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)


Co-Ordinator
Woman Grievance
Cell


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

D.P. VIPRA LAW COLLEGE BILASPUR (C.G.)

Approved From BCI,
Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya Bilaspur (C.G.)



Academic Year 2022-23

D.P. Vipra Law College Bilaspur
Ashok Nagar, Seepat Road, Sarkanda, Bilaspur (C.G.)



OFFICE OF THE PRINCIPAL D.P. Vipra Law College Bilaspur

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
<https://dpvipralawcollege.ac.in> –Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

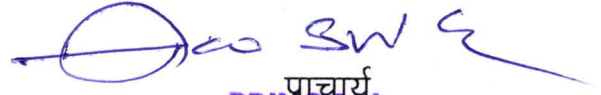
Letter No. 9 /2022


Dated : 02 /09 /2022

– :: आदेश :: –

शैक्षणिक सत्र 2022–2023 हेतु महिला उत्पीड़न समिति का गठन किया जाता है जिसके सदस्य निम्न हैं जो 03.09.2022 से प्रभावशील होगी।

- | | |
|---------------------------|--------|
| 1. प्रो. कु. सुषमा तिवारी | संयोजक |
| 2. श्री जी. पी. कौशिक | सदस्य |
| 3. डॉ. हीराचंद पटेल | सदस्य |
| 4. डॉ. इन्दुबाला मिंज | सदस्य |
| 5. प्रो. अनिता टण्डन | सदस्य |
| 6. प्रो. नम्रता परिछा | सदस्य |


प्राचार्य
PRINCIPAL
डी.पी.विप्रा विधि महाविद्यालय,
Bilaspur (C.G.)
बिलासपुर (छ.ग.)


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)



OFFICE OF THE PRINCIPAL

D.P. Vipra Law College Bilaspur


Approved from BCI, Affiliated to AtalBihariVajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
<https://dpvipralawcollege.ac.in> –Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

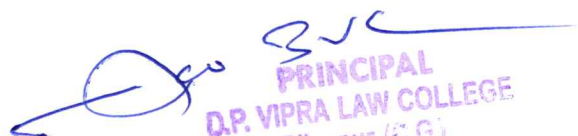
Letter No. Q./2022

Dated: 05/09/2022

EXECUTIVE COMMITTEE (2022-2023)

1. Ku. Sushma Tiwari
2. Mr. G.P. Kaushik
3. Dr. Hirachand Patel
4. Dr. Indubala Minj
5. Ku. Anita Tandon
6. Ku. Namrata Parichha


Principal
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)


Principal
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)



कार्यालय प्राचार्य

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
<https://dpvipralawcollege.ac.in> –Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

पत्र क्रमांक Q.... / 2022

दिनांक 15 / 09 / 2022


NOTICE

It is to inform you that a meeting of the Women Grievance Cell Committee has been scheduled on Monday, September 19, 2022, at 03:00 PM in the meeting room.

The agenda for the meeting is as follows:

1. Introduction of committee members.
2. Discussion regarding ragging incidents involving girls in the college campus.
3. Discussion on organizing seminars/conferences on women's rights.

All members are requested to make every effort to attend the meeting.


Principal
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)



कार्यालय प्राचार्य

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
<https://dpvipralawcollege.ac.in> –Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

पत्र क्रमांक Q.... / 2022

दिनांक 19/09/2022

MINUTES OF MEETING

Agenda 1: Introduction of committee members

Resolution:

The committee members introduced themselves and acknowledged their commitment to addressing the concerns of female students and promoting gender equality on campus.

Agenda 2: Discussion regarding ragging incidents involving girls in the college campus

Resolution:

The committee resolved to:

1. Establish a robust reporting mechanism for ragging incidents and ensure prompt action.
2. Collaborate with the college administration to strengthen security measures on campus.

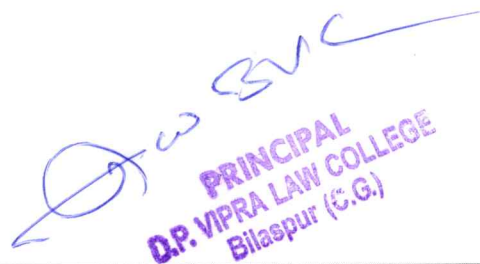
Agenda 3: Discussion on organizing seminars/conferences on women's rights

Resolution:

The committee resolved to:

1. Organize a session on "Women's Rights and the Law".
2. Collaborate with women's rights organizations and NGOs to conduct workshops and training sessions for female students.

The meeting concluded with thanking all the members for their active participation and valuable contributions. The committee agreed to meet regularly to monitor the progress of the resolutions and address any emerging concerns.


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)



कार्यालय प्राचार्य

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

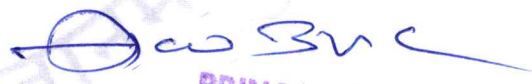
Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
<https://dpvipralawcollege.ac.in> –Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

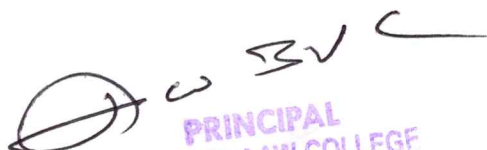
पत्र क्रमांक Q...../2022

दिनांक 19/09/2022

Action Taken Report of Meeting on Monday, 19/09/2022

Sr. No.	Resolution in the meeting	Action Taken for Implementation & Outcomes
		NIL


Principal
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

—: श्रद्धावान लभते ज्ञानम् —



**GRIEVANCE REDRESSAL
COMMITTEE
(STUDENT REDRESSAL COMMITTEE)**

**PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)**

D.P. VIPRA LAW COLLEGE BILASPUR (C.G.)

Approved From BCI,
Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya Bilaspur (C.G.)



Academic Year 2018-19

D.P. Vipra Law College Bilaspur
Ashok Nagar, Seepat Road, Sarkanda, Bilaspur (C.G.)

कार्यालय, प्राचार्य,

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

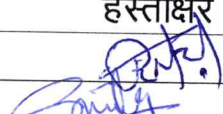

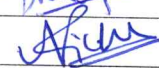
Ph. 07752-329260, 210760, E-Mail-dpvlawprincipal@yahoo.com www.dpvipralawcollege.com


पत्र क्रमांक९...../2018

दिनांक 07/08/2018

आदेश

शैक्षणिक सत्र 2018-19 हेतु शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया जाता है, जिसके अंतर्गत समन्वयक एवं सदस्य निम्नानुसार है, जो 10/08/2018 से प्रभावशील होगी।

क्रमांक	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
01	टी. आर. पटेल	समन्वयक / प्रभारी	
02	अनिता टंडन	सदस्य	
03	नम्रता परीछा	सदस्य	


प्राचार्य
PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

कार्यालय, प्राचार्य,

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

Ph. 07752-329260, 210760, E-Mail-dpvlawprincipal@yahoo.com www.dpvipralawcollege.com

पत्र क्रमांक/2018

दिनांक 16/08/2018

Notice

On August 20, 2018, at 1:00 p.m., the Grievance Redressal Committee will convene at the Principal Office.

The schedule for the meeting:

1. Summarizes the objectives and responsibilities of the Committee.
2. Discuss any challenges that are raised.

Please make time to attend the meeting, as requested.



Principal

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)



PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

कार्यालय, प्राचार्य,

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)



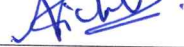
Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

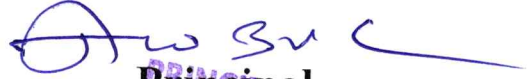
Ph. 07752-329260, 210760, E-Mail-dpvlawprincipal@yahoo.com www.dpvipralawcollege.com

पत्र क्रमांक९...../2018

दिनांक 20/08/2018

ATTENDENCE

S. No.	Name	Signature
1.	T.R.Patel	
2.	Anita Tandon	
3.	Namrata Parichha	


Principal
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)


Principal
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

कार्यालय, प्राचार्य,

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

Ph. 07752-329260, 210760, E-Mail-dpvlawprincipal@yahoo.com www.dpvipralawcollege.com

पत्र क्रमांक९...../2018

दिनांक 20/08/2018

Minutes of meeting

Agenda 1.

The meeting of introduction

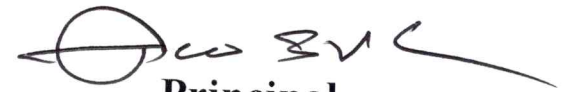
Resolution: T.R. Patel, the coordinator of the group, gave a description of the committee's responsibilities.

Agenda 2:

Discuss the issues that were found on college campuses.

Resolution:

The committee discussed a number of student problems that were brought to their attention about the committee's offices, libraries, infrastructure, and other issues. T.R. Patel then brought up the issue of the filthy restrooms in the Vijay Kumar Building and requested that Principal Sir take the appropriate action. There was nothing else to discuss, therefore the meeting was adjourned with a vote of thanks.



Principal

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)



PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

कार्यालय, प्राचार्य,

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

Ph. 07752-329260, 210760, E-Mail-dpvlawprincipal@yahoo.com www.dpvipralawcollege.com

पत्र क्रमांक ...९...../2018

दिनांक 20/08/2018


Action Taken

REPORT ON ACTIONS TAKEN AT THE MONDAY AUGUST 20,2018

Sr. No.	Resolution in the meeting	Action Taken for Implementation & Outcomes
	The principal's request was unanimously approved, and the building's Restroom and Library will be used hygienically very soon. for the pupils.	


Principal

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

D.P. VIPRA LAW COLLEGE BILASPUR (C.G.)

Approved From BCI,
Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya Bilaspur (C.G.)



Academic Year 2019-20

D.P. Vipra Law College Bilaspur
Ashok Nagar, Seepat Road, Sarkanda, Bilaspur (C.G.)

कार्यालय, प्राचार्य,

डी.पी. विप्रविधि महाविद्यालय, सीपतरोड, अशोकनगरबिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to AtalBihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

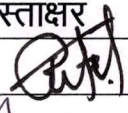
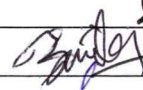
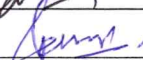
<https://dpvipralawcollege.ac.in> – Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 992613873

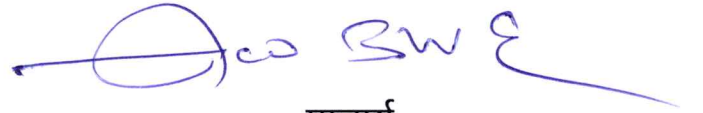
पत्र क्रमांक .Q/2019

दिनांक 03/07/2019

आदेश

शैक्षणिक सत्र 2019-20 हेतु शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया जाता है, जिसके अंतर्गत समन्वयक एवं सदस्य निम्न हैं, जो 08/07/2019 से प्रभावशील होगी।

क्रमांक	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
01	टी. आर. पटेल	समन्वयक / प्रभारी	
02	अनिता टंडन	सदस्य	
03	रानी गोरख	सदस्य	



प्राचार्य
PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)



PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

कार्यालय, प्राचार्य, डी.पी. विप्रविधि महाविद्यालय, सीपतरोड, अशोकनगरबिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to AtalBihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

<https://dpvipralawcollege.ac.in>– Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 992613873

पत्र क्रमांक .Q/2019

दिनांक 12/07/2019

NOTICE

This meeting of Grievance Redresser Committee is scheduled on 14 August 2019 at 2.00 p.m. in principal office.

Agenda of the meeting

1. Introduction and Roll of the committee
2. Discussion regarding grievances found in the college campus

You are requested to make it convenient to attend the meeting.


Co-Ordinator
Grievance Redressal
Committee


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

कार्यालय, प्राचार्य,

डी.पी. विप्रविधि महाविद्यालय, सीपतरोड, अशोकनगरबिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to AtalBihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

<https://dpvipralawcollege.ac.in>– Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 992613873

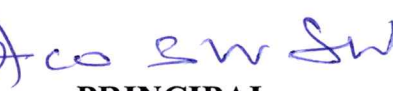
पत्र क्रमांक .Q/2019


दिनांक 14/08/2019

Attendance

S. No.	Name	Signature
1.	T.R.Patel	
2.	Anita Tandon	
3.	Rani Garakh	


Co-Ordinator
Grievance Redressal
Committe


PRINCIPAL
PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

कार्यालय, प्राचार्य,

डी.पी. विप्रविधि महाविद्यालय, सीपतरोड, अशोकनगरबिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to AtalBihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
https://dpvipralawcollege.ac.in- Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 992613873

प्रत्र क्रमांक- Q/2019

दिनांक 14/08/2019

Minutes of Meeting

Agenda 1. Committee Introduction.

Resolution:

Each member introduced himself, and T.R. Patel provided a summary of the committee's duties.

Agenda 2. A discussion of compacts report on college.

Resolution:

The committee talked about a range of issues pertaining to students that included office pertaining to student's that included office, library, infrastructure, and academic issues. The committee was made aware of these issues.

The issue raised by students was brought to light by T.R. Patel. The issue is that the classes Bharat Kausik building are messy, and since the blackboards are not easily seen, they need to be painted or a green board needs to be painted or a green board needs to be provided.

Therefore, we need to act on this right away.

The meeting was adjourned with a vote of gratitude from all of the attendees as there was nothing else to discuss.


**Co-Ordinator
Grievance Redressal
Committee**


**PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)
PRINCIPAL**


**PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)**

कार्यालय, प्राचार्य,

डी.पी. विप्रविधि महाविद्यालय, सीपतरोड, अशोकनगरबिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to AtalBihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

<https://dpvipralawcollege.ac.in>– Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 992613873

पत्र क्रमांक .Q/2019

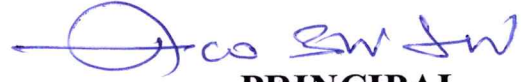
दिनांक 14/08/2019

Action Taken Report of Meeting held on Wednesday, 14/08/2019

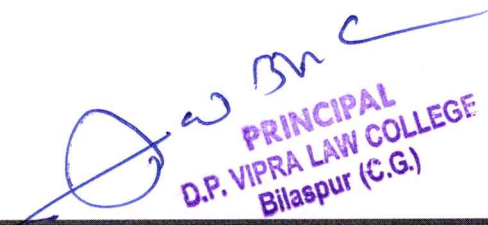
Sr. No.	Resolution in the meeting	Action Taken for Implementation & Outcomes
	The principal decided to act swiftly to improve the hygiene of the classes in the Bharat Kaushik building based on the coordinator's proposal.	



Co-Ordinator
Grievance Redressal
Committee



PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)



PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

D.P. VIPRA LAW COLLEGE BILASPUR (C.G.)

Approved From BCI,
Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya Bilaspur (C.G.)



Academic Year 2020-21

D.P. Vipra Law College Bilaspur
Ashok Nagar, Seepat Road, Sarkanda, Bilaspur (C.G.)



कार्यालय प्राचार्य

पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to AtalBihariVajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
<https://dpvipralawcollege.ac.in>—Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

पत्र क्रमांक.....Q/

दिनांक 09/07/2020

आदेश

शैक्षणिक सत्र 2020–21 हेतु कियत निवारण प्रकोष्ठ का गणन किया जाता है, जिसके अंतर्गत समन्वयक एवं सदस्य निम्न है, जो 13/07/2020 से प्रभावशील होगी।

क्रमांक	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
01	टी. आर. पटेल	समन्वयक / प्रभारी	
02	अनिता टंडन	सदस्य	
03	नम्रता परिच्छा	सदस्य	

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)



कार्यालय प्राचार्य

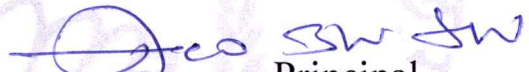
डी.पी. विप्रविधि महाविद्यालय, सीपतरोड, अशोकनगरबिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
<https://dpvipralawcollege.ac.in> – Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

Date: 04/08/2020

DECLARATION

Owing to the covid – 19 Pandemic, there was not a Grievance Redressal Committee meeting planned for the 2020 - 21 session.


Principal
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

D.P. VIPRA LAW COLLEGE BILASPUR (C.G.)

Approved From BCI,
Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya Bilaspur (C.G.)



Academic Year 2021-22

D.P. Vipra Law College Bilaspur
Ashok Nagar, Seepat Road, Sarkanda, Bilaspur (C.G.)



कार्यालय प्राचार्य

पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to AtalBihariVajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
<https://dpvipralawcollege.ac.in>–Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

पत्र क्रमांक.....Q/2021

दिनांक 05/07/2021

आदेश

शैक्षणिक सत्र 2021–22 हेतु कियत निवारण प्रकोष्ठ का गणन किया जाता है, जिसके अंतर्गत समन्वयक एवं सदस्य निम्न है, जो 08/07/2021 से प्रभावशील होगी।

क्रमांक	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
01	टी. आर. पटेल	समन्वयक / प्रभारी	
02	अनिता टंडन	सदस्य	
03	नम्रता परिच्छा	सदस्य	

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)



कार्यालय प्राचार्य

डी.पी. विप्रविधि महाविद्यालय, सीपतरोड, अशोकनगरबिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
<https://dpvipralawcollege.ac.in>—Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

पत्र क्रमांक ७/2021

Date:-17/08/2021

NOTICE

The Grievance Redressal Committee is scheduled to meet in the Staff Room on August 23, 2021, at 2:30 p.m.

The meeting's Agenda:

1. The Introductory class
2. Talk about a rang of topics related to comments made on staff room.

We kindly ask that you find time to attend the meeting.

**Co-Ordinator
Grievance Redressal
Committee**

**Principal
PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)**

**PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)**



कार्यालय प्राचार्य

डी.पी. विप्रविधि महाविद्यालय, सीपतरोड, अशोकनगरबिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
<https://dpvipralawcollege.ac.in>—Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

पत्र क्रमांक ..९/२०२१

Date:-23/08/2021

Attendance

S. No.	Name	Signature
1.	T.R.Patel	
2.	Anita Tandon	
3.	Namrata Parichha	

Principal
PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

Co-Ordinator
Grievance Redressal
Committe

Principal
PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)



कार्यालय प्राचार्य

डी.पी. विप्रविधि महाविद्यालय, सीपतरोड, अशोकनगरबिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
<https://dpvipralawcollege.ac.in>—Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

पत्र क्रमांक.... ९/२०२१

Date:-23/08/2021

Meeting Minutes

Agenda 1. Introductory Session.

Resolution:

Following their self- Introduction, the committee members summarized the roles and goals of the group.

Agenda2. Talk about a range of complaints made on college campus.

Resolution:

The committee talked about a number of student complaints that had previously been settled at their respective levels. Subsequently, T.R. Patel sir, brought up a concern to the committee attention. This concern was that English-medium topic books. Library. The conference was adjourned with a vote of thanks because there were no further matters to consider. Therefore, we must take action in this area and bring English-language publications to the table.

As there were no other issues to discuss, the meeting was concluded with the vote of thanks.


Co-Ordinator
Grievance Redressal
Committee


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)



कार्यालय प्राचार्य

डी.पी. विप्रविधि महाविद्यालय, सीपतरोड, अशोकनगरबिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
<https://dpvipralawcollege.ac.in>—Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

पत्र क्रमांक ...९/२०२१

Date:-23/08/2021

REPORT ON ACTIONS TAKEN AT THE MONDAY, AUGUST 23, 2021

Sr. No.	Resolution in the meeting	Action Taken for Implementation & Outcomes
	The principal unanimously decided to approve the use of English- language books in the library for the students.	


Co-Ordinator
Grievance Redressal
Committee


Principal
PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

D.P. VIPRA LAW COLLEGE BILASPUR (C.G.)

Approved From BCI,
Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya Bilaspur (C.G.)



Academic Year 2022-23

D.P. Vipra Law College Bilaspur
Ashok Nagar, Seepat Road, Sarkanda, Bilaspur (C.G.)



OFFICE OF THE PRINCIPAL

D.P. Vipra Law College Bilaspur

Approved from BCI, Affiliated to AtalBihariVajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
<https://dpvipralawcollege.ac.in> –Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

Letter No. Q./ 2022

Dated-06/07/2022

आदेश

शैक्षणिक सत्र 2022–23 हेतु कियत निवारण प्रकोष्ठ का गणन किया जाता है, जिसके अंतर्गत समन्वयक एवं सदस्य निम्न है, जो 08/07/2022 से प्रभावशील होगी।

क्रमांक	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
01	टी. आर. पटेल	समन्वयक / प्रभारी	
02	अनिता टंडन	सदस्य	
03	नम्रता परिच्छा	सदस्य	

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)



OFFICE OF THE PRINCIPAL

D.P. Vipra Law College Bilaspur

Approved from BCI, Affiliated to AtalBihariVajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
<https://dpvipralawcollege.ac.in> –Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

Letter No. Q./2022

Dated : 17/08/2022

NOTICE

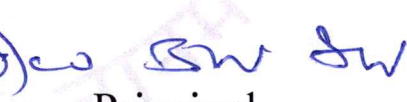
The Grievance Redressal Committee will meet in the Principal Office on August 22,2022, at 2:00 p.m.


The meeting agenda:

1. Provides an overview of the Committee's goals and duties.
2. Talk about any difficulties that are brought up

We kindly ask that you find time to attend the meeting.


Co-Ordinator
Grievance Redressal
Committe


Principal
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)



OFFICE OF THE PRINCIPAL

D.P. Vipra Law College Bilaspur

Approved from BCI, Affiliated to AtalBihariVajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
<https://dpvipralawcollege.ac.in> –Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

Letter No. 9./2022

Dated : 22/08/2022

ATTENDENCE

S. No.	Name	Signature
1.	T.R.Patel	
2.	Anita Tandon	
3.	Namrata Parichha	

Co-Ordinator
Grievance Redressal
Committee

Principal
PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)



OFFICE OF THE PRINCIPAL

D.P. Vipra Law College Bilaspur

Approved from BCI, Affiliated to AtalBihariVajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
<https://dpvipralawcollege.ac.in> –Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

Letter No. Q./2022

Dated : 22/08/2022

MINUTES OF MEETING

Agenda 1: Provides an overview of the committee's goals and responsibilities.


Resolution:

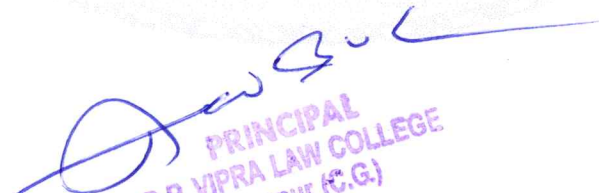
All Members of the committee gave an overview of their duties and responsibilities and gave their introductions.

Agenda 2: Talk about the points brought up.

Resolution:

The committee deliberated on issues pertaining to infrastructure, offices, libraries, and academic matters that were brought to their attention. The vote of thanks was held to end the meeting since no problems were brought forward to be handled.


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)



OFFICE OF THE PRINCIPAL

D.P. Vipra Law College Bilaspur

Approved from BCI, Affiliated to AtalBihariVajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
<https://dpvipralawcollege.ac.in> –Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

Letter No. 8./2022


Dated : 22/08/2022

REPORT ON ACTIONS TAKEN AT THE MONDAY, AUGUST 22,2022

Sr. No.	Resolution in the meeting	Action Taken for Implementation & Outcomes
NIL		


Co-Ordinator
Grievance Redressal
Committe


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

शैक्षणिक

सत्र -

2019 - 2020

कार्यालय, प्राचार्य,

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

<https://dpvipralawcollege.ac.in> – Email– dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

पत्र क्रमांक / 2019

दिनांक 07 / 09 / 2019

– :: आदेश :: –

शैक्षणिक सत्र 2019–2020 हेतु महिला उत्पीड़न समिति का गठन किया जाता है जिसके सदस्य निम्न हैं जो 09.09.2019 से प्रभावशील होगी।

1. प्रो. कु. सुषमा तिवारी
2. श्री जी. पी. कौशिक
3. डॉ. हीराचंद पटेल
4. डॉ. इन्दुबाला मिंज
5. प्रो. अनिता टण्डन
6. प्रो. नम्रता परिछा

संयोजक

सदस्य


सदस्य


सदस्य

सदस्य

सदस्य




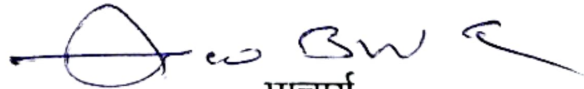








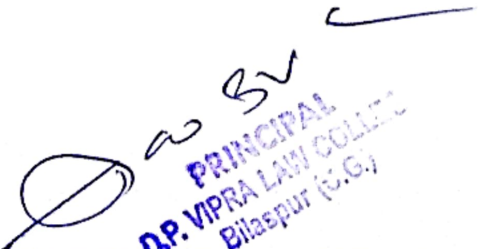




प्राचार्य

डी.पी.विप्र. विधि महाविद्यालय,

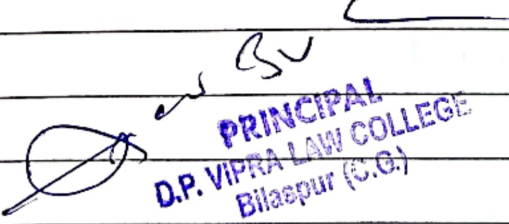
PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

कार्यकारिणी समिति

कु. सुषमा तिवारी
 श्री जी. पी. कौशिक
 डॉ. हीरा चंद पटेल
 डॉ. इंदु बाला मिश्र
 कु. अनिता टंडन
 कु. नम्रता परिच्छा

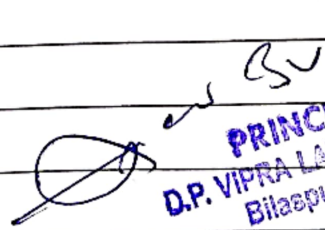
संयोजक
 सदस्य
 सदस्य
 सदस्य
 सदस्य
 सदस्य


 PRINCIPAL
 D.P. VIPRA LAW COLLEGE
 Bilaspur (C.G.)

कार्यकारी समिति

कु. सुषमा तिवारी
श्री जी. पी. कौशिक
डॉ. हीरा चंद पटेल
डॉ. इंदु बाला मिश्र
कु. अनिता टंडन
कु. नमरा परिच्छा

संयोजक
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

बैठक सूचना

दिनांक 20/09/2019

महिला उत्पीड़न समिति के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 20/09/2019 को महाविद्यालय के मीटिंग हल में समय 2:00 बजे दोपहर महिला उत्पीड़न समिति की एक आवश्यक बैठक करी गयी है, इस बैठक में सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है।

कृपया समय का ध्यान रखें।

इस बैठक में निम्न विषय पर चर्चा की जायेगी:

- (i) महाविद्यालय में छात्राओं पर रेगिंग होने की स्थिति में विचार
- (ii) महाविद्यालय छात्राओं को महिला अधिकारों की जानकारी हेतु कार्यशाला आयोजित किये जाने हेतु।

सदस्य

श्री जी० पी० कौशिक
डॉ० हीरानंद पुरेल
डॉ० बंशु बाला मिश्र
डु० आनता टंडन
डु० नमिता परिधा

डिप्टी प्रिन्सिपल
D.P. Vipra Law College
Bilaspur (C.G.)

प्रभारी

डु० सुषमा तिवारी
सहाय प्राध्यापिका
(विधि)
डि० पी० विप्र विधि
महाविद्यालय बिलासपुर

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

बैठक

दिनांक 25/09/2019

दिनांक 20/09/2019 की बैठक सूचना के अनुसार आज दिनांक को महाविद्यालय के मीटिंग कक्ष में महिला उत्पीड़न समिति की बैठक का आयोजन किया गया एवं इस बैठक में चर्चा एवं निम्न निर्णय लिये गये :-

- (i) महाविद्यालय में छात्रों पर रैगिंग बने की स्थिति में प्राचार्य को सूचित कर शान्त प्रभारी को सूचना दी जायेगी।
- (ii) छात्रों को रैगिंग के दुष्प्रभाव से अवगत कराया जायेगा।
- (iii) महिला अधिकारों की जातकारी हेतु कार्यशाला महाविद्यालय स्तर पर आयोजन किया जायेगा।

इस बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित

हए :-

कु. सुषमा तिवारी

Dr. ...

श्री जी. पी. कौशिक

मे. ...

डॉ. हीरानंद पटेल

...

डॉ. इन्दुबाला मिश्र

...

कु. अनिता टंडन

...

कु. नम्रता परिधा

...

Dec 30

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

बैठक सूचना

दिनांक - 11/12/2019

महिला उत्पन्न समिति के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वी.रू. एल.एल.बी. के डिप्लोमा सेमेस्टर की छात्रों द्वारा परीक्षा फॉर्म जमा करते समय कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः उपयुक्त विषय के संबंध में आप सभी सदस्यों को निराकरण हेतु एक बैठक का आयोजन रखा जाना है, अतः समिति के सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है।

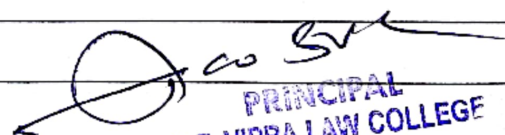
स्थान :- प्राचार्य कार्यालय

सदस्यता :-

प्रभारी

श्री जी. पी. कौशिक जे. एल.एल.बी. कु. सुबमा तिवारी
डॉ. धीराचंद पटेल J Patel सहायक प्राचार्य
डॉ. रंजुबाला मिश्रा R. Mishra (विधि)
कु. अमिता खन्ना A. Khanna डी. पी. वि. विधि

विशाल मल विद्यालय (द्वारा)


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

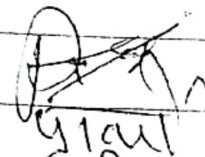
प्रति,


प्रचार्य महोदय
डी. पी. विप्र विधि महाविद्यालय
(बिलासपुर 2 (छ.ग.))
विषय, - परीक्षा कार्य बजल

महोदय,
निवेदन है कि मैं आपके महाविद्यालय
के बी.ए. एल.एल.बी की छात्रा हूँ मुझे परीक्षा
कार्य जमा करने में कठिनाई हो रही है।

धन्यवाद

दिनांक
3/12/2019


आपराजिता


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

बैठक

दिनांक - 13/10/2019


दिनांक 11/10/2019 की बैठक सूचना के आधार पर आज दिनांक 13/10/2019 को प्राचार्य डायनिंग में महिला उत्पीड़न समिति की बैठक की गई। इस बैठक में काफी बाद निम्नलिखित नियम लिए गए -

- वकील ए. एल. एल. वी. किराण्य सेमेटर की हजामों द्वारा की गई शिकायत के संबंध में प्राचार्य महोदय को अवगत कराया गया तथा उसका निराकरण समिति द्वारा किया गया

इस बैठक में निम्न सदस्यों की उपस्थिति रही -

श्री जी. पी. कौशिक ~~प्राचार्य~~ ^{प्रभारी}
डॉ. वीरचंद्र पटेल ^{Dr. Patel} कु. सुवमा तिवारी
डॉ. रंजुवाला मीन ^{Dr. Ranjwala} सहपाठ शहपाठ
कु. अनिता लंडन ^{Anita Lundon} (विद्यार्थी)

डी. पी. विज बिजे महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

२१
२१ दैनिक सत्र

2020 - 2021



कार्यालय, प्राचार्य,

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

<https://dpvipralawcollege.ac.in> – Email– dpvlawprincipal@yahoo.com PII. No. – 9926165945, 9926138734

पत्र क्रमांक/2020

दिनांक 20/08/2020

– :: आदेश :: –

शैक्षणिक सत्र 2020–2021 हेतु महिला उत्पीड़न समिति का गठन किया जाता है जिसके सदस्य निम्न हैं जो 21.08.2020 से प्रभावशील होगी।

1. प्रो. कु. सुषमा तिवारी
2. श्री जी. पी. कौशिक
3. डॉ. हीराचंद पटेल
4. डॉ. इन्दुबाला मिंज
5. प्रो. अनिता टण्डन

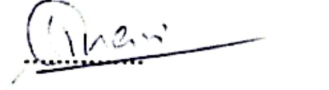

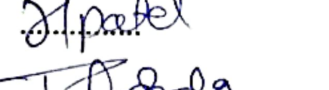
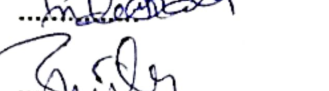
संयोजक

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

प्राचार्य

डी.पी.विप्र. विधि महाविद्यालय,

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)



कार्यालय, प्राचार्य,

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
<https://dpvipralawcollege.ac.in> – Email– dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

पत्र क्रमांक / 2020

दिनांक 21/08/2020

DECLARATION

This meeting of Anti-sexual harassment committee was not held during the session 2020-2021 due to COVID-19 pandemic.

Principal
PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

शैक्षणिक

सत्र 2021 - 2022



कार्यालय प्राचार्य

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
<https://dpvipralawcollege.ac.in> -Email - dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. - 9926165945, 9926138734

पत्र क्रमांक/2021

दिनांक 12/11/2021

— :: आदेश :: —

शैक्षणिक सत्र 2021-2022 हेतु महिला उत्पीड़न समिति का गठन किया जाता है जिसके सदस्य निम्न है जो 12.11.2021 से प्रभावशील होगी।

1. प्रो. कु. सुषमा तिवारी
2. श्री जी. पी. कौशिक
3. डॉ. हीराचंद पटेल
4. डॉ. इन्दुबाला मिंज
5. प्रो. अनिता टण्डन
6. प्रो. नम्रता परिछा

संयोजक

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

[Signatures of the members]

[Signature of the Principal]

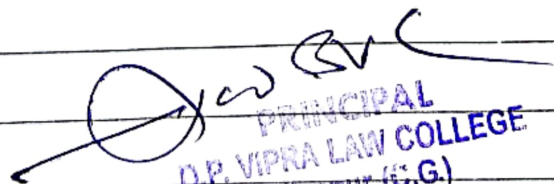
प्राचार्य

डी.पी.विप्र. विधि महाविद्यालय,
PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

[Signature of the Principal]
PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

कार्यकारिणी समिति

कु. सुषमा तिवारी	संयोजक
श्री जी. पी. कौशिक	सदस्य
डॉ. हीरानंद पटेल	सदस्य
डॉ. इन्दुबाला मिश्र	सदस्य
कु. अनिता टण्डन	सदस्य
कु. नम्रता परिन्दा	सदस्य


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

बैठक सूचना

Date :- 10/03/2022 .

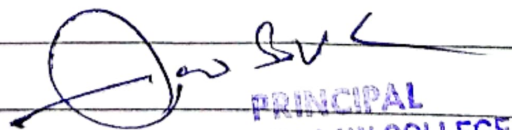
महिला उल्टीड़न के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 11/03/2022 को मीटिंग उस में समय दोपहर 2 बजे, B.A.L.B उर्वर क्षेत्र की छात्राओं द्वारा ऑनलाइन परीक्षा की उत्तरपुस्तिका जमा करने में असुविधा की शिकायत की गई है जिसके संबंध में बैठक रखी गई है।

बैठक में सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है।
हमारा समय का ध्यान रखें।

सदस्य
श्री. जी. पी. गौरिग — उच्चे. क्षेत्र
डॉ. वीराचंद पटेल
डॉ. इन्दुबाला मिश्र
कुं. अनिता टंडन
कुं. नम्रता परिचर

उच्चे. क्षेत्र
Dr. Patel
Indubala
Anita
Namrata

प्रभारी
कुं. सुपमा तिवारी
सहा. प्राध्यापक (विधि)
डी. पी. विप्र। विधि। महा.
बिलासपुर (छ.ग.)


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

प्रति,

प्राचार्य महोदय
डॉ. पी. विप्र विधि महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय: उत्तरपुस्तिका जमा करने में असुविधा।

महोदय,

समग्र निवेदन है कि मैं आपके महाविद्यालय के B.A.LLB. IIIrd sem की छात्रा हूँ। मुझे उत्तरपुस्तिका (मुख्य परीक्षा) को जमा करने में असुविधा हो रही है।

अतः महोदय से निवेदन है कि छात्राओं के लिए अलग से व्यवस्था की जाए।

धन्यवाद।

दिनांक

9/03/2022

Mangla
आवेदिका
मेनू

B.A.LLB 3rd sem

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

बैठक

दिनांक - 11/03/2022.

आ दिनांक 10/03/2022 की प्राप्त सूचना के अनुसार आज दिनांक को महिला उत्पीड़न समिति की बैठक रखी गई जिसमें छात्राओं द्वारा लिए गए शिकायत के निराकरण हेतु निम्न निर्णय लिए गए -

- (1) छात्राओं के लिए अलग पंक्ति लगाई जाएगी।
- (2) महिला स्नातक प्राध्यापकों के द्वारा छात्राओं की उत्तरप्रतिक्रियाओं को संचालित किया जाएगा।

प्रमुखगण

श्री. जी. पी. कौशिक
 डॉ. वीरचन्द्र पटेल
 डॉ. इन्दुबाता मिश्र
 कु. अनिता रॉडन
 कु. नमिता परिच्छा

प्रभारी

कु. सुषमा तिवारी
 स्नातक प्राध्यापक (विधि)
 डी. पी. विप्र विधि मठा
 विलासपुर (द.ग.)

PRINCIPAL
 D.P. VIJAYA LAW COLLEGE
 Bilaspur (C.G.)

29
21/10/23

2022 - 2023



OFFICE OF THE PRINCIPAL

D.P. Vipra Law College Bilaspur

Approved from BCI. Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
<https://dpvipralawcollege.ac.in> Email - dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. - 9926165945, 9926138734

Letter No. 298-A / 2022

Date: 02/09/2022

Dated : 02 / 09 / 2022

— :: आदेश :: —

शैक्षणिक सत्र 2022-2023 हेतु महिला उत्पीड़न समिति का गठन किया जाता है जिसके सदस्य निम्न हैं जो 03.09.2022 से प्रभावशील होगी।

1. प्रो. कु. सुषमा तिवारी
2. श्री जी. पी. कौशिक
3. डॉ. हीराचंद पटेल
4. डॉ. इन्दुबाला मिंज
5. प्रो. अनिता टण्डन
6. प्रो. नम्रता परिछा

संयोजक

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

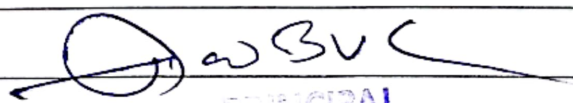
प्राचार्य
डी.पी.विप्र. विधि महाविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)

प्राचार्य
डी.पी.विप्र. विधि महाविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)

[Signature]
PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

कार्य कारिणी समिति

कु. सुषमा तिवारी	संयोजक
श्री. जी. पी. कौशिक	सदस्य
डॉ. हीराचंद पटेल	सदस्य
डॉ. इन्दुबाला मिश्र	सदस्य
कु. अमिता टंडन	सदस्य
कु. नम्रता परिच्छा	सदस्य


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

९०
बैठक सूचना

दिनांक - 14/09/2022

महिला उत्पीड़न समिति के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि B.Com. LL.B. 1st Semester के छात्रों द्वारा B.A. LL.B. 1st Semester के छात्र द्वारा छात्रों पर अशुद्ध अभद्र टिप्पणी करने की शिकायत की गई है जिसके निवारण हेतु दिनांक 16/09/2022 को बैठक आयोजित की गई है।

अतः सभी सदस्यों से आग्रह है कि उपर्युक्त समस्या के समाधान हेतु बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित हो।

स्थान :- मीटिंग कक्ष

सदस्य

श्री जी पी कौशिक

डॉ. हीरचंद पटेल

डॉ. इंदुबाला मिश्र

कु. अनिता टोंडन

नम्रता परिच्छा

प्रभारी

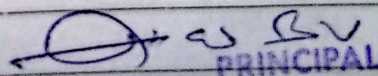
कु. सुवमा तिवारी

सहायक प्राध्यापक

(विधि)

डॉ. पी. विप्र. विधि महाविद्यालय

बिलासपुर (छ.ग.)



PRINCIPAL

D.P. VIPRA LAW COLLEGE

Bilaspur (C.G.)

बैठक

दिनांक - 16-09-22

दिनांक 16/09/22 को महिला उत्पीड़न समिति की बैठक मीटिंग कक्षा में रवीश्वर जिले में P. (000, L.L.B. नून रुक. की छात्राओं द्वारा की गई शिकायत से प्राचार्य महोदय को अवगत कराया गया एवं प्राचार्य महोदय द्वारा छात्र के माता-पिता को छात्र के उचित कृत्य से अवगत कराने तथा व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने हेतु कि सूचना भौजी गरु तथा समिति के सदस्यों को इस मामले को निराकरण हेतु निर्देश दिए गए।

निवेदन
श्री. श्री. पी. कौशिक - ले. प्रोफेसर
शु. केशचंद पटेल
डा. इंदुबाबा मिश्र
कु. अनिता 205 न
श्रीमति मसुदा परिष्का

प्रिन्सिपल
प्रभारी
कु. लुक्मा तिवारी
लहा. प्राध्या.
(विधि)
डा. पी. विपु
विधि महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

प्रति

प्रति

प्रति

प्राचार्य महोदय

प्राचार्य महोदय

डी० पी० विप्र विधि महाविद्यालय
बिलासपुर (छ० ग०)

विषय :- छात्र द्वारा अनुमति दियी
करने हेतु शिकायत करने हेतु वि

महोदय,

महोदय,

सजग निवेदन है कि मैं
आपके महाविद्यालय की B.Com LL.B
प्रथम सेमेस्टर की नियमित छात्र हूँ।
मुझे कई दिनों से इस महाविद्यालय
के B.A LL.B III के छात्र महेंद्र किरी
के द्वारा अनुमति दियी की जा रही है।

अतः महोदय से
निवेदन है कि आप इस संबंध में
कार्यवाही करने की कृपा करें।

धन्यवाद।
दिनांक :- 12/11/22

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

S. Pandey
श्रीया पाण्डे
(आवेदक)

B.Com LL.B Ist Sem.

शैक्षणिक

सत्र - 2023 - 2024



Office Of The Principal

D.P. Vipra Law College Bilaspur



Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
https://dpvipralawcollege.ac.in Email = dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. = 9926165945, 9926138734

Letter No. 170-B/2023

Date: 19/08/2023

Dated : 19/08/2023

— :: आदेश :: —

शैक्षणिक सत्र 2023-2024 हेतु महिला उत्पीड़न समिति का गठन किया जाता है जिसके सदस्य निम्न है जो 19.08.2023 से प्रभावशील होगी।

1. प्रो. कु. सुषमा तिवारी
2. श्री जी. पी. कौशिक
3. डॉ. हीराचंद पटेल
4. डॉ. इन्दुबाला मिंज
5. प्रो. अनिता टण्डन
6. प्रो. नम्रता परिछा

संयोजक

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

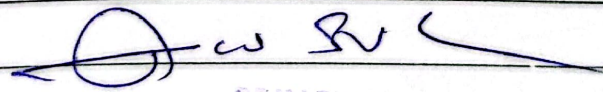
प्राचार्य
PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

कार्यकारिणी समिति

डु. सुषमा तिवारी
श्री. जी. पी. कौशिक
डॉ. हीरानंद पटेल
डॉ. इन्दु बाला मिश्र
अनिता टंडन
नमता परिच्छा

संयोजक
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य



PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

बैठक सूचना

दिनांक 9/10/2023

महिला उत्पीड़न के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 9/10/2023 को B.A. L.B पाठ्य सेमेस्टर की छात्रा स्टाफ को उसकी सहपाठिका द्वारा धमकी मिलने की शिकायत की गयी है। जिसकी बैठक IPUAC कक्षा में समय 2.00 बजे पोपहा को रखी गयी है।

उपस्थिति वस बैठक में सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है।

कृपया समय का ध्यान रखें।

Signature

प्रभारी

सदस्य गण

श्री जी.पी. कोरियर

डॉ. हीराचंद पटेल

डॉ. इंदुबाला मिश्र

अनिता टंडन

नम्रता परिच्छा

Dr. Patel

Dr. Patel

Dr. Patel

Dr. Patel

Dr. Patel

कु. सुषमा तिवारी

सहायक प्राध्यापक

(विधि)

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय

बिलासपुर (छ.ग.)

Signature

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

बैठक

दिनांक 12/10/23

दिनांक 9/10/2023 को महाविद्यालय की धारा द्वारा की गयी शिकायत पर आज दिनांक 12/10/23 को महिला उत्पीड़न समिति के सदस्यों द्वारा बैठक की गयी है जिसमें सदस्यों द्वारा शिकायत का अतिशीघ्र समाधान करने का निर्णय लिया गया एवं प्रचार्य महोदय को इससे अवगत कराया गया।

सदस्य
श्री जी० पी० कौशिक - चे. प्र. उ. उ.
डॉ. हीराचंद पटेल
डॉ. इंदुबाला मिश्र
अनिता टंडन
नामता परित्या

प्रभारी
डु. सुषमा तिवारी
सहायक प्राध्यापक
(विधि)

डी० पी० विप्र विधि महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

प्रति,

प्राचार्य महोदय,

डी.पी. विप्र. विधि महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

विषय: छात्रा द्वारा घमण्णी मिलने हेतु शिकायत।

महोदय,

निवेदन है, कि मैं आपके महाविद्यालय के छात्रा BA.LL.B III Sem की छात्रा हूँ। मुझे पिछले कुछ महीने से मेरी सहायिका, शब्दा लहरे द्वारा मेरी कुछ फोटो को प्रसारित करने हेतु घमण्णी दी जा रही है। जिस हेतु मैंने उससे बात करने की भी कोशिश की परंतु उसने मुझसे इस बारे में कोई भी बात करने से इन्कार कर दिया।

अतः महोदय से निवेदन है, कि आप इस विषय में अपना ध्यान आकर्षित करते हुए उस छात्रा से बात करें।

धन्यवाद।

09.10.2023

आवेदक:- सजल साहू

BA.LL.B III Sem.

BA.LL.B III Sem
PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

D.P. VIPRA LAW COLLEGE BILASPUR (C.G.)

Approved From BCI,
Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya Bilaspur (C.G.)

Appendix - III

D.P. Vipra Law College Bilaspur

Ashok Nagar, Seepat Road, Sarkanda, Bilaspur (C.G.)



कार्यालय प्राचार्य

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय, सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
<https://dpvipralawcollege.ac.in> – Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

पत्र क्रमांक Q/2021

दिनांक 08/09/2021

NOTICE

It is to inform all the students that during the academic session 2021-2022 our college has launched an online portal for submitting grievances related to anti-ragging, anti-sexual harassment, and women's development. This new system aims to provide a more accessible and efficient way for students, faculty, and staff to report any issues or concerns in these areas.

Grievance Submission Process


To submit a grievance, please visit the following link:

[https://dpvipralawcollege.ac.in/?page_id=2718]

Please note that this notice is being sent with a copy (CC) to the following:

1. All members of the Women's Grievance Cell
2. All students
3. All faculty members
4. The college administration for record-keeping purposes


Principal
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)


Principal
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

DP Vipra Law College

Bilaspur-Chattisgarh

[Home](#) [About us](#) [Courses](#) [Syllabus](#) [Student Corner](#) [Gallery](#) [Contact us](#) [Online Registration \(BU\)](#) [NAAC](#)
[Screen Reader](#) [Practical Exam 2023-24](#) [Scholarship](#)

GRIEVANCE REDRESSAL PORTAL

Grievance Redressal Portal

DP Vipra Law College is committed to providing a safe and inclusive environment for all students. We have established the following committees to address grievances related to anti-ragging, anti-sexual harassment, and women's development.

Anti-Ragging Committee

Ragging is defined as any act of physical or mental abuse (including bullying and exclusion) targeted at another student on the grounds of colour, race, religion, caste, ethnicity, gender, sexual orientation, appearance, nationality, regional origin, linguistic identity, or economic background. Ragging is a criminal offense and will not be tolerated at DP Vipra Law College. Students found engaging in ragging will face severe disciplinary action, including possible expulsion from the college.

The Anti-Ragging Committee is responsible for overseeing the implementation of anti-ragging measures and addressing any incidents of ragging on campus. The committee members are:

1. Prof. K. Sathya, Ex-Officio - Coordinator
2. Prof. Santosh Prasad - Member
3. Shri. Alok Sharma (Sports Officer) - Member
4. Prof. Dharmendra Sharma - Member

Women Grievance Committee (Anti-sexual harassment)

Sexual harassment includes any unwelcome physical, verbal, or non-verbal conduct of a sexual nature that has the purpose or effect of violating the dignity of a person or creating an intimidating, hostile, degrading, humiliating, or offensive environment. DP Vipra Law College has a zero-tolerance policy towards sexual harassment, and all complaints will be investigated and addressed promptly.

The Women Grievance Committee is responsible for addressing complaints of sexual harassment and ensuring a safe and respectful environment for all female students, faculty, and staff. The committee members are:

LATEST POST

Merit list (2024-25) UG First Semester July 06, 2024

SAUGR SECURED Merit list 2024-25 July 03, 2024

SCOM U.S SECURED Merit list 2024-25 July 03, 2024

SECURED U.S (Merit list - 2024-25) July 4, 2024

SAUGR U.S (Merit list (2024-25) July 4, 2024

Merit list 2024-25 UG First Semester September 26, 2023

One Day Workshop August 26, 2023

RECENT NEWS

Download the referred form- Question Paper and Sent to Email id

LATEST POST

Merit list (2024-25) UG First Semester July 06, 2024

PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)



OFFICE OF THE PRINCIPAL

D.P. Vipra Law College Bilaspur

Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
<https://dpvipralawcollege.ac.in> –Email – dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945, 9926138734

Letter No. Q/2022

Dated: 09/09/2022

NOTICE

It is to inform all the students that for the academic session 2022-2023 all the grievances related to anti-ragging, anti-sexual harassment, and women's development can be submitted online through the portal also.

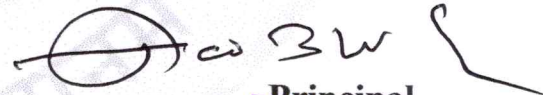
Grievance Submission Process


To submit a grievance, please visit the following link:

[https://dpvipralawcollege.ac.in/?page_id=2718]

Please note that this notice is being sent with a copy (CC) to the following:

1. All members of the Women's Grievance Cell
2. All students
3. All faculty members
4. The college administration for record-keeping purposes


Principal
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)


Principal
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

DP Vipra Law College

Bilaspur, Chhattisgarh



GRIEVANCE REDRESSAL PORTAL

Home > Grievance Redressal Portal

DP Vipra Law College is committed to providing a safe and inclusive environment for all students. We have established the following committees to address grievances related to anti-ragging, anti-sexual harassment, and women's development:

Anti-Ragging Committee

Ragging is defined as any act of physical or mental abuse (including bullying and exclusion) targeted at another student on the grounds of colour, race, religion, caste, ethnicity, gender, sexual orientation, appearance, nationality, regional origins, linguistic identity, or economic background. Ragging is a criminal offense and will not be tolerated at DP Vipra Law College. Students found engaging in ragging will face severe disciplinary action, including possible expulsion from the college.

The Anti-Ragging Committee is responsible for overseeing the implementation of anti-ragging measures and addressing any incidents of ragging on campus. The committee members are:

1. Prof. Ka. Sushma Tiwari - Coordinator
2. Prof. Santosh Thakur - Member
3. Shri. Anil Sharma (Sports Officer) - Member
4. Prof. Dharmendra Sharma - Member

Women Grievance Committee (Anti-sexual harassment)

Sexual harassment includes any unwelcome physical, verbal, or non-verbal conduct of a sexual nature that has the purpose or effect of violating the dignity of a person or creating an intimidating, hostile, degrading, humiliating, or offensive environment. DP Vipra Law College has a zero-tolerance policy towards sexual harassment, and all complaints will be investigated and addressed promptly.

The Women Grievance Committee is responsible for addressing complaints of sexual harassment and ensuring a safe and respectful environment for all female students, faculty, and staff. The committee members are:

1. Prof. Ka. Sushma Tiwari - Coordinator
2. Shri. G.P. Koushik - Member
3. Dr. Harendra Patel - Member
4. Dr. Indulal Singh - Member
5. Prof. Anil Kumar - Member
6. Prof. Rameshwar Panchbhai - Member

To file a grievance related to any of these areas, students can submit a written complaint to the respective committee or use the online grievance redressal portal available on the college website. All complaints will be handled confidentially and in accordance with the UGC's guidelines on anti-ragging and anti-sexual harassment.

LATEST POST

Merit List (2024-25) LLB First Semester July 16, 2024

BALLB SECOND MERIT LIST 2024 July 10, 2024

BCOM LLB SECND MERIT LIST 25 July 10, 2024

B.COM LLB (Merit List- 2024- July 4, 2024

BA LLB- Merit List (2024-25) J 2024

Merit List 2023-24 LLB First Semester September 26, 2023

One Day Workshop August 2 2023

RECENT NEWS

Download the Internal exam- Question Paper and Set to rd

LATEST POST

Merit List (2024-25) LLB First Semester July 16, 2024

BALLB SECOND MERIT LIST 2024 July 10, 2024

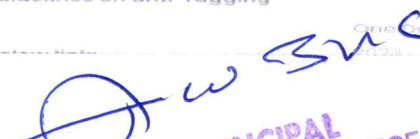
BCOM LLB SECND MERIT LIST 25 July 10, 2024

B.COM LLB (Merit List- 2024- July 4, 2024

BA LLB- Merit List (2024-25) J 2024

Merit List 2023-24 LLB First Semester September 26, 2023

One Day Workshop August 2 2023


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)

regional origin, linguistic identity, or economic background. Ragging is a criminal offense and will not be tolerated at DP Vipra Law College. Students found engaging in ragging will face severe disciplinary action, including possible expulsion from the college.

The Anti-Ragging Committee is responsible for overseeing the implementation of anti-ragging measures and addressing any incidents of ragging on campus. The committee members are:

1. Prof. K. Sushma Tiwari - Coordinator
2. Prof. Animesh Thakur - Member
3. Shri Alex Sharma (Sports Officer) - Member
4. Prof. Dharmendra Chandra - Member

Women Grievance Committee (Anti-sexual harassment)

Sexual harassment includes any unwelcome physical, verbal, or non-verbal conduct of a sexual nature that has the purpose or effect of violating the dignity of a person or creating an intimidating, hostile, degrading, humiliating, or offensive environment. DP Vipra Law College has a zero-tolerance policy towards sexual harassment, and all complaints will be investigated and addressed promptly.

The Women Grievance Committee is responsible for addressing complaints of sexual harassment and ensuring a safe and respectful environment for all female students, faculty, and staff. The committee members are:

1. Prof. K. Sushma Tiwari - Coordinator
2. Shri G.P. Kaushik - Member
3. Dr. Bhacharya Patel - Member
4. Dr. Anand Mishra - Member
5. Prof. Anil Pandey - Member
6. Prof. Namrata Pandey - Member

To file a grievance related to any of these areas, students can submit a written complaint to the respective committee or use the online grievance redressal portal available on the college website. All complaints will be handled confidentially and in accordance with the UGC's guidelines on anti-ragging and anti-sexual harassment.

Kindly register your complaint by clicking on the below link:

<https://www.dpvipra.ac.in/grievance-redressal-portal>

B.COM LLB (Merit List- 2024-
July 4, 2024

BA LLB- Merit List (2024-25) 2
2024

Merit List 2023-24 LLM First
Semester September 26, 2023

One Day Workshop August 2
2023

RECENT NEWS

Download the Internal exam
Question Paper and Sent to
it.

LATEST POST

Merit List (2024-25) LLB First
Semester July 16, 2024

BALLB SECOND MERIT LIST 202
July 10, 2024

B.COM LLB SECOND MERIT LIST 2
25 July 10, 2024

B.COM LLB (Merit List- 2024-
July 4, 2024

BA LLB- Merit List (2024-25) 2
2024

Merit List 2023-24 LLM First
Semester September 26, 2023

One Day Workshop August 2
2023

RECENT NEWS

Download the Internal exam
Question Paper and Sent to
it.

Sorry. No data so far.

FIND US ON GOOGLE MAP



LOGO



CONTACT US

DWARIKA PRASAD VIPRA
LAW COLLEGE Ashok
Nagar, Seepat,
Road, BILASPUR

MOB: 99261-
38734, 992616594
5

Say Hi:
dpilawcollege@gmail.co
m

LATEST NEWS

Merit List (2024-25) LLB
First Semester

BALLB SECOND MERIT LIST
2024-25

B.COM LLB SECOND MERIT
LIST 2024-25

B.COM LLB (Merit List-
2024-25)

BA LLB- Merit List (2024-
25)

Sorry. No data so far.


PRINCIPAL
D.P. VIPRA LAW COLLEGE
Bilaspur (C.G.)